राष्ट्रीय संस्करण

लंदन के मंदिर में बोले जॉनसन, मोदी के साथ बनाएंगे नया भारत
>> 13

वर्ष 3 अंक 181

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 9 दिसंबर 2019

पृष्ठ 16

सरोकार

छह लाख बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर फोकस

रांची : झारखंड में 2002 से कार्यरत चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) की पहुंच आज राज्य के छह लाख बच्चों तक है। लैंगिक आधारित हिंसा और भेदभाव, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के खिलाफ पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता सिनी की कार्ययोजना में शामिल है। (पेज-11)

जागरण विशेष

युवा वकीलों ने शुरू किया पहला 'लीगल क्लीनिक'

इंदौर : मप्र के इंदौर शहर में अनोखा 'लीगल क्लीनिक' है, जहां लोगों को कानूनी मदद मुफ्त मिलती है। युवा वकील और सीविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे 40 से ज्यादा लोग इसे चलाते हैं। 'क्लीनिक' से अब तक तमाम लोगों को मदद मिल चुकी है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे

बेंगलुरु : कर्नाटक में चार माह पुरानी बीएस येदियुरप्पा सरकार का भविष्य सोमवार को तय हो जाएगा। राज्य में जिन 15 सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं उनकी मतगणना सोमवार को होगी। 11 केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम सामने आ जाएगा। चुनाव अधिकारी ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

अस्पताल से 28 दिन बाद घर आईं लता मंगेशकर

मुंबई : स्वर कोकिला लता मंगेशकर 28 दिन बाद अस्पताल से लौट आई हैं। भारत रत्न लता को 11 नवंबर को सांस में दिक्कत की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में उन्हें न्यूमोनिया होने की बात सामने आई थी। रविवार को घर वापसी के बाद उन्होंने प्रार्थनाओं एवं शुभकामनाओं के लिए प्रशंसकों का धन्यवाद किया।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी बनेगी एयरटेल

नई दिल्ली : भारती एयरटेल की प्रमोटर कंपनी भारती टेलीकॉम ने सरकार से 4,900 करोड़ रुपये के एफडीआइ हासिल करने की इजाजत मांगी है। कंपनी सिंगापुर स्थित सिंगटेल व कुछ अन्य निवेशकों से यह रकम जुटाना चाहती है। अगर सरकार यह इजाजत देती है, तो कंपनी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 50 फीसद के पार चली जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

हांगकांग में आजादी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाखों लोग

हांगकांग : हांगकांग में आजादी की मांग को लेकर रविवार को लाखों लोग सड़क पर निकले। जिस सड़क पर देखो-उसी पर काले कपड़े पहने लोकतंत्र समर्थकों का रेला दिखाई दे रहा था। बच्चे-बूढ़े और जवान, सभी के मुख से- आजादी के लिए हांगकांग के साथ खड़े हों, का नारा निकल रहा था। आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर आयोजित जनसभा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया।

दर्दनाक हादसा ▸ 1997 में उपहार सिनेमा के बाद राजधानी का दूसरा सबसे बड़ा अग्निकांड

दिल्ली में आग ने फिर ली 43 की जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में उपहार सिनेमा जैसे एक और अग्निकांड में 43 लोगों की जान चली गई। आग राजधानी के फिल्मिस्तान इलाके में अनाज मंडी में लगी। ज्यादातर की मौत धुंए के कारण दम घुटने से हुई। मृतकों में ज्यादातर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के बिजनौर व मुरादाबाद के हैं। अब तक 22 की पहचान हुई, इनमें 18 बिहार और 4 उप्र के हैं। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि उसे काबू करने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां और 150 कर्मी लगे। बता दें उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे। इसी साल फरवरी में दिल्ली के करोल बाग में एक होटल में आग से 17 की मौत हो गई थी। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक रिहान व मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। रिहान के एक भाई को भी हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार ने भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

मुआवजे की घोषणा : घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। बिहार सरकार ने अग्निकांड में मारे गए बिहार के श्रमिकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की। दिल्ली भाजपा भी पांच पांच लाख देगी।

- फिल्मिस्तान इलाके में अनाज मंडी स्थित अवैध फैक्ट्री में शार्ट सर्किट से लगी आग
- ज्यादातर मौतें दम घुटने से, मरने वालों में अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के
- एलएनजेपी, लेडी हार्डिंग व आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं घायल
- पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को किया गिरफ्तार, लापरवाही का मुकदमा दर्ज

30 दमकल गाड़ियों ने पांच घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पाया

10 लाख रुपये हर मृतक के स्वजनों को देगी दिल्ली सरकार

5 लाख रुपये प्रत्येक मृतक के स्वजनों को भाजपा भी देगी

- घायलों का इलाज भी दिल्ली सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

4 हजार अवैध फैक्ट्रियां इस इलाके में हो रही हैं संचालित

घटनाक्रम

- **4:45** बजे सुबह भवन की तीसरी मंजिल पर शॉट सर्किट हुआ
- **5:00** बजे चार मंजिला इमारत में आग लगी
- **5:15** बजे पड़ोसी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे
- **5:22** बजे लोगों ने दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी
- **5:35** बजे दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
- **5:55** बजे कैट एंबुलेंस की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
- **6:00** बजे घायलों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू हुआ
- **9:30** बजे तक सभी घायलों व मृतकों को अस्पताल पहुंचाया गया

घायलों के लिए 72 घंटे हैं महत्वपूर्ण : एनडीआरएफ, पुलिस व दमकलकर्मियों ने आग में फंसे लोगों को निकालकर एलएनजेपी, लेडी हार्डिंग व आरएमएल अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने 43 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 20 की हालत गंभीर है। इनमें से 15 को आग में झुलसने व सांस लेने में परेशानी के कारण भर्ती किया गया है। पीड़ितों के लिए 72 घंटे महत्वपूर्ण हैं। उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है।

अवैध थी फैक्ट्री : चार मंजिला फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी इसलिए इसे अवैध बताया जा रहा है। छह सौ गज के प्लॉट पर वहां तीन भाइयों शान-ए-इलाही, रिहान और इमरान की 200-200 गज में अपनी अपनी फैक्ट्री है। उसमें लेडीज बैग, स्कूल बैग व खिलौना निर्माण सहित पैकजिंग का काम होता था। वहां रह रहे कामगारों के मुताबिक रविवार सुबह करीब 5 बजे रिहान की फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर शार्ट सर्किट से आग लग गई। प्लास्टिक व ज्वलनशील सामान होने के कारण आग ने भयावह रूप ले लिया। फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए कोई साधन नहीं था और ऊपर जाने का रास्ता बंद था।

नई दिल्ली में रविवार को फैक्ट्री में लगी आग में अपने परिजन को खोने के बाद फोन पर जानकारी देता युवक। रायटर

दरवाजा तोड़ कर लोगों को निकाला : राहतकर्मी पड़ोस के मकान से छत पर उतरे फिर जीने का दरवाजा तोड़कर नीचे पहुंचे और लोगों को निकाला। रास्ता संकरा होने के कारण दमकलकर्मियों को बचाव में दिक्कत आई। कर्मियों ने 400 मीटर से पानी का पाइप ले जाकर बचाव कार्य शुरू किया।

आप सरकार को ठहराया जिम्मेदार : भाजपा नेताओं ने अग्निकांड के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, संकरी गलियों में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने भी आप सरकार व भाजपा शासित नगर निगम को जिम्मेदार बताया है।

आधी दिल्ली बैठी है आग के मुहाने पर >> पेज 2
लापरवाही की लपटें (विशेष) >> पेज 5
लापरवाही की आग (संपादकीय) >> पेज 8

> दिल्ली में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी इलाके का अग्निकांड बहुत ही भयावह है। इसमें अपने परिजन को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

> लोगों की मौत से सदमे में हूं। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं घायलों की सुरक्षा और उनके शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं। घायलों को सर्वोत्तम उपचार सहित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।
>
> **-अनिल बैजल, उप राज्यपाल, दिल्ली**

> दिल्ली में हुआ अग्निकांड बेहद दर्दनाक घटना है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें।
>
> **-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार**

22 साल, 10 घटनाएं और 167 मौतें

संजीव कुमार मिश्र, नई दिल्ली

अनाज मंडी में अग्निकांड की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फैक्ट्री अवैध थी। यदि फैक्ट्री अवैध थी तो नगर निगम या अन्य जिम्मेदार एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आग से बचाव के इंतजाम भी नगण्य थे। इस तरह की घटनाओं में हर बार रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियां चलने, होटल, रेस्त्रां, सिनेमाघर आदि में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के अभाव की बातें सामने आती हैं। जब घटना हो जाती है तो प्रशासन फायर ऑडिट की बात कहता है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और फिर शुरू होता है जांच के नाम पर लीपापोती का खेल। इसीलिए, दिल्ली में आग लगने की बड़ी घटनाओं से अब तक सबक नहीं लिया गया।

दिल्ली के भयावह अग्निकांड

तारीख	जगह	मौतें
08 दिसंबर 2019	अनाज मंडी	43
13 जुलाई-2019	झिलमिल में रबड़ फैक्ट्री	03
26 मार्च 2019	शाहीन बाग	02
12 फरवरी 2019	करोलबाग होटल	17
19 नवंबर 2018	करोलबाग की फैक्ट्री	04
13 अप्रैल 2018	कोहाट एन्क्लेव	04
20 जनवरी 2018	बवाना औद्योगिक क्षेत्र	17
07 जुलाई 2017	नंदनगरी में किन्नर सम्मेलन	14
07 जुलाई 2017	दिलशाद कॉलोनी	04
13 जून 1997	उपहार सिनेमा	59

पीएम ने महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी पुलिसिंग पर दिया जोर

- कहा, समाज में विश्वास जगाने के लिए पुलिस की छवि सुधारने के सतत प्रयास हों
- गृहमंत्री ने आइपीसी और सीआरपीसी में बदलाव की प्रतिबद्धता जताई

पुणे में रविवार को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 54 वें सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह (दाएं) भी उपस्थित रहे। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दिया है, ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकें। हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर देश में पैदा हुए आक्रोश के बीच पीएम का यह पहला बयान सामने आया है।

पुणे में पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षकों (आइजीपी) के 54वें सम्मेलन में मोदी ने कहा, अफसरों को हर समय पुलिस की छवि निखारने के प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि महिलाओं और बच्चों समेत समाज के सभी वर्गों के बीच भरोसा बढ़ सके। प्रधानमंत्री दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक, पीएम मोदी का मानना था कि सक्रिय पुलिसिंग सुनिश्चित करने में तकनीक बहुत मददगार हो सकती है, जिसके जरिए आम लोगों का उसे फीडबैक मिलेगा।

तीन दिनी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने माना कि पुलिस अफसरों के सामने रोज-रोज के कार्यों में तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब कभी भी उनके सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो तो वो उस आदर्श और भावना को याद करें, जिसके तहत उन्होंने पुलिस सेवा में आने और देशहित में काम करने का फैसला किया था। हमेशा समाज के कमजोर व गरीब वर्ग के कल्याण की भावना मन में रख कर काम करें। इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और अपराधी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को देश के और अनुकूल बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने के दृढ़ निश्चय पर बल दिया था। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं।

पुलिस स्मारक बनाने की योजना : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने पुलिस रिसर्च केंद्र में पुलिस स्मारक पर माल्यार्पण के बाद कहा, प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में स्मारक बनेगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कराने को सरकार ने कसी कमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज पेश करेंगे बिल, विपक्ष विरोध पर आमादा, लाएगा संशोधन प्रस्ताव

लोकसभा में सोमवार को पेश होने जा रहे नागरिकता संशोधन विधेयक पर राजनीतिक खेमेबंदी की तस्वीर साफ हो गई है। घटक और बीजद जैसे मित्र दलों के समर्थन के बूते राजग सरकार ने बिल को पारित कराने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस की अगुआई में अधिकतर विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन बिल के वर्तमान स्वरूप को देश के लिए खतरनाक बताते हुई इसके विरोध की ताल ठोक दी है। पार्टी रणनीतिकारों के साथ हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरी ताकत से संसद में इस बिल का विरोध करने पर मुहर लगा दी। दूसरी तरफ लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में गृह मंत्री अमित शाह के विधेयक पेश करने की तैयारी की जानकारी देकर सरकार ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सरकार और विपक्ष के रुख को देखते हुए लोकसभा में सोमवार को सियासी संग्राम तय माना जा रहा है।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर किस कदर आर-पार होनेवाली है, इसकी झलक रविवार को दोनों पक्षों की ओर से आए बयानों में दिखी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल के प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया, तो यह गांधी के विचारों पर जिन्ना के विचारों की जीत होगी। वहीं भाजपा नेता राम माधव ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों को नागरिकता देने संबंधी के प्रस्ताव को जायज ठहराया।

उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिमों को नागरिकता का प्रावधान

नागरिकता संशोधन बिल में सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार होकर आने वाले गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है।

नागरिकता विधेयक पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को 10 जनपथ पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों से चर्चा की। इसमें तय हुआ कि पार्टी संसद में साफ करेगी कि वह बिल का नहीं बल्कि इसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव के प्रावधान के खिलाफ है। कांग्रेस की ओर से विधेयक के विवादित प्रावधान में संशोधन भी पेश किए जाएंगे। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा कि उनकी पार्टी की ओर से बिल के धार्मिक भेदभाव वाले प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन दिया जाएगा और पार्टी विधेयक का विरोध करेगी।

भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया कि नौ दिसंबर से तीन दिनों तक सदन में मौजूद रहें। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को विधेयक के दौरान दोनों सदनों में उपस्थिति सुनिश्चित रखने को कहा है।

रास में रास्ता रोकने की तैयारी : लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और उसके समर्थक दलों के पास करीब दो तिहाई बहुमत को देखते हुए विधेयक का पारित होना लगभग तय है। इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी दल राज्यसभा में संख्या बल जुटाकर बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोशिशों में जुटे हैं।

विपक्ष की ताकत : कांग्रेस और वामदलों के अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद, द्रमुक, राकांपा के साथ ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियां भी विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रही हैं।

सरकार के साथ : बीजू जनता दल (बीजद), अन्नाद्रमुक, वाइएसआर कांग्रेस और टीआरएस अब तक जिस तरह से मोदी सरकार के साथ रहे हैं, उसमें राज्यसभा में भी विपक्ष के लिए विधेयक को रोकना कठिन काम है।

न्याय आनन-फानन नहीं हो सकता पर देरी भी ठीक नहीं : वेंकैया

नई दिल्ली, प्रेट्र : न्याय आनन-फानन नहीं हो सकता है पर इसमें लगातार देरी भी नहीं होनी चाहिए। देरी होने से लोग बेसब्र होते हैं और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को यह बात कही। नायडू का यह बयान ऐसे समय में आया है, जबकि देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे ने एक दिन पहले कहा था कि न्याय आनन-फानन में नहीं किया जा सकता है। यदि बदले की भावना से न्याय हुआ तो वह अपना मूल चरित्र खो देगा।

उपराष्ट्रपति नायडू ने न्यायिक प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि अदालत की कार्यवाही स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें। नायडू ने कहा कि कुछ मामलों में निश्चित समयसीमा के भीतर फैसला दिए जाने की जरूरत है। चुनाव याचिकाएं और सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में फैसले की समयसीमा तय होनी चाहिए।

ज्ञात हो, हैदराबाद में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के आरोपितों के पुलिस एनकाउंटर के बाद से न्याय व्यवस्था पर व्यापक विमर्श हो रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपित पुलिस टीम पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मारे गए। एक पक्ष पुलिस के कदम को सही मान रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पुलिसिया न्याय की परंपरा समाज के लिए घातक है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल से रुकेंगी दुष्कर्म की घटनाएं पेज>>3

असली हीरो

दिल्ली अग्निकांड में असली हीरो राजेश शुक्ला ने पेश की साहस की मिसाल, लोगों को बचाने में खुद भी घायल हुए अग्निशमन विभाग के एडीओ, स्वास्थ्य मंत्री जैन से कहा-सर, थोड़ा पहले पहुंचते तो बच जाती और लोगों की जान

मुश्किल हालात में रांची के जांबाज ने बचाईं 12 जिंदगियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की जान चली गई, लेकिन अग्निशमन विभाग के बहादुर असिस्टेंट डिवीजन ऑफिसर (एडीओ) राजेश शुक्ला और उनकी टीम न होती तो हादसा और भयावह हो सकता था। रांची के राजेश शुक्ला और उनकी टीम ने जान की परवाह किए बिना 12 लोगों को बचाया। इस काम में राजेश घायल हो गए और उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उन्हें ऑक्सीजन दी गई। जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मिलने पहुंचे तो शुक्ला ने व्यथित मन से उन्हें हादसे की जानकारी दी और कहा-सर थोड़ा पहले मौके पर पहुंच जाते तो और लोगों भी जान बच जाती।

दैनिक जागरण से बातचीत में पुरानी दिल्ली इलाके के एडीओ राजेश शुक्ला ने बताया कि आग फैक्ट्री में तीन मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उन्हें वहां मौजूद लोगों से जानकारी मिली कि कुछ लोग अंदर फंसे हैं। इसके बाद वह ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर ही दो-तीन अन्य दमकल कर्मियों के साथ दरवाजा तोड़कर फैक्ट्री के अंदर घुस गए।

> राजेश शुक्ला सही मायने में नायक हैं। वह आग से घिरी इमारत में घुसने वाले पहले शख्स थे। वहां उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। इस बहादुर को मेरा सलाम।
>
> **-सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार**

आग में फंसे बारह लोगों का जीवन बचाने वाले अग्निशमन विभाग के असिस्टेंट डिवीजन ऑफिसर राजेश शुक्ला (दाएं) से बातचीत करते दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। ट्विटर

कमरे में गूंज रही थी आवाज : बचाव कार्य के दौरान फैक्ट्री के अंदर दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे तो दो लोगों को छोड़कर सब बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें इतनी तेज चल रहीं थीं कि पूरे कमरे में आवाजें गूंज रही थीं। जो लोग होश में थे, उन्हें साथ ले आए। जो बेहोश थे उन्हें भी बाहर लाने का काम शुरू किया गया। तीन-चार दमकलकर्मियों ने मिलकर पहली बार में 12 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें दो बच्चे भी थे।

एक ही हॉल में 30 से ज्यादा लोग पड़े थे बेहोश : राजेश ने बताया कि पहली बार में कमरे से लोगों को बाहर निकालने में काफी धुआं सांस के जरिये शरीर में चला गया था। इसलिए दूसरी बार सुरक्षा उपकरण के साथ अंदर प्रवेश किया, जहां एक ही हॉल में 30 से ज्यादा लोग पड़े थे। ज्यादातर की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। सभी को बाहर भेजने का काम शुरू किया गया। तब तक मौके पर पर्याप्त एंबुलेंस नहीं पहुंचीं थीं। ऐसे में कई पीड़ितों को खुद की गाड़ी से अस्पताल भेजना पड़ा।

आग बुझाना और लोगों को निकालना दोहरी चुनौती : राजेश ने कहा कि आग बुझाना और लोगों को बाहर निकालना, यह दोहरी चुनौती थी। गली इतनी संकरी है कि एक साथ फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकती थीं। इस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी थीं, उस वक्त पीड़ितों को उठाकर गली के बाहर एंबुलेंस तक लाना पड़ रहा था। बचाव कार्य के दौरान बेहोश व्यक्ति को बाहर निकालते वक्त वह गिर पड़े। इस वजह से उनके घुटने में चोट भी लग गई।

सोशल मीडिया पर दिलेरी के चर्चे : रांची के नामकुम तेतरी टोला के मूल निवासी राजेश शुक्ला का नाम हर किसी की जुबां पर है। सोशल मीडिया पर राजेश की दिलेरी के चर्चे हो रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर राजेश शुक्ला को असली हीरो बताया। राजेश शुक्ला 2004 से दिल्ली अग्निशमन में सेवारत हैं। इसके पूर्व भी गुजरात के भूकंप और दिल्ली में कई हादसों में कई लोगों की जान बचा चुके हैं।

अमेठी की राजनीतिक रस्साकशी में सेल के डूब गए 366 करोड़

नई दिल्ली, आइएएनएस : राजनीतिक हस्तक्षेप देश की केंद्रीय सरकारी कंपनियों को किस तरह बेमतलब के निवेश निर्णय लेने को मजबूर करता है, इसका बेहतरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के अमेठी में सामने आया है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल (2009-2014) के दौरान देश की प्रतिष्ठित पीएसयू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अमेठी में मालविका स्टील के अधिग्रहण को राजी किया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सेल का यह निवेश अधिग्रहण के बाद से ही निरर्थक साबित हुआ, क्योंकि वित्तीय संकट से जूझ रही मालविका स्टील को पुनर्जीवित करने की कोशिशें बेकार गईं।

मालविका स्टील के पुनरुद्धार की इस योजना को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय जनता को लुभाने के राजनीतिक हथकंडे के तौर पर देखा गया। अधिग्रहण को इस तौर पर पेश किया गया जैसे कि इससे वहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और शहर में औद्योगिक क्रांति का पदार्पण हो जाएगा।

सेल हमेशा से कहती रही कि मालविका स्टील का अधिग्रहण उसके लिए व्यावहारिक नहीं है। अधिग्रहण के वक्त भी उस वह बंद पड़ी कंपनी कबाड़ का रूप ले चुकी थी। कैग ने कहा है कि सेल ने 44.35 करोड़ रुपये में इस प्लांट और मशीनरी का अधिग्रहण किया, लेकिन पूरी मशीनरी कबाड़ हो गई। इस वक्त तक सेल की इस पर कुल लागत 366 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इस संपत्ति के उपयोग को लेकर वर्ष 2015 में गठित एक समिति ने कहा कि ज्यादातर आइटम लगभग 17 वर्षों से बिना उपयोग के पड़े हुए हैं और किसी काम के नहीं हैं। इन्हें एक संयंत्र का रूप देना और चालू हालत में लाना संभव नहीं है। इस पूरे मामले में दिलचस्प यह है कि मालविका स्टील की भू-संपत्ति भी अब तक सेल के नाम नहीं की गई है।

1061 आरोपितों को गिरफ्तार किया है गाजियाबाद जिले में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से चलाए गए ऑपरेशन सुरक्षा में 72 घंटे के अभियान में। यह अभियान एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में पूरे जिले में चलाया गया था।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 दिसंबर 2019

आधी दिल्ली बैठी है आग के मुहाने पर

अनधिकृत कॉलोनियां के साथ ही कई रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहीं औद्योगिक इकाइयां

संतोष शर्मा, नई दिल्ली

फिल्मिस्तान अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में रविवार की सुबह लगी आग तो मात्र एक नमूना है। हकीकत यह है कि आधी दिल्ली आग के मुहाने पर बैठी है। न केवल पुरानी दिल्ली और अनधिकृत कॉलोनियां, बल्कि अन्य कई रिहायशी इलाकों में मकानों में अवैध रूप से औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी से दर्जनों लोग काल के गाल में समा सकते हैं।

सबसे बुरा हाल अनधिकृत कॉलोनी और पुरानी दिल्ली इलाके का है। ये कॉलोनियां आग से असुरक्षित हैं। यहां बहुमंजिला इमारतें बना दी गई हैं। इनमें धड़ल्ले से अवैध व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। पाश और नियमित कॉलोनियों में भी औद्योगिक इकाइयां चलाना आम बात है। इन इकाइयों का कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जाता है।

अधिकारी इसमें तकनीकी दिक्कत की बात करते हैं। उनका कहना है कि स्थानीय निकाय को यह पता ही नहीं होता कि किस परिसर में कौन सा व्यवसाय चल रहा है। कई लोग बगैर एजेंसियों को बताए अपना व्यवसाय तक बदल चुके हैं तो कुछ परिसर को दूसरे को किराये पर दे देते हैं। उनमें खतरनाक कारोबार तक किए जाते हैं। गत दिनों बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में लगी आग की घटना में कई लोगों की मौत एजेंसियों की लापरवाही का ही नतीजा था।

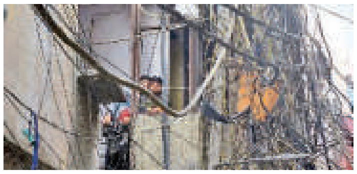

फिल्मिस्तान सिनेमा के पास अनाज मंडी स्थित तारों के जाल में चलती रही है फैक्ट्रियां। यह स्थिति दिल्ली के और भी कई इलाकों में देखी जा सकती है। हरीश कुमार

अग्निशमन नियमों का पालन जरूरी : अग्निशमन विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि आग से बचाव के नियम नहीं बनाए गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2010 में भवनों में आग से बचाव के लिए कई तरह के प्रावधान हैं। अवैध इलाके में भी 15 मीटर से ज्यादा ऊंचे आवासीय भवन में आग से बचाव किया जाना जरूरी है। व्यावसायिक परिसर में अलग-अलग मानक के मुताबिक आग से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नियम का कड़ाई से पालन किया जाए और इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तभी स्थिति में बदलाव संभव है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के पूर्व निदेशक एके शर्मा ने बताया कि फिल्मिस्तान में जहां आग लगी है, वह रिहायशी इलाका है। वहां औद्योगिक कार्य करना कानून का उलंघन है। इसके लिए सरकार को सामने आना होगा। स्पष्ट और कड़े नियम बनाने के साथ ही एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना होगा। तभी लोगों में डर कायम होगा और भवन में चलाए जा रहे अवैध कार्य रोके जा सकेंगे।

अर्पित होटल हादसे के बाद सख्त किए गए थे नियम : करोलबाग के होटल अर्पित में फरवरी में हुए भीषण अग्निकांड में 17 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नियमों में बदलाव किया था। इसके बाद दमकल विभाग ने बजट होटल और गेस्ट हाउस पर छापे मारे थे। वहीं, मई में 50 होटलों व गेस्ट हाउसों में मानक न पूरे होने पर अग्निशमन विभाग ने उनको दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) वापस ले लिया था। एनओसी न होने पर दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने भी उनके लाइसेंस को रद कर दिया था। जिन होटलों व गेस्ट हाउसों के लाइसेंस रद किए गए थे, वे पहाड़गंज, करोलबाग, नबीकरीम व महीपालपुर में स्थित हैं।

रिहायशी इलाकों में चल रहीं पांच हजार फैक्ट्रियां

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : चार मंजिला इमारत में इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री चल रही थी और अग्निशमन विभाग को पता नहीं चला, सैकड़ों की संख्या में श्रमिक काम करते रहे और श्रम विभाग अंजान रहा। प्लास्टिक सामानों का निर्माण हो रहा था तब भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की नजर में नहीं आई। हैरानी की बात यह कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों के संचालन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी पूरी दिल्ली घूम रही थी तो भी उसे यह फैक्ट्री दिखी नहीं। किसी इमारत में थोड़ी भी हलचल होने पर सक्रिय हो जाने वाली नगर निगम और दिल्ली पुलिस भी उंघता ही रहा। यह तो बात महज एक फैक्ट्री की। इसी अनाज मंडी में इसी तरह की 100 और अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। पुरानी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में इस तरह करीब 5000 फैक्ट्रियां चल रही हैं।

अनाज मंडी में पहले था आग बुझाने का इंतजाम, रहता तो बच जाती जानें

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

> अनाज मंडी में 500 से अधिक इमारतें, पहले होता था अनाज का काम

अनाज मंडी में पहले आपात स्थिति में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम थे। गलियों में आपातकाल में आग बुझाने के लिए अलग से पाइपलाइनें गई थीं। मुख्य द्वार के साथ अंदर जगह-जगह फायर हाइड्रेंट लगा था। जहां से पाइप लगाकर आग को बुझाया जा सकता था। कभी आग लगी तो उसका इस्तेमाल कर समय पर आग पर काबू पा लिया गया, इसलिए कभी इस तरह का भयावह हादसा नहीं हुआ, लेकिन 30 साल पहले तक रखरखाव और जनसंख्या के भारी दबाव में वह लुप्त हो गई। अगर वह व्यवस्था आज भी रहती तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता।

अनाज मंडी के व्यापारी व थाना सदर बाजार के नागरिक सुरक्षा समिति के संयोजक अर्जुन कुमार बताते हैं कि पहले यहां आगे से निपटने के लिए पूरे इंतजाम थे। अग्निशमन की लाइन पूरे बाजार में बिछी थी, उसे बोरिंग और नगर निगम के पीने के पाइपलाइन से जोड़ा गया था। छोटी आग की घटनाओं को समय रहते उसपर काबू पा लिया जाता था, लेकिन 30 साल पहले तक ररखरखाव के अभाव में वह व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बंद हो चुके फिल्मिस्तान सिनेमाहाल के नजदीक स्थित अनाज मंडी में आजादी से पहले अनाज का कारोबार होता था। तब इसमें 30 से अधिक दुकानें और 12 अनाज पीसने की चक्की थी। यह 20 साल पहले तक था इसके बाद इसमें प्लास्टिक उत्पादों की फैक्ट्रियां लग गईं। आठ साल पहले इन औद्योगिक इकाइयों को खतरनाक मानते हुए दिल्ली सरकार ने बवाना स्थानांतरित कर दिया तो उसके बाद इसमें पर्स, बैग, टिफिन बाक्स व टोपी बनाने की छोटी फैक्ट्रियां लग गई। प्लास्टिक पर छपाई का काम होने लगा। इसके लिए हर परिसर में मशीने लग गई। पूरे अनाज मंडी में 500 से अधिक इमारते हैं, जिनमें से 100 से अधिक इमारतें पूरी तरह से फैक्ट्रियों में तब्दील हो गई हैं। अभी भी काफी लोगों की रिहाइश इसी इलाके में है। नीचे फैक्ट्री चलती है और ऊपर लोग रहते हैं। जबकि पूरी तरह से व्यवसायिक इमारतों में वहां काम करने वाले मजदूर ही रहते हैं।

अनधिकृत कॉलोनी में घर होगा वैध, व्यवसाय हो जाएगा अवैध

पेच ▶ आवासीय आधार पर मिलेगा संपत्तियों को मालिकाना हक

किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि हो जाएगी पूर्णतया प्रतिबंधित

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

केंद्र व दिल्ली सरकार 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने का श्रेय लेना चाहती हैं, लेकिन यह हक कितना और किस एवज में मिलेगा, इसे कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है। इस आशय की अधिसूचना की पड़ताल करने पर ऐसी कई जानकारियां मिलीं जिनके सामने आने पर इन कॉलानियों के निवासियों की खुशी काफूर हो सकती है। इस कड़ी में एक कड़वा सच यह सामने आया है कि मालिकाना हक मिलने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में घर भले वैध हो जाएं, लेकिन वहां चल रहे तमाम व्यवसाय अवैध हो जाएंगे।

मालिकाना हक की सूची में शामिल कॉलोनियों में इकाइयां बेतरतीब ढंग से बनी हैं। वहां मनमाने ढंग से प्लॉट काटकर बेचे गए थे। लिहाजा, ढांचागत विकास कार्य और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जगह ही नहीं है। इन कॉलोनियों को नियमित न कर वहां केवल मालिकाना हक देने की योजना बनाई गई है। यह मालिकाना हक भी महज रिहायशी आधार पर ही दिया जाएगा। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा स्थिति यह है कि तमाम अनधिकृत कॉलोनियों में व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयां धड़ल्ले से चल रही हैं, चूंकि इन कॉलोनियों में फिलहाल सब कुछ ही अवैध है, इसलिए कार्रवाई से भी राहत है। यहां पर अब संपत्तियों को कानूनन मालिकाना हक मिलना शुरू होने जा रहा है तो व्यावसायिक गतिविधियां भी अवैध हो जाएंगी एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी और कार्रवाई की जद में आ जाएंगी। डीडीए के आला अधिकारियों का कहना है कि मालिकाना हक का प्रमाण पत्र जिस भी संपत्ति को मिलेगा, वह इसी आधार पर मिलेगा कि वह आवासीय इकाई है।

सभी कॉलोनियों में सौ फीसद मालिकाना हक नहीं

अधिसूचना में एक सच्चाई यह भी सामने आई है कि जिन 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने की बात हो रही है, वह भी वहां की सौ फीसद संपत्तियों को नहीं मिल पाएगा। जिन-जिन कॉलानियों का जो-जो हिस्सा मास्टर प्लान रोड, वन क्षेत्र, ओ जोन, हाई टेंशन तारों और एएसआइ द्वारा संरक्षित क्षेत्र में आ रहा होगा, उस क्षेत्र की संपत्तियों को मालिकाना हक से वंचित रखा जाएगा।

सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों में भी पेच

मालिकाना हक के लिए आवेदन के समय जो कागजात अनिवार्य हैं, उनमें जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), भुगतान की रसीदें और कब्जा पत्र प्रमुख हैं। ये कागजात होने और इनके सही पाए जाने पर ही डीडीए पोर्टल पर आवेदन हो सकेगा। डीडीए की टीम इन कागजों का सत्यापन करने पर ही आवेदक को कन्वेंस डीड (फ्री होल्ड के कागज) जारी करेगी। इसी कन्वेंस डीड के आधार पर रजिस्ट्री हो सकेगी। पेच यह है कि किसानों एवं बिल्डरों की जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी तो फिर भी यह कागजात जुटा लेंगे, जबकि सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों के निवासियों के लिए यह संभव नहीं होगा। ऐसे में उन्हें भी मालिकाना हक मिलना मुश्किल ही होगा।

छाया रहा स्मॉग, 12 से हैं राहत के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

रविवार को भी दिल्ली-एनसीआर वासियों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली। दिनभर स्मॉग छाया रहा व अगले दो-तीन दिन और प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी। सफर और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार से प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। गुरुवार से हवा फिर से साफ होने लगेगी। नोएडा रविवार को देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरेलाल के अनुसार पराली जलाने के मामले तो अब कम हो गए हैं, लेकिन ठंड बढ़ने लगी है। इससे बचने के लिए लोग खुले में आग जला रहे हैं। इसे नियंत्रित करना काफी जरूरी है। दिसंबर और जनवरी में वायू प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी होती है।

सफर के मुताबिक सोमवार को प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार आ सकता है। जमीनी स्तर पर हवा की रफ्तार में थोड़ा इजाफा संभव है। मंगलवार को हवा फिर सुस्त रहेगी। बुधवार से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे गुरुवार को दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। बारिश से प्रदूषक तत्व बैठ जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण में भी सुधार होने के आसार हैं। बारिश के साथ मौसम और भी ठंडा हो जाएगा।

> बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ- दिल्ली एनसीआर का एयर इंडेक्स

> बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व बारिश होने के हैं आसार

रविवार का एयर क्वालिटी इंडेक्स

शहर	एक्यूआइ
दिल्ली	391
गाजियाबाद	413
ग्रेटर नोएडा	395
गुरुग्राम	362
नोएडा	414
पलवल	327

दिल्ली में रविवार को छाए स्मॉग का दृश्य। अगले दो-तीन दिन यही स्थिति रहने का अनुमान। प्रेट्र

न्यायालय के निर्णय से एकेटीयू को झटका, छात्रों को राहत

मनीष तिवारी, ग्रेटर नोएडा

> झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची के सैकड़ों छात्रों का प्रवेश कर दिया था निरस्त

डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि (एकेटीयू) की सेमेस्टर परीक्षाओं से पूर्व हाई कोर्ट ने झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची से परीक्षा पास कर एकेटीयू से संबंद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। निर्णय से छात्रों में खुशी व्याप्त हो गई है।

एकेटीयू से संबंद्ध कॉलेजों में देश के दूसरे राज्यों के छात्र भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर उन शिक्षा बोर्डों की सूची डालता है जिनको वैधानिक मान्यता है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने पर कॉलेज प्रबंधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उन बोर्डों की सूची देखकर छात्रों को प्रवेश देते हैं। विवि ने बिना जांचे-परखे झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची का नाम भी वेबसाइट पर अपनी सूची में डाल दिया था। इसके आधार पर कॉलेजों ने वहां के छात्रों को प्रवेश दे दिया था। झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची की वैधानिक मान्यता न होने की बात कह कर विवि ने कुछ माह पूर्व वहां के छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया था। इससे प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों को झटका लगा था। बहुत से छात्र ऐसे थे जो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। विवि के निर्णय से छात्रों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ उनकी सालों की मेहनत भी खराब हो रही थी। छात्रों ने फाइट अंगेस्ट करप्शन(फेस) संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर एके सिंह के साथ लड़ाई की शुरुआत कर न्यायालय में याचिका दायर की थी। निर्णय में न्यायालय ने कहा है कि विवि ने विभिन्न तथ्यों को देखने के बाद छात्रों को प्रवेश दिया था। इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। छात्रों की पढ़ाई जारी रखते हुए परीक्षा में बैठने दिया जाए। एकेटीयू के वीसी विनय पाठक ने कहा कि न्यायालय का आदेश अभी नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद कानूनी विशेषज्ञ से राय लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

गुरुद्वारों में दंगा पीड़ितों के लिए खुलेंगी दुकानें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगे के पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने ऐतिहासिक गुरुद्वारों में '1984 स्टोर' नाम से दुकानें खोलने का फैसला किया है। इन दुकानों का प्रबंधन पीड़ित परिवार के सदस्य संभालेंगे। इस माह के अंत तक गुरुद्वारा बंगला साहिब में और जनवरी में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दुकानें शुरू हो जाएंगी। अगले वर्ष के अंत तक दिल्ली के दस ऐतिहासिक गुरुद्वारों में इस तरह की दुकानें खुल जाएंगी।

डीएसजीपीसी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों को नियमित आमदनी उपलब्ध कराने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सरकार व अन्य संगठनों पर उनकी निर्भरता खत्म हो सके। पीड़ित परिवार सामूहिक रूप से इन दुकानों का संचालन करेंगे। दुकानों से होने वाली आमदनी पीड़ित परिवारों के विकास पर खर्च होगी। इन दुकानों में चावल, आटा सहित घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं उपलब्ध होंगी। साथ ही धार्मिक किताबें, सिख धर्म से संबंधित साहित्य की बिक्री की जाएगी।

नेताओं की वीआइपी सुरक्षा हटाने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

> दुष्कर्म के दोषियों को फांसी दिलवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी हैं स्वाति जयहिंद

> गृहमंत्री को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों की भर्ती का मामला भी उठाया

दुष्कर्म के दोषियों को फांसी दिलवाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद का अनशन छठे दिन भी जारी रहा। डॉक्टरों के मुताबिक स्वाति की सेहत स्थिर है लेकिन वजन पहले दिन से चार किलो कम हो चुका है। अनशन के छठे दिन स्वाति ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नेताओं की वीआइपी सुरक्षा हटाने की अपील की है।

स्वाति ने कहा कि संसद में बैठने वाले नेता बेटियों पर हो रहे जुर्म और अपराधों का दर्द इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका परिवार सुरक्षा घेरे में रहता है। ऐसे में देश की आम महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए वे कैसे कोई कड़ा कानून बना सकते हैं।

पत्र में स्वाति ने गृहमंत्री को अपनी मांगों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने यह भी लिखा कि दिल्ली पुलिस पिछले 13 सालों से 66 हजार पुलिस कर्मियों की मांग कर रही है, जो आज तक नहीं मिले। दिल्ली पुलिस कर्मियों की बहुत बड़ी संख्या वीआइपी सुरक्षा में ड्यूटी देने में इस्तेमाल की जाती है। दिल्ली के पुलिस थाने निर्धारित स्टाफ से आधे पर काम करने पर मजबूर हैं। ऐसे में सुरक्षाबलों की वीआइपी सुरक्षा में तैनाती जायज नहीं है। उन्होंने पत्र में पुलिसकर्मियों की तत्काल नियुक्ति की मांग भी की। स्वाति ने ट्वीट कर यह भी कहा, जिस दिन नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई और जब उनके घर की बेटियां रात को अकेली कहीं से लौटेंगी तब इनके मन में डर बनेगा। उस दिन वे मजबूत कानून बनाने की दिशा में काम करेंगे। स्वाति ने पत्र में लिखा कि दिल्ली महिला आयोग की सदस्य महिला सुरक्षा के मुद्दों पर उनके साथ तत्काल बैठक करना चाहती हैं, उन्हें मिलने का समय दिया जाए। स्वाति की मांग को देशभर से समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर 'नो मोर वीआइपी कल्चर' ट्रेंड हुआ। इसमें महिलाओं ने हाथों में तख्ती लिए सरकार से पूछा, जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं तो पुलिस के संसाधनों का अपव्यय क्यों हो रहा है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद के समर्थन में पहुंची महिलाएं। जागरण

कुलपति कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने परिजनों के साथ किया प्रदर्शन

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) शिक्षक संघ की तरफ से तदर्थ शिक्षकों की बहाली के लिए आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। तदर्थ शिक्षकों के समायोजन, पदोन्नति व पेंशन के साथ विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों ने परिवार के साथ नॉर्थ कैंपस में कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन डूटा के बैनर तले हुआ। डूटा ने रविवार को शिक्षकों को परिवार संग आने के लिए कहा था। शिक्षकों के स्वजन हाथों में नारों वाली तख्तियां लिए थे। इन तख्तियों पर 'मेरी मां को समायोजन दो', 'मेरी मां अभी भी एडहॉक है' जैसे नारे लिखे थे। डूटा उपाध्यक्ष आलोक पांडेय ने कहा कि बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने अपनी पीड़ा को साझा करते हुए प्रशासन से समायोजन की मांग की।

डीयू प्रशासन ने फिर डूटा से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। डीयू के रजिस्ट्रार प्रो. तरुण दास ने वरिष्ठ शिक्षाविदों और डीयू की कुछ संकाय के प्रमुखों के साथ रविवार को हुई बैठक का हवाला देते हुए डूटा के मौजूदा आंदोलन को विश्वविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला कहा।

योजना

नाव पर बैठ कर पर्यटक कर सकेंगे पक्षियों का दीदार

ओखला पक्षी विहार के लिए वन विभाग तीन नावों में कर रहा सजावट, एक सप्ताह बाद उपलब्ध होगी सुविधा

जागरण संवाददाता, नोएडा

ओखला पक्षी विहार में प्रवासी पक्षियों के कलरव देखने आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए वन विभाग अलग प्रयोग कर रहा है। वन विभाग पक्षी विहार में बेंच के साथ तीन नावों को पक्षी विहार के किनारे स्थापित कर रहा है। इन नावों पर पर्यटक बैठ कर पक्षियों का दीदार कर सकेंगे। अगले सप्ताह तक तीनों नावों को स्थापित कर दिया जाएगा।

प्रभागीय वनाधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया कि ओखला पक्षी विहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पर्यटकों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। कुछ नए बेंच और लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पानी के किनारे तीन नावों को स्थापित किया जा रहा है। ये नावें कभी यमुना में इस्तेमाल की जाती थीं। इन नावों को सजाया जा रहा है। इन पर विभिन्न पक्षियों की फोटो व उनके बारे में जानकारी भी दी जाएगी।

पीके श्रीवास्तव। जागरण आर्काइव

पर्यटकों के बैठने के लिए नाव के दोनों तरफ बेंच लगाई जाएंगी। दोनों बेंच के बीच टेबल होगी। जिस पर पर्यटक सामान रख सकते हैं। तीनों नावों को अलग-अलग स्थान पर लगाया जा रहा है, जहां से अधिक से अधिक पक्षियों को देखा जा सके।

आठ हजार से अधिक पहुंचे प्रवासी पक्षी : प्रभागीय वनाधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया कि ओखला पक्षी विहार में करीब आठ हजार प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। इनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। फ्लेमिंग इस बार पूरे वर्ष रहे हैं। सिर्फ बारिश के समय में कुछ दिन नहीं दिखाई दिए थे। दस वर्ष पहले ओखला पक्षी विहार इनका मुख्य ठिकाना हुआ करता था।

हाईटेंशन लाइन, डीएनडी पर गुजरने वाले वाहनों व निर्माण कार्य से होने वाले शोर की वजह से इस पक्षी ने राजस्थान, दिल्ली व अन्य स्थानों को ठिकाना बना लिया था। भोजन की पर्याप्त उपलब्धता की वजह से अब दोबारा यह पक्षी यहां आकर रहने लगे हैं। यह पक्षी बदलते पर्यावरण के मुताबिक खुद को ढाल चुके हैं। इसके अलावा, ग्रेट ईग्रेट, ब्लैक विंगेड स्टिल्ट, ग्रे हेरोन, पर्पल हेरोन, कॉमन कोट, ग्रेलाग गूज, नार्दर्न शोवेलर समेत 35 से अधिक प्रजाति के प्रवासी पक्षी भी मौजूद हैं।

ओखला पक्षी विहार में पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच की तरह इस्तेमाल की जाएगी नाव। तीन नावें तैयार की जा रही हैं। सौजन्य : वन विभाग

फिर झलका ट्विटर पर आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों का दर्द

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

> आम्रपाली के पीड़ित फ्लैट खरीदार ने गृह मंत्री को अपना फ्लैट देने का किया एलान

आम्रपाली की बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले खरीदारों ने ट्विटर अभियान छेड़ा हुआ है। खरीदार लगातार ट्वीट कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। रविवार को भी आम्रपाली की बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले लोगों का ट्विटर पर दर्द झलक उठा। इतना ही नहीं एक खरीदार ने तो अपना फ्लैट गृहमंत्री अमित शाह के नाम करने का ट्विटर पर एलान किया है। पीड़ित द्वारा किया गया ट्वीट रविवार को पूरे दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा।

जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के खरीदारों को घर दिलाने की लड़ाई लड़ने वाली संस्था नेफोवा के उपाध्यक्ष व आम्रपाली की बिल्डर परियोजना में घर खरीदार दीपांकर ने अपना घर गृह मंत्री अमित शाह को देने का फैसला किया है। उन्होंने बकायदा अपनी सारी समस्या स्टांप पेपर पर लिखकर ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि वे संयुक्त होकर लगातार विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं में फंसे खरीदारों को घरौंदा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अपना घर पाने को पिछले दस साल से चल रही जद्दोजहद के बाद उनके खुद की हिम्मत जवाब देने लगी है। उन्होंने अपना घर गृहमंत्री को देने की बात करते हुए कहा कि यदि गृहमंत्री के नाम घर कर दिया जाए तो शायद अन्य पीड़ितों को उनका घर मिल सकता है। साथ ही उन्हें घर देने के बाद कुछ बड़े अधिवक्ता भी फ्लैट खरीदारों के खिलाफ अपना मुंह नहीं उठा सकेंगे। साथ ही परियोजना में गृह मंत्री का घर होने की वजह से केंद्र सरकार आम्रपाली को भी स्ट्रेस फंड देने पर विचार करेगी।

3.46 लाख दुर्घटनाएं हुईं थी भारत में जनवरी–सितंबर 2018 में। इनमें 3,55,042 लोगों की मौत हुई थी और 3,39,135 लोग घायल हुए थे। यह आंकड़े सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं।

आतंकवाद के कारण सार्क पर लगा ग्रहण

खरी–खरी ▸ क्षेत्रीय संगठन के स्थापना दिवस पर मोदी का पाकिस्तान पर निशाना

कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से ही बढ़ेगा सदस्य देशों में भरोसा

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

दक्षिण एशियाई देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 35 वर्ष पहले स्थापित सार्क संगठन का भविष्य अभी अंधकारमय ही दिख रहा है। सार्क के स्थापना दिवस पर रविवार (आठ दिसंबर) को पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्क सचिवालय को पत्र लिख कर एक समृद्ध व शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने परोक्ष तौर पर यह भी बता दिया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की वजह से ही सार्क पर ग्रहण लगा है। पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिया है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ ठोस व निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक सार्क सदस्यों के बीच भरोसे का संचार भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी इस अवसर पर औपचारिक संदेश देते हुए उम्मीद जताई है कि सार्क की राह में जो अड़चनें पैदा की गई हैं वे जल्द समाप्त कर दी जाएंगी।

नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि वैसे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गठन आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हुआ था लेकिन इस दिशा में अभी काफी काम किया जाना शेष है। उन्होंने कहा है कि सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को आतंकवाद के खतरों से काफी धक्का लगा है। अगर सार्क की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना है तो हमें वैसा माहौल भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी है कि इस क्षेत्र के सभी देश आतंकवाद और इसे समर्थन देने वाली ताकतों को हराने के लिए आतंकवाद के स्रोतों को नष्ट करें। ऐसा करने से ही सदस्य देशों के बीच भरोसा पैदा होगा और सार्क मजबूत होगा। कहने की जरूरत नहीं कि पीएम मोदी ने सार्क को लेकर भारत की पारंपरिक नीतियों को ही बताया है और पाकिस्तान का नाम लिये बगैर उसे सार्क की राह में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर चिन्हित किया है।

दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सार्क दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि, सार्क को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में जो अंतराल पैदा हुआ है उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने दक्षिण एशिया के सभी निवासियों के लिए शांति, समृद्धि और संपन्नता की कामना करते हुए कहा है कि यह दिवस हमें बताता है कि इस क्षेत्र की जनता ने हमारे कंधे पर कितना बड़ा दायित्व डाला हुआ है। इस क्षेत्र की जनता यहां के नेताओं से उम्मीद करती है कि वह अशिक्षा, गरीबी, बीमारी की चुनौतियों से लड़ेंगे। पाकिस्तान क्षेत्रीय विकास में सहयोग का पूरा समर्थन करता है और समझता है कि यह सार्क चार्टर के मुताबिक क्षेत्रीय संप्रभुता व परस्पर आदर भाव से हासिल किया जा सकता है।

बता दें कि सार्क की पिछली बैठक वर्ष 2016 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी तय थी। लेकिन जनवरी, 2016 में पठानकोट और उसके बाद उड़ी में सैन्य शिविरों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के बाद भारत ने बेहद सख्त रणनीति अख्तियार करते हुए सार्क की बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। भारत के साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के भी शामिल होने से इन्कार की वजह से सार्क शिखर बैठक नहीं हो सकी थी।

भारत ने सार्क को दरकिनार कर उसकी जगह एक दूसरे क्षेत्रीय सहयोग संगठन बिम्सटेक को बढ़ावा देने की रणनीति अपना ली। उसके बाद सार्क सहयोग भी तकरीबन बिखरा हुआ है। बिम्सटेक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व मालदीव के अलावा सार्क के शेष देश व साथ ही म्यांमार व थाइलैंड भी शामिल हैं। सार्क को लेकर भारत के बदले मिजाज को पीएम मोदी के दूसरे शपथग्रहण समारोह से भी पता चलता है। वर्ष 2014 के शपथ ग्रहण में सार्क के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था जबकि मई, 2019 के समारोह में बिम्सटेक देशों के सदस्यों को निमंत्रित किया गया था।

बता दें कि सार्क आठ देशों का संगठन है। इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान शामिल हैं।

सोनिया गांधी नहीं मनाएंगी अपना जन्मदिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश भर में महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर अपनी चिंता और संवेदना का इजहार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। पार्टी की ओर से सोनिया गांधी के जन्मदिन पर किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।

सोनिया गांधी (फाइल फोटो)

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेताओं को भी सोनिया गांधी के जन्मदिन का जश्न नहीं मनाने का संदेश दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद में महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हुई बर्बर हत्या और उन्नाव की लड़की को दुष्कर्मियों द्वारा जलाकर मारने की घटना से सोनिया गांधी बेहद व्यथित हैं। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ हिंसक यौन अपराध की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं और कांग्रेस अध्यक्ष ने इसीलिए अपना 73वां जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। दिल्ली की अनाज मंडी में भीषण आग से हुई लोगों की दर्दनाक मौत को देखते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व जन्मदिन पर कोई आयोजन नहीं करेगा।

विदेशी डिग्रीधारी डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ भारत में प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य परीक्षा में महज 10 फीसद हो पाते हैं पास

सरकार विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस शुरू करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने में मदद करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए इन डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदेश से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एक विशेष परीक्षा देनी होती है, लेकिन इसमें अधिकांश डॉक्टर फेल हो जाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2014 से 2018 के बीच विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 74,202 डॉक्टरों ने प्रैक्टिस शुरू करने के लिए होने वाली अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा दी थी। इनमें से केवल 10,400 डॉक्टर ही इस परीक्षा में सफल हो सके। अब स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी में जुटी है, ताकि उन्हें भारत में पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के समान गुणवत्ता तक लाया जा सके। इसके तहत कई ओपन ऑनलाइन कोर्स के साथ-साथ उन्हें क्लीनिकल स्किल लैब की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर वापस आने वाले डॉक्टरों का आरोप है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में भारतीय डॉक्टरों के मुकाबले जानबूझकर कठिन सवाल पूछे जाते हैं, इसी कारण केवल 10 फीसद डॉक्टर इसे पास कर पाते हैं। यह परीक्षा जून और दिसंबर में साल में दो बार आयोजित की जाती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आने वाले एक-दो वर्षों में विदेश से पढ़ाई कर आने वाले छात्रों के लिए नई परीक्षा की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 1956 के एमसीआइ कानून की धारा 13(4ए) के तहत विदेशी डॉक्टरों के लिए विशेष परीक्षा पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब एमसीआइ को निरस्त कर सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन करने जा रही है। इससे संबंधित कानून संसद के पिछले मानसून में पास हो चुका है। नए कानून में विदेश से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को भी भारतीय डॉक्टरों के साथ एक ही एक्जिट परीक्षा देनी होगी। दरअसल एमबीबीएस की अंतिम साल की परीक्षा को एक्जिट परीक्षा में बदल दिया गया है, जो पूरे देश में एक समान होगी। इससे एमबीबीएस डॉक्टरों की गुणवत्ता में समानता लाने में मदद मिलेगी।

परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए रेलवे के कई विभागों का होगा विलय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक तथा कार्मिक व लेखा विभाग एक में मिलेंगे

▸ अगले कुछ दिनों में विभागों के विलय को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना

दुनिया में सबसे बड़ा है भारतीय रेलवे का परिचालन तंत्र। (फाइल फोटो)

विभागों के बीच खींचतान के कारण परियोजनाओं में विलंब तथा खर्चों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेलवे के कई विभागों का आपस में विलय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सिविल इंजीनियरिंग के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जबकि कार्मिक के साथ लेखा विभाग को मिलाने का प्रस्ताव है। अगले कुछ दिनों में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके बाद रेलमंत्री स्वयं इसकी घोषणा कर सकते हैं।

हाल में राजधानी में संपन्न 'परिवर्तन' संगोष्ठी में पहले से विचाराधीन इस विषय पर खुलकर चर्चा हुई और इसके बारे में युवा अफसरों से भी राय ली गई। उनसे पूछा गया कि रेलवे में परियोजनाओं की लागत घटाने और उनमें तेजी लाने के लिए वे किन चीजों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत समझते हैं। इस पर ज्यादातर युवा अफसरों ने विभागवाद को रेलवे की सबसे बड़ी समस्या बताया। इससे परियोजनाओं में अकसर देरी होती है। रेलवे की माली हालत खराब होने के लिए भी काफी हद तक यही जिम्मेदार है जिसके कारण अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा मिलता है। युवा अफसरों ने इसे समाप्त करने के लिए कुछ विभागों के आपस में विलय का सुझाव दिया। इससे पहले बिबेक देबराय समिति भी इसी तरह का सुझाव दे चुकी है।

परिवर्तन संगोष्ठी का आयोजन रेलवे की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करना था। इसके लिए युवा अफसरों की राय को खास महत्व देने का निर्णय लिया गया था। यही वजह है कि संगोष्ठी में महाप्रबंधकों के अलावा बड़ी संख्या में उनके अधीनस्थ प्रतिभाशाली युवा अफसर बुलाए गए थे।

दरअसल रेलवे में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अफसरों की लड़ाई के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस के भविष्य के उत्पादन में विलंब होने के कारण नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इसी प्रकार कार्मिक और लेखा विभाग के अफसरों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण कर्मचारियों द्वारा वित्तीय कदाचार के कई मामले सामने आए हैं।

दो दिन तक चले महामंथन में महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में युवा अफसरों के समूहों ने रेलवे के आधुनिकीकरण एवं सेवाओं में सुधार के बारे में कई क्रांतिकारी परिवर्तनों के सुझाव दिए हैं जिन पर निकट भविष्य में ही कार्य शुरू हो जाने की संभावना है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने दो दिनों के दौरान संगोष्ठी में उपस्थित 300 अफसरों के अलावा सुदूर मुख्यालयों में 1000 अफसरों को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये संबोधित किया।

'पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यक बंटवारे के पीड़ित'

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा महासचिव राम माधव ने नागरिकता संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है, क्योंकि वे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किए जाने के पीड़ित हैं। राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही आलोचना का जवाब देते हुए माधव ने कहा कि इसी तरह का कानून आव्रजक (असम से निर्वासन) अधिनियम 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तत्कालीन सरकार ने बनाया था।

माधव ने कहा कि नेहरू सरकार ने अवैध प्रवासियों को खासतौर पर पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए लोगों को निर्वासित करने के लिए 1950 में इसी तरह का कानून बनाया था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक इसके दायरे में नहीं आएंगे। भारत ने उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे।

पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी के रणनीतिकार माधव ने कहा कि सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्र के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षकारों से गहन चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विधेयक के मद्देनजर जनसांख्यिकी, भाषा और संस्कृति में बदलाव सहित राज्यों की सभी आशंकाओं का सरकार निराकरण करेगी। सांसदों को वितरित नागरिकता (संशोधन) विधेयक -2019 की प्रति के मुताबिक यह कानून परमिट क्षेत्र (आइएलपी) और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जहां पर संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासन होता है। इसलिए यह कानून असम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों और अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम के परमिट इलाकों में लागू नहीं होगा।

राम माधव। (फाइल फोटो)

▸ भारत ने उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे

▸ पूर्वोत्तर की आशंकाएं दूर करने के लिए सरकार ने की है पक्षकारों के साथ गहन चर्चा

नागरिकता विधेयक पारित होना गांधी के विचारों पर जिन्ना की जीत होगी : थरूर

▸ पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर लगाया 'एक समुदाय' को निशाना बनाने का आरोप

▸ कहा, धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता तय करने को लेकर बंट गया था स्वतंत्रता संग्राम

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का पारित होना निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के विचारों पर मुहम्मद अली जिन्ना के विचारों की जीत होगी। यह बात रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कही। थरूर ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने से भारत 'पाकिस्तान का हिंदू संस्करण' भर बनकर रह जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 'एक समुदाय' को निशाना बना रही है। दूसरे धर्मों की तुलना में उस समुदाय के लोगों का उन्हीं स्थितियों में उत्पीड़न पर उन्हें शरण नहीं दे रही है।

थरूर ने विशेष भेंट में कहा कि अगर विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया भी जाता है, तो उन्हें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय की कोई भी पीठ संविधान की मूल भावना का 'घोर उल्लंघन' नहीं होने देगी।

थरूर ने कहा, 'यह सरकार का शर्मनाक काम है, जिसने पिछले वर्ष राष्ट्रीय शरणार्थी नीति बनाने पर चर्चा करने से इन्कार कर दिया, जिसे मैंने निजी विधेयक के तौर पर प्रस्तावित किया था।' उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक उन्होंने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। वास्तव में वे मूलभूत कदम भी नहीं उठाना चाहते, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थियों से अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम इस आधार पर बंट गया कि क्या धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता तय की जाए और जिन लोगों का उस सिद्धांत में विश्वास था उन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा की वकालत की।

शियाओं ने उठाई मांग, अलग से की जाए उनकी जनगणना

जागरण संवाददाता, लखनऊ

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित सालाना बैठक (इजलास-ए-आम) में केंद्र सरकार से जनगणना में शिया मुस्लिमों की अलग से गणना किए जाने तथा आबादी के मुताबिक योजनाओं का लाभ देने की मांग उठी। साथ ही बोर्ड में 21 अन्य प्रस्ताव भी पेश किए गए। इन प्रस्तावों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से मिलेगा।

इजलास का आगाज कारी नदीम नजफी ने किया। मौलाना एजाज अतहर ने बोर्ड की ओर से प्रस्ताव पेश किए। प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा,एनआरसी पर पुनर्विचार होना चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष मौलाना सायम मेहंदी नकवी ने भी अपने विचार रखे। बोर्ड ने शादी की फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की।

पुनर्विचार याचिका का विरोध गलत : मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अयोध्या मामले में संविधान ने हमें पुनर्विचार याचिका का अधिकार दिया है। अगर कोई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहा है तो उसका विरोध करना सही नहीं है।

पास हुए ये प्रस्ताव

- एनआरसी पर पुनर्विचार कर शियों की समस्याओं का समाधान हो।
- शिया–सुन्नी वक्फ बोर्ड को मर्ज न किया जाए, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हो।
- हज कमेटी में प्रतिनिधित्व के साथ शियों को सहूलियत दी जाए।
- हज सब्सिडी बहाल कर 1970 तक ईरान व ईराक में जियारत करने जाने वालों को विमान किराए में सब्सिडी मिले।
- हिंदुस्तानी सिटीजन बिल के तहत पाक, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के शियों को नागरिकता दी जाए।
- जन्नतुल बकी के रौजे की तामीर की इजाजत दी जाए।
- सच्चर कमेटी की तरह अलग कमीशन गठित किया जाए
- सरकारी नौकरी में आरक्षण के साथ सदन में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।
- लखनऊ के चिकनकारी व जरदोजी को इंडस्ट्री के रूप में विकसित करें।

काम न करने वाले अधिकारी बांध लें बोरिया–बिस्तर : योगी

जागरण संवाददाता, बांदा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में मंडल स्तरीय बैठक के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बेहद अंदाज में कहा कि काम न करने वाले अफसर अपना बोरिया-बिस्तर बांध लें। प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनुराग श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि चित्रकूट के बरगढ़ व मऊ पेयजल परियोजना व हैंडपंप घोटाले में दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।

रविवार को तय समय से करीब एक घंटा विलंब से आए मुख्यमंत्री सीधे तिंदवारी पहुंचे। यहां करीब 25 मिनट गोशाला का निरीक्षण के बाद सड़क मार्ग से करीब तीन बजे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। लंच के बाद चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पशु वन्य बिहार सहित गोशालाओं के लिए अरबों रुपये दिए गए लेकिन काम क्यों नहीं कराए गए। मवेशियों में जियो टैगिंग न होने पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों की क्लास ली। कहा कि तय करिए काम करना है या नहीं, अन्यथा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा पाइका विद्रोह का स्मारक : राष्ट्रपति

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

▸ विद्रोह के 200 साल पूरा होने पर खुर्दा के वरुणेई में किया शिलान्यास

▸ उत्कल विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में पूर्व छात्रों का किया आह्वान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को ओडिशा में खुर्दा जिले के वरुणेई में पाइका विद्रोह के 200 साल पूरा होने पर स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने पाइका विद्रोह की गौरवगाथा का वर्णन किया और विद्रोहियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वरुणेई को वीरभूमि बताते हुए कहा कि यह स्मारक आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। कहा कि पाइका स्वाभिमानी थे। उन्होंने बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति ने कहा कि पाइका विद्रोह में ओडिशा के सभी वर्ग के लोग शामिल थे। यह स्मारक विश्व को पाइका संस्कृति से साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ने पाइका स्मारक का निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रयासों की सरहाना की।

ओडिशा ने दिया पूरी दुनिया को शांति का संदेश : उत्कल विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में भाग लेते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। एक दिन यह देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षा संस्थान बनेगा। पांच से सात साल में यह विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल होगा। इसके लिए राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को आगे आने का आह्वान किया।

भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (दाएं नीले कोट में), उनकी पत्नी सविता कोविंद (साड़ी में) और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन का स्वागत करते ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (बाएं)। (एएनआइ)

यह था पाइका विद्रोह : 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध ओडिशा में पाइका जाति के लोगों ने विद्रोह किया था। यह एक सशस्त्र, व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था।

राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल से रुकेंगी दुष्कर्म की घटनाएं

प्रथम पृष्ठ से आगे

इससे पहले पुणे में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून से ऐसी घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल जरूरी है। नायडू ने कहा कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को मां एवं बहन की तरह सम्मान दिया जाता है। हाल में हुई घटनाएं शर्मनाक हैं और सबके लिए चुनौती हैं। उन्होंने इस मसले को धर्म के चश्मे से देखने और राजनीति करने की भी आलोचना की। नायडू ने कहा, 'कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ऐसी घटनाओं की राजधानी बन गया है। मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता। हमें अपने देश का अपमान नहीं करना चाहिए और ऐसी नृशंस घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।'

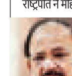

वेंकैया नायडू फाइल

बेहतर नतीजे

कुछ राज्यों ने सड़क पर निगरानी बढ़ाकर प्राप्त किए बेहतर परिणाम, उत्तराखंड ने भी साबित किया जुर्मानों से अधिक कारगर है कानून का कार्यान्वयन, इस साल जनवरी से सितंबर तक देश में हुईं कुल 3,39,135 सड़क दुर्घटनाएं

जुर्माना बढ़ाए बगैर गुजरात, पश्चिम बंगाल में सड़क हादसों में कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महज जुर्माना बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। बल्कि कानून को सख्ती से लागू कर भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कई राज्यों ने इसे करके दिखाया है। उन्होंने संशोधित मोटर एक्ट के बढ़े जुर्माने वसूले बगैर केवल सड़क पर निगरानी बढ़ाकर उन राज्यों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं, जिन्होंने अपने यहां जुर्माने बढ़ाए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के नवीनतम आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है।

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी-सितंबर के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में 2.2 फीसद की गिरावट देखने को मिली है। मौतों का आंकड़ा सिर्फ 0.2 फीसद बढ़ा है। सड़क दुर्घटनाओं के राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि जो राज्य मोटर एक्ट को सख्ती से लागू कर रहे हैं, वहां हादसे और मौतें दोनों घट रही हैं। भले ही उन्होंने एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ाने से इन्कार कर दिया हो। इनमें गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। गुजरात में हादसे 9.6 फीसद, जबकि मौतें 9.6 फीसद घटी हैं। उत्तराखंड में हादसों में 5.2 फीसद व मौतों में 16.7 फीसद की कमी आई। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में क्रमशः 4.6 तथा 3.4 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

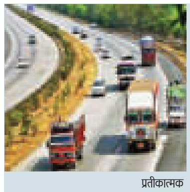

प्रतीकात्मक

उत्तर प्रदेश, केरल में बढ़े हादसे

- जिन राज्यों ने मोटर एक्ट को लागू करने में उदासीनता दिखाई है, वहां हालात बदतर हुए हैं।
- उत्तर प्रदेश में हादसों में 1.7 फीसद, जबकि मौतों में 3.7 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
- केरल में सड़क दुर्घटनाओं में 3 फीसद और मौतों में 4.3 फीसद का इजाफा हुआ है।
- मेघालय में हादसों में 31.2 फीसद, जबकि मौतों में 7.3 फीसद का इजाफा हुआ है।
- मणिपुर में भी हादसे 22 फीसद और मौतें 12.8 फीसद बढ़ी हैं।

संशोधित मोटर एक्ट अगस्त में संसद से पास हुआ था। एक सितंबर से इसके बढ़े जुर्माने वाले प्रावधान लागू कर दिए गए थे। लेकिन, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने बढ़े जुर्मानों को लागू करने से इन्कार कर दिया था और कम जुर्मानों से ही यातायात उल्लंघनों में कमी लाने का दावा किया था। इनका कहना था कि संशोधित एक्ट में सीट बेल्ट या हेलमेट बगैर गाड़ी चलाने जैसे कंपाउंडेबल अपराधों में भी जुर्माने को अनाप-शनाप बढ़ा दिया गया है, जिससे आम जनता के उत्पीड़न का खतरा है। जुर्माना बढ़ाए बगैर केवल कानून के सख्त अनुपालन से भी हादसों में कमी लाई जा सकती है।

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी-सितंबर 2019 तक देश में कुल 3,39,135 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,12,735 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,45,067 लोग घायल हुए। इससे पहले जनवरी-सितंबर 2018 में 3,46,806 दुर्घटनाओं में 3,55,042 लोगों की मौत हुई थी और 3,39,135 लोग घायल हुए थे। इससे पता चलता है कि मोटर एक्ट लागू होने के एक माह समेत नौ महीनों में केवल 7,671 दुर्घटनाएं कम हुईं, जबकि 266 मौतें बढ़ गईं। घायलों का आंकड़ा भी केवल 9,975 कम हुआ है।

दूसरी ओर जिन राज्यों ने केवल जुर्माने बढ़ाने के बजाय यातायात नियम अनुपालन पर सख्ती शुरू की, वहां हादसों व मौतों दोनों पर प्रभावी अंकुश लगता दिखाई देता है। उदाहरण के लिए दिल्ली को लें। यहां जुर्मानों के अलावा कंपाउंडिंग उल्लंघनों के चालान भी कोर्ट भेजे जाने के कारण कम चालानों के बावजूद हादसों में 12 फीसद तथा मौतों में 19 फीसद की उल्लेखनीय कमी आई है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा था और तीनों हार गए थे। इस बार दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व हेमंत सोरेन मैदान में हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 दिसंबर 2019

हुंकार ▸ रक्षा मंत्री ने धनबाद के झरिया और देवघर के करौं में की चुनावी सभाएं

'हम किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं'

जागरण संवाददाता, धनबाद/देवघर

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

हम किसी देश को छेड़ते नहीं, लेकिन हमें जो छेड़ता है उसे छोड़ते भी नहीं। यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को झारखंड के धनबाद के झरिया और देवघर के करौं में आयोजित भाजपा की चुनावी जनसभाओं में कहीं। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35 ए को जम्मू-कश्मीर से हटाए जाने को वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाने जैसा बताया। साथ ही कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाए जाने का वादा करते हुए कहा कि भाजपा ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया।

उन्होंने कहा कि अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की मजबूत सरकार है, जिसके इरादे ठोस हैं। हम बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। भाजपा देश के विकास की राजनीति करती है। हमारी नीति और नीयत दोनों साफ हैं। डेढ़ साल पहले पड़ोसी देश ने आतंकवादी भेजकर देश की सेना पर हमला किया था। इसका जवाब हमारी सेना ने पड़ोसी देश में घुसकर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा और इज्जत दोनों बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में हमारी बहुमत की सरकार बनी तो कश्मीर में आजादी के बाद से चले आ रहे अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाया गया। हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश में एक प्रधान, एक विधान व एक निशान के सपने को पूरा किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर किया। अब दुनिया की कोई ताकत वहां राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही देश में एनआरसी लागू कर विदेशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश के हर गरीब को पक्का घर देने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए रसोई गैस और उनके सम्मान व स्वास्थ्य के लिए हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना से हर साल पांच लाख का निःशुल्क इलाज का खर्च दिया जा रहा है। इसके अलावा भी दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है।

झारखंड के देवघर के करौं में जनसभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य में पांच साल में काफी विकास हुआ है। यही कारण है कि यह राज्य देश के विकासशील राज्यों में टॉप सेवन में स्थान प्राप्त किया है।

कांग्रेस पर किया प्रहार : कांग्रेस पर प्रहार करते हुए राजनाथ ने कहा कि एनआरसी का विरोध कांग्रेस क्यों कर रही है इसका अंदाजा उसे भी नहीं है, लेकिन देश में एनआरसी लागू होगा यह तय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उन्माद की त्रासदी झेलने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान एनआरसी के तहत किया जाएगा।

तीसरे चरण में धुआंधार प्रचार, आज गरजेंगे पीएम मोदी और राहुल

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दो चरणों की 33 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब तीसरे चरण की सीटों की बारी है। इस चरण में राजधानी रांची तथा इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों सहित 17 सीटों पर 12 दिसंबर को मतदान होगा। इस चरण में भी कई हॉट सीटें हैं, जहां कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरे चरण में दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए महज दो दिन मिल रहे हैं। 10 दिसंबर को शाम में यहां चुनाव प्रचार थम जाएगा। सो, सोमवार को सभी बड़े-छोटे दलों के स्टार प्रचारक पूरा जोर लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बरही और बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे तो राहुल गांधी हजारीबाग और रांची में गरजेंगे।

तीसरे चरण में कुल 309 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 32 महिलाएं हैं, जबकि 99 निर्दलीय अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सबसे अधिक 31 उम्मीदवार ईचागढ़ तथा सबसे कम रांची और कांके में महज 12-12 हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो, मंत्री सीपी सिंह, नीरा यादव, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, जेपी पटेल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चरण के मतदान से जुड़ी हुई है।

रामगढ़ से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं, जिनके समक्ष अपने पति की परंपरागत सीट बचाए रखने की चुनौती है। इस चरण में चार सीटों रामगढ़, बड़कागांव, सिमरिया तथा कांके को छोड़कर सभी सीटों पर वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस का शिवसेना से निकाह के बाद मुसलमानों का हो गया तीन तलाक : ओवैसी

▸ कांग्रेस व झामुमो को बताया मुस्लिम विरोधी, कहा– इनकी धर्मनिरपेक्षता केवल वोट के लिए

जागरण संवाददाता, बोकारो

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रमुख एवं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बोकारो विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिवनीडीह के कर्बला मैदान में ओवैसी के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे ही, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि महाराष्ट्र में जिस दिन कांग्रेस का शिवसेना से निकाह हुआ, उसी दिन देश के मुसलमानों ने कांग्रेस को 'तलाक तलाक तलाक' बोल दिया है। अब देश के मुसलमान जान लें कि उनके साथ कोई नहीं है। एक ओर दंगाई पार्टी है, तो दूसरी ओर मॉब लिंचिंग के पैरोकार।

उन्होंने कहा कि 70 वर्षों तक ओवैसी को यह कहकर रोका गया कि धर्मनिरपेक्ष वोट का विभाजन होगा। यही कहकर कांग्रेस सहित अन्य दल वोट लेते रहे हैं। 2019 के चुनाव में मुसलमानों ने भाजपा व मोदी को वोट नहीं दिया। दूसरी ओर, कांग्रेस व झामुमो के नेता हिंदुत्व की गोद में बैठ गए। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो की मदद से एनआइए कानून में संशोधन किया गया, तीन तलाक विधेयक पास किया गया, अनुच्छेद 370 हटाया गया, अब नागरिकता संशोधन बिल लाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को गिराने वाली शिवसेना की गोद में कांग्रेस व एनसीपी बैठ चुकी है। ये सारे दल केवल भाजपा के नाम पर मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मेरी सभा हो रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। पीएम इस बात का जवाब दें कि बोकारो के विस्थापितों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। ओवैसी ने रविवार को गिरिडीह जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। डुमरी में पार्टी प्रत्याशी अब्दुल मोबीन रिजवी तथा धनवार में मु. दानिश के पक्ष में सभा की। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, झाविमो, झामुमो सहित झारखंड की सभी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। मुसलमानों के साथ-साथ दलितों और आदिवासियों को अपने पक्ष में रिझाने का पूरा प्रयास किया। नागरिकता संशोधन बिल एवं एनआरसी का विरोध करने की अपील की।

असदुद्दीन ओवैसी फाइल

संप्रग होगा हाफ बाकी विपक्ष साफ : सुधांशु त्रिवेदी

राज्य ब्यूरो, रांची : भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के रुझानों को अपने पक्ष में बताते हुए विपक्षी दलों पर तंज कसा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड में चुनाव का परिणाम साफ है। संप्रग हाफ होगा, बाकी अन्य सभी विपक्षी दल साफ। न परिवार बचेगा, न हैसियत। त्रिवेदी रविवार को रांची में भाजपा के मीडिया सेल में पत्रकारों से मुखातिब थे।

सुधांशु त्रिवेदी ने संप्रग के शीर्ष नेताओं को पराजित सेनापतियों का समूह बताया। कहा, पराजित सेनापतियों का गठबंधन झारखंड को किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी पैतृक सीट हार कर अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। झारखंड के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पराजित हो चुके हैं। झारखंड में संप्रग सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, जबकि झाविमो अपनी हैसियत बचाने के लिए। सरकार बनाने के लिए केवल भाजपा चुनाव मैदान में है। त्रिवेदी ने कहा कि झामुमो का अविश्वसनीय रिकार्ड रहा है। सीएनटी-एसपीपी एक्ट का उल्लंघन कर उन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन हड़पी। एक दिन में 16-16 रजिस्ट्री कराईं। जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया गया। उनके दावे और कृतित्व में कितना अंतर है, इससे यह स्पष्ट है। ग्राम सभा को देने की जगह जगह बालू घाट बेचे, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया।

हम करते हैं देश गढ़ने की राजनीति, विपक्षी चाहते अस्थिरता : स्मृति

जागरण संवाददाता, धनबाद : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को झारखंड के बोकारो के पेटरवार, गिरिडीह के धनवार और रांची के टाटीसिलवे में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से लेकर झारखंड तक भाजपा की सरकार ने विकास की गंगा बहाई, बड़े फैसले लिए और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। विपक्षी दल झारखंड में स्थिर सरकार नहीं बनने देना चाहते, ताकि उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता रहे। रांची में कहा कि लोकतंत्र में वह ताकत है, जो धूल को भी कमल का फूल बना देती है। उन्होंने मतदाताओं को विरोधी दलों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि लक्ष्मी तीर-धनुष लेकर नहीं, बल्कि कमल के फूल पर सवार होकर आती हैं। गिरिडीह के धनवार में ईरानी ने यहां वामपंथी संगठन भाकपा माले पर प्रहार करते हुए कहा कि वामपंथी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। ये जाति और धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करते हैं।

उप चुनाव के परिणाम तय करेंगे कर्नाटक में भाजपा सरकार का भविष्य

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में चार माह पुरानी बीएस येदियुरप्पा की अगुआई वाली भाजपा सरकार का भविष्य सोमवार को स्पष्ट हो जाएगा। राज्य में जिन 15 सीटों पर उप चुनाव कराए गए हैं, उनकी मतगणना सोमवार को कराई जाएगी। पांच दिसंबर को हुए मतदान में 67.91 फीसद मतदाताओं ने वोट डाले थे। 11 केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम सामने आ जाएगा। चुनाव अधिकारी ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी।

कांग्रेस और जद(एस) के 17 विधायकों के विद्रोह के बाद जुलाई में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी और भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिला। अयोग्य ठहराए गए इन्हीं विधायकों द्वारा खाली की गई सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं। 15 में से 12 पर कांग्रेस विजयी हुई थी जबकि तीन सीटें जद(एस) खाते की हैं। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को इनमें से कम से कम छह सीटों की दरकार है। हाई कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण विधानसभा में दो सीटें अभी तक खाली हैं। इन सीटों के लिए उपचुनाव नहीं कराया गया है।

वर्तमान में भाजपा के पास एक निर्दलीय समेत 105 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 66 और जद(एस) के पास 34 विधायक हैं। सदन में बसपा का एक और एक मनोनीत सदस्य हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा समेत सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पांच लोगों के एक जगह पर जमा होने और कानून एवं व्यवस्था में व्यवधान करने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सरकार के कार्यकाल पूरा करने का विश्वास जताया है। मतगणना की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी 13 सीटों पर विजय हासिल करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस और जद(एस) को भरोसा है कि अयोग्य ठहराए गए बागियों को जनता नकार देगी। ये सभी अभी सत्ताधारी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। भाजपा ने 16 अयोग्य विधायकों में से 13 को मैदान में उतारा है। उन सभी को वहीं से प्रत्याशी बनाया गया है जहां से वे 2018 के चुनाव में जीतकर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है।

ओडिशा में विधायक के घर ताला जड़कर कार आग के हवाले की

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : ओडिशा में अराजकतत्वों ने तालचेर विधायक ब्रजकिशोर प्रधान के घर में बाहर से ताला जड़कर उनके कैंपस कार्यालय में खड़ी उनकी कार को आग के हवाले कर दिया। इस मामले की शिकायत होने पर विक्रमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक, शनिवार देर रात को विधायक ब्रजकिशोर प्रधान विक्रमपुर थाना अंतर्गत नंदिरा गांव में मौजूद कैंप हाउस में सो रहे थे। उसी समय कुछ अराजकतत्व वहां पहुंचे और उनके घर के बाहर के दरवाजे में ताला जड़ दिया। इसके बाद उनके गैरेज में रखी कार को आग के हवाले कर दिया। इस बात की जानकारी विधायक के सहयोगियों को हुई तो वे मौके पर पहुंचे और घर का ताला खोलकर विधायक को बाहर निकाला। इस घटना में विधायक की कार जलकर खाक हो गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले 19 अगस्त को भी विधायक ब्रज किशोर प्रधान के भुवनेश्वर स्थित आवास में मौजूद दो कार एवं मोटरसाइकिल में अराजकतत्वों ने आग लगा दिया था।

बीरभूम तिहरे हत्याकांड में मुकुल रॉय को नौ साल बाद बनाया गया आरोपित

▸ भाजपा नेता ने ममता पर लगाया प्रतिशोध की सियासत करने का आरोप

▸ तृणमूल महासचिव ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, पुलिस कर रही है निष्पक्ष जांच

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल स्थित बीरभूम के लाभपुर में 2010 में हुई तीन भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को बोलपुर कोर्ट में पूरक चार्जशीट पेश की। इसमें विधायक मनीरुल इस्लाम और भाजपा नेता मुकुल रॉय समेत कुल 23 लोगों के नाम शामिल हैं। हाई कोर्ट ने जिला पुलिस को तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर दोबारा 16 नवंबर, 2019 से मामले की जांच में जुटी जिला पुलिस ने चार्जशीट में भाजपा नेता मुकुल रॉय व विधायक मनीरुल इस्लाम का नाम इसमें जोड़ा है। हालांकि, मामले में मुकुल का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। साथ ही राज्य सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लग रहा है। मामले में नाम सामने आने को भाजपा नेता मुकुल रॉय ने इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सियासी प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है तो वहीं तृणमूल महासचिव व राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका दावा है कि पुलिस निष्पक्ष हो जांच कर रही है और फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है।

मुकुल रॉय फाइल

आरोप है कि 2010 में माकपा समर्थक कटन शेख व जरीना बीबी के तीन बेटों को मनीरुल इस्लाम द्वारा उनके निवास पर आयोजित सालिसी सभा में बुलाया गया था, जहां उनकी पीट-पीटकर हत्या के उपरांत मौके पर बमबाजी की गई थी। उस दरम्यान फारवर्ड ब्लॉक के पूर्व नेता मनीरुल इस्लाम तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष थे। इधर, घटना के बाद मृतक माकपा समर्थकों के स्वजनों ने मनीरुल समेत कुल 42 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में हत्या का आरोप दर्ज कराया था और मामले पुलिस ने मनीरुल को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद तृणमूल की टिकट पर चुनाव जीतने के उपरांत 2014 में उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ मृतकों के स्वजनों ने न्याय को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कोर्ट के निर्देश पर दोबारा मामले की जांच में जुटी जिला पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसमें मनीरुल के साथ ही भाजपा नेता मुकुल रॉय के नाम को भी शामिल किया गया है।

मप्र में कारतूस फैक्ट्री लगाएगा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप

नईदुनिया, भोपाल

400 करोड़ के निवेश को लेकर बुधवार को होगा फैसला

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कारतूस की (आयुध) फैक्ट्री लगा सकता है। इसके लिए ग्रुप की एक कंपनी ने 400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश का उद्योग विभाग कंपनी को शिवपुरी में जमीन भी दिखा चुका है। इस पर 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली निवेश प्रोत्साहन कैबिनेट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा इजरायल की कंपनी एवगोल 1200 करोड़, बैकमेट 900 करोड़, केजेएस सीमेंट 350 करोड़ और रमणीक पॉवर के 200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

शिवराज सरकार में अंबानी ने खींच लिए थे हाथ : अनिल अंबानी ने शिवराज सरकार के वक्त भी मप्र में रक्षा क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन सरकार ने इसे हाथों-हाथ लेकर जमीन सहित अन्य सुविधाएं देने का निर्णय भी कर लिया था लेकिन उन्होंने हाथ खींच लिए थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने अब फिर इसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने की पहल की है। इसने राज्य सरकार से कहा है कि केंद्र ने रक्षा खरीद नीति बदल दी है, इसलिए अब परिस्थितियां अनुकूल हैं। वह मप्र में आयुध कारखाना लगाने चाहता है, जिस पर 400 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

एवगोल व बैकमेट पीथमपुर में प्लांट लगाने की इच्छुक : इजरायल की एवगोल कंपनी डायपर में उपयोग आने वाला कपड़ा बनाती है। वह मप्र में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके लिए कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर पीथमपुर में जमीन भी देख ली है। सरकार कंपनी को जमीन देने पर सहमत है। कंपनी को निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली सहायता पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं, पैकेजिंग मैटेरियल बनाने वाली कंपनी बैकमेट पीथमपुर में 900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

हुनर हाट से रोजगार...

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को गुजरात के शहर अहमदाबाद में हुनर हाट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान एक स्टाल पर नकवी ने रबड़ी का जायका लिया। हुनर हाट कार्यक्रम में दक्ष दस्तकारों और शिल्पकारों द्वारा हाथों से तैयार उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। सरकार का दावा है कि हुनर हाट के जरिये लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर मिले हैं। यह सम्मान के साथ सशक्तीकरण का विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। प्रेट्र

आजम खां से पूछताछ करीबी ठेकेदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रामपुर

जौहर यूनिवर्सिटी में कोसी नदी की जमीन के मामले में अजीमनगर पुलिस ने रविवार को सांसद आजम खां से पूछताछ की। वहीं, शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद के करीबी ठेकेदार इस्लाम खां को गिरफ्तार कर लिया है।

जौहर यूनिवर्सिटी में नदी की जमीन को लेकर प्रशासन ने अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में भी याचिका दायर की गई, जिस पर एनजीटी ने नदी क्षेत्र से निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इस पर आजम खां सुप्रीम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया था।

पुलिस अब थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना करने में लगी है। रविवार शाम अजीमनगर थाने के एसएसआइ अनंगपाल मिश्रा ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर आजम खां से पूछताछ की। उनके बयान दर्ज किए। इस जमीन को लेकर आजम खां कहते रहे हैं कि सरकार से खरीदी है, जबकि प्रशासन ने रिपोर्ट में लिखा है कि जमीन नदी क्षेत्र की है और इसे किसी को नहीं दिया सकता है। यह जमीन परती भूमि बताकर आवंटित कराई गई है। वहीं, दूसरी ओर आजम खां के करीबी ठेकेदार इस्लाम खां को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ठेकेदार के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इन्हीं मामलों में आजम खां को भी नामजद किया गया है। इनमें भैंस चोरी, गाय चोरी, बकरी चोरी, मकान तोड़ने, जमीन कब्जाने, गैर इरादतन हत्या करने का भी आरोप है। पुलिस ने आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू घर भी दबिश दी, लेकिन वह घर पर नहीं मिले।

आजम खां फाइल

बदलाव की सुगबुगाहट

सुखबीर की प्रधानी में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं, वरिष्ठ नेता सुखदेव ढींडसा ने उनके नेतृत्व में काम करने से कर दिया था मना

बादल कमान संभालेंगे या सुखबीर ही रहेंगे प्रधान, फैसला 14 को

▸ बीते तीन सालों में तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं चढ़ पाया है पार्टी का ग्राफ

▸ पार्टी के स्थापना दिवस पर चलेगा पता– किसके पास रहेगी बागडोर

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

शिरोमणि अकाली दल में एक बार फिर से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो मौजूदा प्रधान सुखबीर बादल के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन बीते तीन सालों में तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी का ग्राफ चढ़ नहीं पाया है। इसलिए पार्टी में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कमान अब प्रकाश सिंह बादल को संभालनी चाहिए। 14 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर क्या एक बार फिर से पार्टी की बागडोर बादल संभालेंगे या सुखबीर को ही पार्टी का प्रधान चुना जाएगा, यह तो उसी दिन पता चलेगा।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के बाद पार्टी हाशिये पर चली गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बढ़ रहे रोष के बावजूद शिअद की जड़ें मजबूत न होने से पार्टी में इस बात की जोरदार चर्चा है कि प्रकाश सिंह बादल को फिर से प्रधान बनाया जाए और सुखबीर बादल कार्यकारी प्रधान के तौर पर काम करें।

प्रकाश सिंह बादल फाइल

सुखबीर बादल फाइल

विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सुखदेव सिंह ढींडसा, रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सेवा सिंह सेखवां जैसे नेताओं ने पार्टी का साथ यह कहकर छोड़ा था कि वे सुखबीर बादल की प्रधानगी में काम नहीं कर सकेंगे, उससे पार्टी और कमजोर हुई है। पार्टी का कोर पंथक वोट बैंक अभी तक वापस नहीं आया है। अपने सबसे करीबी साथी ढींडसा को मनाने की कोशिश तो खुद प्रकाश सिंह बादल ने भी की थी। वह उनके घर भी गए, लेकिन ढींडसा ने साफ तौर पर कह दिया कि वह सुखबीर के साथ काम नहीं कर सकते। ब्रह्मपुरा व सेखवां जैसे नेताओं को बिक्रम मजीठिया के पार्टी में बढ़ते दबदबे से नाराजगी है। इसीलिए वे पार्टी में अब तक नहीं लौटे हैं। इन नेताओं ने तो सुखबीर बादल की प्रधानी को सीधे तौर पर चुनौती भी दी थी।

बादल को इसलिए फिर प्रधान बनाना चाहते हैं नेता : प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। बादल रविवार को 93 साल के हो गए, लेकिन उन्हें फिर से पार्टी प्रधान बनाने की चर्चाओं से साफ है कि आज भी पार्टी उनके नाम पर ही टिकी हुई है। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि सुखबीर का फिर से प्रधान बनना तय है। साथ ही पार्टी में यह चर्चा भी है कि अगर प्रकाश सिंह बादल कमान संभाल लेते हैं तो 2022 में पार्टी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। पहले विधायक अपनी सरकार की कारगुजारी से नाराज थे, लेकिन अब मंत्री भी कैबिनेट की बैठकों में खुलकर बोलने लगे हैं। तीन दिन पहले हुई बैठक में तीन मंत्रियों ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे।

ढींडसा व ब्रह्मपुरा क्या बनाएंगे नया दल? : अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रकाश सिंह बादल फिर से कमान संभालते हैं तो ढींडसा व ब्रह्मपुरा जैसे नेता क्या पार्टी में लौटेंगे या फिर वे 14 दिसंबर को ही किसी नए अकाली दल का गठन करेंगे। शनिवार को चंडीगढ़ में पूर्व स्पीकर रवि इंद्र सिंह के आवास पर ढींडसा की रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा और कई अन्य नेताओं से मीटिंग के बाद तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि बीते विधानसभा चुनाव से पहले ब्रह्मपुरा शिअद से अलग होकर अकाली दल टकसाली का गठन कर चुके हैं।

पूर्व सीएम बादल ने तीन बार केक काटकर मनाया 94वां जन्मदिन

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब : शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रविवार को अपना 94वां जन्मदिन तीन बार केक काटकर मनाया। सुबह 11 बजे के बाद उनके घर में लोगों का आना शुरू हुआ। पहले गांव बादल के दशमेश स्कूल के बच्चे उनके घर पहुंचे। बादल ने उनके साथ केक काटा और बच्चों की बधाई स्वीकार की। इसके बाद पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, दलजीत सिंह चीमा और अन्य नेता भी बादल को बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घर में ही नेताओं के साथ केक भी काटा। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ तीसरी बार केक काटा और सभी का धन्यवाद किया।

पूर्व सीएम बादल ने अपनी सेहत का राज सबके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर आदमी लंबी आयु चाहता है तो वह बिना काम के न रहे। नशे से दूर रहे।

लापरवाही की लपटें

59 लोगों की जान गई थी उपहार सिनेमा अग्निकांड में। 13 जून, 1997 को 'बॉर्डर' फिल्म देख रहे थे लोग

17 लोगों की मौत हो गई थी करोलबाग स्थित होटल अर्पित पैलेस में 12 फरवरी 2019 को लगी आग में

आह भी न भर सके, धुएं ने सुला दी मौत की नींद

सो रहे लोगों को नहीं मिला भागने का मौका

अग्निकांड में इन 22 मृतकों की हुई पहचान

मृतक	स्थान (बिहार)
अफसाद (28 वर्ष)	नौहट्टा, सहरसा
समीर (23 वर्ष)	समस्तीपुर
अकबर(12 साल)	हरीपुर, समस्तीपुर
छेदी (18 साल)	हरीपुर, समस्तीपुर
समीउल्लाह (18 साल)	हरीपुर, समस्तीपुर
साजिद (23 वर्ष)	समस्तीपुर
सजीमुद्दीम (55 वर्ष)	नरियार, सहरसा
मो. ग्यासुद्दीन (19 साल)	समस्तीपुर
साकिर (28 साल)	गांव मलमल, मधुबनी
तौकीन (22 साल)	समस्तीपुर
राजू (24 वर्ष)	समस्तीपुर
जाहिद (31 वर्ष)	अररिया
ऐजु (19 वर्ष)	अररिया
अंसार (18 वर्ष)	अररिया
सदरे आलम (26वर्ष)	हरिपुर, समस्तीपुर
महबूब (13 वर्ष)	ब्रह्मपुरा , जिला समस्तीपुर
मुहम्मद अताबुल (17 वर्ष)	समस्तीपुर
बब्लू (24 वर्ष)	उपरौली, जिला मुजफ्फरपुर

उत्तर प्रदेश के मृतकों की सूची

मृतक	स्थान
इकराम (35 वर्ष)	मुरादाबाद
इमरान (40 वर्ष)	मुरादाबाद
समीर (18 साल)	मुरादाबाद
मुशर्रफ (30 वर्ष)	गांव माई टांडा, बिजनौर

शुजाउद्दीन ● नई दिल्ली

फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कब फैक्ट्री को चपेट में ले लिया कर्मचारियों को पता ही नहीं चला। जिनकी आंख खुली उन्होंने मौत को सामने देखा और जो सोते रहे वह आह किए बिना ही दुनिया को अलविदा कह गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी जद्दोजहद की लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उनके कोशिशें नाकाम हो गईं और 43 लोगों की जान चली गई।

घटना के वक्त मौके पर मौजूद एक फैक्ट्री मालिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री की मशीन ठीक करनी थी। इस वजह से रविवार की सुबह तड़के ही उठ गए थे। उन्होंने बताया कि मशीन ठीक करने के बाद जब वह औजार लेकर गली में निकले तो रेहान की फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से चिंगारी निकलती देखी। इसके बाद भू-तल पर लगे बिजली के मीटर पर शॉट सर्किट होने लगा। नीचे फैक्ट्री का गेट खुला था। वह तुरंत फैक्ट्री भागकर गए और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और तीसरी मंजिल पर जाकर आग बुझाने लगे। लेकिन, सिलेंडर कम पड़ गए, इसके बाद उन्होंने आस पड़ोस की फैक्ट्रियों से 10 सिलेंडर जमा किए और आग बुझाई। लेकिन, प्लास्टिक और कपड़े के कारण आग बढ़ती चली गई। इसके बाद उन्होंने प्लास से बिजली के मीटर से तार काटे, ताकि आग ज्यादा न बढ़ सके।

पांच मिनट पहले ही निकले थे दो पुलिसकर्मी: शनिवार रात को अनाज मंडी स्थित फैक्ट्रियों में काम चल रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है, उसके बराबर वाली फैक्ट्री को निगम ने सील करने का नोटिस दिया हुआ है। उस फैक्ट्री से रात में क्रेन की सहायता से मशीनें उतारी जा रही थीं। तड़के 4:45 पर आग लगने से करीब पांच मिनट पहले ही दो पुलिसकर्मी गश्त करते हुए वहां से गुजरे थे। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से कहा कि यहां क्रेन लगाना गैरकानूनी है। इसके बाद फैक्ट्री मालिक से सेटिंग होने के बाद वह चुपचाप वहां से खिसक गए। उनके जाने के पांच मिनट बाद ही फैक्ट्री में आग लग गई।

गैंग ऑफ वासेपुर की तरह चलता है यहां कुरैशियों का 'राज' : नाज मंडी का दूसरा रास्ता कुरैश नगर से आता है, जिस तरह से फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में कुरैशियों का राज चलता है, ठीक इसी तरह से यहां इनका दबदबा है। अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियां, जिनकी जमीन पर चल रही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस व निगम के अफसर भी कतराते हैं। रविवार को ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। दरअसल कुरैशनगर के दूसरे रास्ते पर 10 से 12 लोग हाथ में डंडे लेकर चौकीदारी कर रहे थे, ताकि अवैध फैक्ट्रियों की पोल खुलने से बच जाएं। इन दबंगों का काम मीडिया व अन्य लोगों को घटनास्थल तक पहुंचने से रोकना था।

ग्राउंड रिपोर्ट...

- तीसरी मंजिल पर हुआ था शॉर्ट सर्किट फिर मीटर में लगी थी आग
- पड़ोसी ने 11 छोटे गैस सिलेंडरों से की आग बुझाने की कोशिश

फिल्मिस्तान सिनेमा हाल के पास अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में लगी आग से 43 लोगों के मारे जाने की खबर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मी तथा स्थानीय लोगों की भीड़ व लगी एंबुलेंस की लाइन ● ध्रुव कुमार

घर-घर में फैक्ट्री, शनिवार को भी लगी थी आग

अनाज मंडी, बाड़ा हिंदू राव, कुरैश नगर सहित आसपास के इलाके का शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां अवैध फैक्ट्री न चल रही हो। स्थानीय निवासियों के मुताबिक शनिवार को दिन में कुरैशनगर की एक फैक्ट्री के तीसरे मंजिल पर आग भी लगी थी। उन्होंने बताया कि कपड़ा, गत्ता, टोपी , खिलौना सहित कई तरह की फैक्ट्रियां यहां पर चल रही हैं। यहां के लोगों ने बताया कि फैक्ट्री चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, सारी फैक्ट्रियां अवैध हैं। इन्हें चलाने के लिए पुलिस और निगम के अधिकारियों से सेटिंग करनी पड़ती है।

मोर्चरी के बाहर मृतकों की फोटो देख रो पड़े परिजन

जासं, नई दिल्ली : भोर में हादसे का पता लगा, सुबह से तलाश शुरू हुई। लेकिन, यह ऐसी तलाश थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। सुबह से यहां से वहां अपनों की तलाश दोपहर बाद करीब पौने तीन बजे उनकी मौत की खबर के साथ खत्म हुई। दिन भर यह इंतजार था कि कहीं से घायल होने की खबर मिलेगी, लेकिन दोपहर बाद पौने तीन बजे जब एलएनजेपी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जब एक पुलिसकर्मी ने अग्निकांड में जान गंवा चुके लोगों की फोटो मोबाइल पर दिखानी शुरू की तो परिजनों की आंखें नम हो गईं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले मृतकों के परिजन को फोन पर सूचना देने के दौरान भी लोग फफककर रो पड़े।

अपनों की तलाश में भटकते रहे लोग

लोकेश चौहान ● नई दिल्ली

आग लगने की जानकारी मिलने पर जो जैसे था, जिस हाल में था, उसी हाल में घर से अपनों की तलाश में निकल गया। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, कभी वार्ड तो कभी इमरजेंसी तो कभी मोर्चरी के चक्कर लगाकर लोग अपनों की खैर-खबर लेने के लिए दौड़ रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर तो लोगों को वार्ड में जाने दिया न ही इमरजेंसी में। मोर्चरी के गेट के बाहर तक लोगों की तलाश सीमित रह गई। दिन भर लोग आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए यहां से वहां तक दौड़ते रहे, लेकिन हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजन और रिश्तेदारों को किसी भी प्रकार की जानकारी देने की सूचना पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई। हालत यह थी अस्पतालों में आपस में भी कोई सामंजस्य नहीं था। किसी भी अस्पताल में कोई हेल्प डेस्क की व्यवस्था नहीं की गई। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी नहीं किया गया, जिससे परिजन को अपनों के बारे में कोई जानकारी मिल सके।

रविवार को ओपीडी के बंद होने के कारण लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में वार्ड और इमरजेंसी में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया गया, जिनके पास कार्ड थे या जो आपात स्थिति में इलाज के लिए आए थे। इसके अलावा किसी भी अन्य को प्रवेश नहीं करने दिया गया। इससे एक तरफ अपनों की खबर लेने की बैचेनी और दूसरी तरफ उन्हें अस्पताल से कोई जानकारी न मिलने के कारण लोग परेशान रहे। जिस वार्ड में घायलों का इलाज किया जा रहा था, वहां गार्डों को तैनात किया गया, जिससे कोई भी वार्ड तक न पहुंच सके। वहीं इमरजेंसी के बाहर भी गार्ड और पुलिस को तैनात कर दिया गया था। अस्पताल के मुख्य भवन में जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक दिया गया।

छुट्टी के दिन भी इलाज में जुटे रहे चिकित्सक: सुबह के समय एलएनजेपी अस्पताल में अचानक से एक-एक करके शव और घायलों का पहुंचना शुरू हो तो छुट्टी के दिन चिकित्सक और अन्य स्टॉफ को भी बुलाया गया। इसके बाद चिकित्सकों की टीम इलाज में जुट गई।

अनाज मंडी में चल रही अवैध फैक्ट्री में लगी आग में फंसे अपनों की तलाश में लोकनायक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर शव की शिनाख्त करने के लिए परेशान परिजन ● संजय

मौत से पहले मुशर्रफ के मन में थी कर्ज उतारने की कसक

जैनुद्दीन ● बिजनौर

चारों तरफ आग की भयानक लपटें और धुआं। दम घुट रहा था और मौत सामने थी। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में मुशर्रफ को चिंता थी तो बस यह कि वह सिर पर पांच हजार का कर्ज लेकर दुनिया से रुखसत होगा। आग में बुरी तरह झुलसे मुशर्रफ ने अपने दोस्त को फोन किया था। यह उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल थी, जो उसके दोस्त के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। करीब साढ़े पांच मिनट के इस ऑडियो में अधिकांश मुशर्रफ की टूटती सांसों की आवाजें हैं। इस ऑडियो में साफ है कि दर्द से कराह रहा मुशर्रफ अपनी मौत को सामने देख रहा है। इसीलिए वह दोस्त से अपने सिर से कर्ज का बोझ उतारने को कहता है। उप्र के बिजनौर स्थित नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव टांडा माईदास निवासी 30 वर्षीय मुशर्रफ दिल्ली के अनाज मंडी इलाके की उसी फैक्ट्री में काम करता था, जहां रविवार सुबह भीषण अग्निकांड हुआ। वह वहां दस साल से बैग बनाने का काम कर रहा था। फैक्ट्री में आग से घिरे मुशर्रफ ने ग्राम प्रधान के पति फुरकान और अपने दोस्त शोभित अग्रवाल को फोन किया था। शोभित से मुशर्रफ की पांच मिनट 36 सेकंड बात हुई। उसने शोभित से कहा कि वह चारों ओर से आग से घिर गया है। उसकी सांस अटक रही है। आग से निकला नहीं जा सकता। अभी तक दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुंची है। उसने दिल्ली के रहने वाले मोनू के खुद पर पांच हजार रुपये उधार बताए। उसने शोभित से कहा कि मोनू के पैसे लौटा देना। शोभित उसे दिलासा दे रहा है कि वह बच जाएगा। वह ऐसी बातें न करे। ऑडियो में मुशर्रफ की सांसों की डोर टूटने की आवाजें हैं।

मुशर्रफ की फाइल फोटो। ● (सौजन्य से स्वजन)

हौसले और जज्बे से दी मौत को मात

विनीत त्रिपाठी ● नई दिल्ली

धुएं के गुबार से मेरी सांसें फूल रही थी। हर सेकेंड मौत मेरी सांसों की परीक्षा ले रही थी और मैं दो घंटे तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता रहा। कमरे के बगल से आ रहीं आग की लपटें बदन को झुलसा रही थीं और कमरे में भरा धुआं डरा रहा था। खिड़की के किनारे मुंह पर कपड़ा रखकर दो घंटे तक मैं हौसले के जान बचाने के लिए चीखता, चिल्लाता और लड़ता रहा। इसी बीच वहां पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मुझे पकड़कर कमरे से बाहर निकाला। वह मुझे खींच रहे थे, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मुझे लेकर जब वह नीचे आ रहे थे, उसी समय मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और अर्द्धबेहोशी की हालत में मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे दमकल विभाग की गाड़ी के पास आकर गिर गया। होश आने पर मैं कुछ दूर जाकर बैठ गया और बहुत देर तक फैक्ट्री को देखता रहा। इसके बाद जब मेरी जान में जान आई तो खुद वहां से चलकर नबी करीब में रहने वाले चाचा मुहम्मद के घर पहुंच गया। यह दास्तां सुनाई है मुहम्मद अफजल ने जो कि फैक्ट्री की आग में घिर गए थे।

मुहम्मद अफजल (22) बताते हैं कि फैक्ट्री में लगी आग की वह भयावह तस्वीर रह-रहकर उनकी आंखों के सामने घूम रही है। बिहार के जिला मधुबनी के छवराई गांव निवासी अफजल अपने चाचा के साथ लेडी हॉर्डिंग अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे थे। एक सप्ताह पहले ही वह काम करने के लिए यहां आया था। वह आग लगने वाली इमारत के दूसरे हिस्से की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में 10 से 11 लोगों के साथ रहते थे। वह सुबह 9 बजे से लेकर देर रात 12 बजे तक टोपी बनाने का काम करते थे। शनिवार रात भी 12 बजे वह काम करके कमरे में सो गए थे। सुबह करीब पांच बजे जब आंख खुली तो पूरे कमरे में धुएं का गुबार था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बचाने की गुहार लगाने लगा। वहां भी उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो कपड़े मुंह पर लगा लिए। करीब दो घंटे तक वह धुएं के बीच फंसा रहा। आखिरकार वहां पहुंची दमकल की टीम ने उन्हें निकाला। टीम उन्हें निकाल रही थी, जहरीले धुएं के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इसी बीच हाथ आग में लाल हो चुके एक लोहे पर पड़ा और उसका दायां हाथ जल गया। अफजल का कहना है कि उसे नहीं पता उसके साथ सोने वाले अन्य लोग अभी कहां हैं और उनकी हालत क्या है।

आंखों देखी

- फैक्ट्री में दो घंटे तक आग से जूझने वाले मुहम्मद अफजल ने बताई दास्तां
- जहरीले धुएं से बचने के लिए कपड़े से ढक लिया था मुंह, दमकलकर्मियों ने बचाई जान

दिल में था डर और लब पर दुआएं

अनहोनी का डर तो दिल में था, लेकिन लब पर दुआएं भी थीं कि अपने किसी को कुछ भी न हुआ हो। लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी)अस्पताल के बाहर जमा लोगों को दोपहर तक अस्पताल में भर्ती और मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसे में परिजन और रिश्तेदारों का दिल डर से बैठा जा रहा था। खुदा अपनों की हिफाजत करे, ऐसी दुआएं लोगों के लबों पर थीं।

दम घोंटू है कार्बन मोनोऑक्साइड

दिल्ली के अनाज मंडी में लगी भयावह आग में ज्यादा लोगों की मौत दम घुटने से हुए। एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची तो उसने गैस डिटेक्टर की मदद से यह परीक्षण किया कि वहां कोई विषैली गैस तो मौजूद नहीं है। परीक्षण में उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी का पता चला। ठंडक के दिनों में अक्सर बंद कमरे में जलती अंगीठी के कारण लोगों के मौत की वजह यही गैस बनती है।

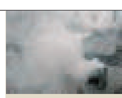

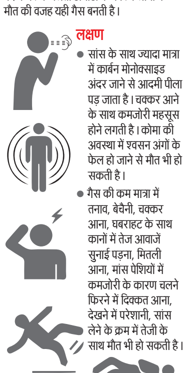

लक्षण

- सांस के साथ ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोक्साइड अंदर जाने से आदमी पीला पड़ जाता है। चक्कर आने के साथ कमजोरी महसूस होने लगती है। कोमा की अवस्था में श्वसन अंगों के फेल हो जाने से मौत भी हो सकती है।
- गैस की कम मात्रा में तनाव, बेचैनी, चक्कर आना, घबराहट के साथ कानों में तेज आवाजें सुनाई पड़ना, मितली आना, मांस पेशियों में कमजोरी के कारण चलने फिरने में दिक्कत आना, देखने में परेशानी, सांस लेने के क्रम में तेजी के साथ मौत भी हो सकती है।

ऐसे बनती है

जब गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं पाते तब सामान्यतौर पर यह गैस पैदा होती है।

जहरीली गैस

कार्बन मोनोक्साइड रंगहीन,गंधहीन और बहुत ही जहरीली गैस है। डीजल इंजन की गाड़ियों के एक्जास्ट में इस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसी भी तरह के ईंधन के जलने से यह गैस निकलती है। कोयले की अंगीठी से भी इस खतरनाक गैस का उत्सर्जन होता है।

कैसे लेती है जान

आदमी के रक्त में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीहीमोग्लोबिन के साथ मिलकर यह गैस कार्बोऑक्सीहीमोग्लोबिन तत्व का निर्माण करती है। यह तत्व खून में ऑक्सीजन को मिलने से रोकता है। जिसके कारण सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया बाधित होती है। ऐसी परिस्थिति में आदमी की मौत हो जाती है।

बचाव

- अंगीठी का प्रयोग करते समय खिड़की दरवाजे खोलकर रखें। कमरा गर्म होने के बाद अंगीठी बुझाकर सोएं।
- खड़े वाहनों में एसी चलाकर न छोड़ें। गाड़ी का शीशा खुला रखें।
- बुजुर्ग और सांस की दिक्कत वाले लोग खास सावधानी बरतें।
- पीड़ित को उस जगह से हटाकर खुली हवा में ले जाएं।

झकझोर देने वाले अग्निकांड

दिल्ली में अनाज मंडी अग्निकांड ने उन जख्मों को हरा कर दिया है, जो पिछले कई सालों से हमें सालते रहे हैं। देश ने ऐसे कई अग्निकांड देखे हैं, जिनमें लोगों ने अपनों को खोया है। हर अग्निकांड के बाद हम शोक व्यक्त करते हैं, मातम मनाते हैं, लेकिन उनसे सबक सीखे बिन अगली घटना का इंतजार करते हैं। अनाज मंडी अग्निकांड के साथ आगजनी की उन घटनाओं को याद करना जरूरी है जिन्होंने देश को झकझोर दिया था। हालांकि उसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्हें रोकने के लिए न हमारे पास पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही हम ऐसी घटनाओं से सबक सीख सकें हैं। पेश है देश के कुछ बड़े अग्निकांडों पर एक नजर:

- **स्टीफन कोर्ट, कोलकाता**: कोलकाता की ऐतिहासिक इमारत स्टीफन कोर्ट में 23 मार्च 2010 को आग लगने से 43 लोग मारे गए। इमारत में ऐसी परिस्थितियों में बाहर निकलने के लिए उचित इंतजाम नहीं थे।

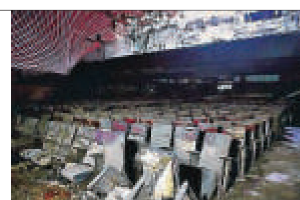

- **उपहार सिनेमा** : दिल्ली के ग्रीन पार्क में 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में फिल्म 'बॉर्डर' दिखाई जा रही थी। इसी दौरान सिनेमाघर में आग लग गई। आग लगने, भगदड़ में घायल होने और घुटन के कारण 59 लोगों की मौत हो गई और 103 लोग घायल हुए।

- **एएमआरआइ अस्पताल**: दक्षिण कोलकाता के धकुरिया में स्थित एएमआरआइ अस्पताल में 9 दिसंबर 2011 के दिन तड़के करीब 3 बजे आग लग गई। अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और बहुत तेजी से उसने अस्पताल की पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। सेंट्रल एसी सिस्टम के कारण पूरी इमारत में धुंआ फैल गया। इसके कारण दम घुटने से 95 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में स्टॉफ के लोग भी थे।
- **मेरठ, उत्तर प्रदेश** : मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल 2006 को 'ब्रांड इंडिया' मेले में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग में 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब डेढ सौ लोग झुलस गए थे।

- **कुंभकोणम स्कूल, तमिलनाडु**: तंजावुर जिले में स्थित कुंभकोणम के एक स्कूल में 16 जुलाई 2004 को भीषण आग लग गई। स्कूल की इमारत में नर्सरी, प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जा रहा था। हादसे में करीब 94 बच्चे मारे गए।
- **बरीपाड़ा, ओडिशा**: ओडिशा के बरीपाड़ा में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। 23 फरवरी 1997 को आग लगी और करीब दो सौ लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड में डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल भी हुए।
- **श्रीरंगम मैरिज हॉल, तमिलनाडु** : 23 जनवरी 2004 को श्रीरंगम के पद्मप्रिया मैरिज हॉल में एक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस अग्निकांड में दूल्हे सहित शादी समारोह के लिए आए 57 लोगों की मौत हो गई।
- **बिहार पटाखा फैक्ट्री**: बिहार के खुसरूपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में 15 सितंबर 2005 में हुए धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई और 72 लोग घायल हो गए। धमाका फैक्ट्री के गोदाम में हुआ जहां पर बड़ी संख्या में पटाखों को रखा गया था।
- **शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री, तमिलनाडु**: तमिलनाडु के शिवकाशी के निकट मुदालीपट्टी में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। 5 सितंबर 2012 को हुए हादसे में 54 लोगों की मौत हो गई और 78 लोग घायल हुए।

(सभी फाइल फोटो)

- **मंडी डबवाली, हरियाणा**: भारत के इतिहास का यह संभवतः सबसे बड़ा अग्निकांड है। 23 दिसंबर 1995 को हरियाणा के मंडी डबवाली में डीएवी स्कूल का वार्षिकोत्सव चल रहा था। शॉर्ट सर्किट के कारण पंडाल ने आग पकड़ ली और उसके बाद मची भगदड़ में 442 लोगों की मौत हुई। इनमें से 258 बच्चे थे। साथ ही करीब 150 लोग घायल हो गए थे।

20 भारतीय शहरों में होती है 81 फीसद आग दुर्घटनाएं

भारत में हर साल सामने आने वाली आग दुर्घटनाओं में बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए भी ये अग्निकांड बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इंडिया रिस्क सर्वे (आइआरएस) 2018 के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में बिना बाधा के किसी कारोबार संचालन में आग लगना तीसरा सबसे बड़ा खतरा है। 2016 में आगजनी की घटनाएं कारोबार के लिए आठवां बड़ा खतरा थीं।

उचित संसाधनों का अभाव: भारत में आगजनी से सुरक्षा के लिए नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया जाता है। साथ ही देश में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण तक नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने 2017 में संसद को तथ्यों के आधार पर बताया था कि हम अग्निशमनकर्मियों, आग बुझाने वाले यंत्रों और वाहनों की संख्या में आवश्यकता से काफी पीछे हैं। फिर भी हमारे अग्निशमनकर्मी जान हथेली पर रखकर जिंदगियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं।

- 2012 में देश में 2,987 अग्निशमन केंद्र मौजूद थे जबकि जरूरत 8559 केंद्रों की थी। इस तरह से उस वक्त 65 फीसद की कमी थी।
- देश को 5 लाख 59 हजार 681 अतिरिक्त प्रशिक्षित अग्निशमनकर्मियों की जरूरत है।
- 2 लाख 21 हजार 411 अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता है।
- 9337 अग्निशमन गाड़ियों और विशेष उपकरणों की आवश्यकता है।

एक दिन में 48 की मौत: एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया (एडीएसआइ) के 2015 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में आग दुर्घटनाओं में 17 हजार 700 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े के मुताबिक, हर दिन 48 लोगों की मौत आग दुर्घटनाओं में हो जाती है।

आगजनी की घटनाओं में उछाल

व्यावसायिक इमारतें: 2014 में 179 आग दुर्घटनाएं हुईं, वहीं 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 716 पहुंच गया। एक ही साल में यह 300 फीसद का इजाफा था। वहीं सरकारी इमारतों में खतरा 218 फीसद बढ़ा। इन इमारतों में 2014 में जहां महज 11 मामले सामने आए थे वहीं 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 35 हो गया।

रिहाइशी इमारतें: 2015 में 7 हजार 493 मामले सामने आए। 2014 के 3 हजार 736 मामले ही सामने आए थे। इस तरह से 2015 में आग दुर्घटनाओं में सौ फीसद का उछाल आया।

छोटे शहर बड़ा सिरदर्द: 2015 में इमारतों में आग लगने की 81 फीसद घटनाएं 20 शहरों में हुईं। इनमें 14 शहर मेट्रो शहर नहीं थे। देश के 53 मुख्य शहरों में आग के कारण सर्वाधिक मौतें कानपुर में 147, अहमदाबाद में 134 और बेंगलुरु में 132 दर्ज की गईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा को 2003-2004 में 14 हजार 500 कॉल आ रहे थे, वो 2015-16 में बढ़कर 27 हजार हो गए।

नहीं हैं आंकड़े: एडीएसआइ की 2015 में जारी रिपोर्ट आग दुर्घटनाओं और हादसों में मरने वालों का सबसे ताजा सरकारी आंकड़ा है। आग दुर्घटनाओं से सुरक्षा के आंकड़े 2012 में सामने आए थे। यह बताता है कि आग से होने वाले खतरों के प्रति हम कितने गंभीर हैं।

8.63 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है कश्मीर पैकेज के तहत। उद्योग व वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई। इसमें जम्मू संभाग के 4.64 करोड़ तथा कश्मीर संभाग के 3.99 करोड़ के सब्सिडी केस मंजूर किए गए।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 दिसंबर 2019

धनोआ के सम्मान में राफेल के टेल नंबर में होंगे 'बीएस' अक्षर

तैयारी ▸ सौदे को साकार करने में पूर्व वायुसेना प्रमुख की थी अहम भूमिका

छह राफेल प्रशिक्षक विमानों में 'टेल नंबर' में 'आरबी' श्रृंखला है

- फ्रांस की कंपनी दासौ एविएशन से 59 हजार करोड़ रुपये में 36 राफेल विमान खरीदने को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ है
- 36 राफेल विमानों में से छह विमान प्रशिक्षक हैं जबकि 30 विमान लड़ाकू हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र: वायुसेना ने अपने पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) बीएस धनोआ को सम्मान देते हुए 30 राफेल लड़ाकू विमानों के पिछले हिस्से पर 'टेल नंबर' में 'बीएस' लिखने का फैसला किया है, जो धनोआ के नाम के अक्षर हैं। अभी छह राफेल प्रशिक्षक विमानों में 'टेल नंबर' में 'आरबी' श्रृंखला है। यह मौजूदा वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के नाम के अक्षर हैं।

धनोआ ने राफेल विमान खरीद का करार कराने में वार्ताकार के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। फ्रांस की कंपनी दासौ एविएशन से 59 हजार करोड़ रुपये में 36 राफेल विमान खरीदने को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ है। यह विवाद धनोआ के वायुसेना प्रमुख रहने के दौरान अपने चरम पर था। हालांकि, उन्होंने मजबूती के साथ करार का बचाव किया था। उन्होंने हमेशा कहा कि करार बिल्कुल सही तरीके से हुआ है।

बीएस धनोआ। फाइल

पीटीआइ से वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रशिक्षक राफेल विमानों को छोड़कर सभी राफेल लड़ाकू विमानों के टेल नंबर में 'बीएस' अक्षर होंगे। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने हमें ये विमान दिलाने के लिए जो भूमिका निभाई है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहने का यह हमारा तरीका है।' 36 राफेल विमानों में से छह विमान प्रशिक्षक हैं जबकि 30 विमान लड़ाकू हैं। प्रशिक्षक विमान दो सीट वाले होंगे और उनमें लगभग वे सभी चीजें होंगी जो लड़ाकू विमानों में होंगी। ये राफेल विमान मिटियोर और स्काल्प मिसाइलों से लैस हैं।

41 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे धनोआ

धनोआ वायुसेना में अपनी 41 वर्षों की सेवा के बाद सितंबर में सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने कहा था कि करार में कुछ भी गलत नहीं हुआ और वायुसेना को अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विमानों की जरूरत है। राफेल विमान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। तीन राफेल विमान पहले भारत को सौंपे जा चुके हैं और फ्रांस में भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आठ अक्टूबर को फ्रांस में पहला राफेल विमान प्राप्त किया था। चार राफेल विमानों की पहली खेप मई 2020 तक भारत आ जाएगी।

भारतीय उपग्रहों को मलबे से सुरक्षित रखने वाले प्रोजेक्ट को 33 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों को मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित रखने वाले इसरो के 'प्रोजेक्ट नेत्र' के लिए 33.30 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव किया है। अनुदान की पूरक मांगों के दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान के लिए प्रस्ताव रखा था जिसे पिछले सप्ताह लोकसभा ने पारित कर दिया। सितंबर में भारत ने अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों एवं अन्य संपत्तियों के मलबे एवं अन्य वस्तुओं से सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नेत्र (नेटवर्क फॉर स्पेस आब्जेक्ट) लांच किया था। इस पर 400 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव की 50 वर्षों की अंतरिक्ष खोज ने पृथ्वी की कक्षा में कचरे की एक पट्टी बना दी है जो मानव निर्मित उपग्रहों के लिए खतरा है। भूस्थैतिक कक्षा में इस समय भारत के 15 संचार उपग्रह सक्रिय हैं। इसके अलावा निम्न भू कक्षा (2,000 किलोमीटर के दायरे) में 13 रिमोट सेंसिंग उपग्रह तथा पृथ्वी की मध्यम कक्षा में आठ नेविगेशन उपग्रह स्थापित हैं। इसके अलावा भी कई छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में मौजूद हैं।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमवाईएस प्रसाद ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति है और इस तरह की निगरानी क्षमता अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 17000 मानव निर्मित वस्तुएं अंतरिक्ष में निगरानी में हैं। इनमें से सात फीसद सक्रिय हैं।

श्रीनगर में हवाई सेवा पर कोहरा हावी तीसरे दिन भी सभी फ्लाइट रद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- यात्रियों को दरबदर होना पड़ रहा, नहीं आ रही कोई फ्लाइट
- शनिवार को 27 फ्लाइट तो गत शुक्रवार को 11 फ्लाइट रद हुई थीं

श्रीनगर में घने कोहरे का असर हवाई सेवा पर पड़ रहा है। लगातार तीसरे दिन रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी फ्लाइट रद कर दी गईं। वहीं, बाहर से भी कोई फ्लाइट नहीं आईं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रविवार को श्रीनगर एयरपोर्ट से 28 फ्लाइट रवाना होनी थी। कुछ फ्लाइट सेना के जवानों के लिए थी। कम रोशनी के कारण सभी फ्लाइट रद कर दी। कई यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन जानकारी मिलते लौटना पड़ा। शनिवार को श्रीनगर से उड़ने वाली 27 फ्लाइट रद कर दी गईं थी। गत शुक्रवार को 11 फ्लाइट रद हुई थीं, जिस कारण एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विस्तारा एयरवेज ने सभी यात्रियों से खराब मौसम के कारण श्रीनगर के लिए रद हुई फ्लाइटों के लिए क्षमा मांगी थी।

उनके अनुसार धुंध व पर्याप्त रोशनी न होने से दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली यूके-611 फ्लाइट और श्रीनगर से दिल्ली रवाना होने वाली यूके-612 को रद कर दिया। इंडिगो एयरलाइन ने भी यात्रियों से एयरपोर्ट रवाना होने से पूर्व फ्लाइट से संबंधित जानकारी हासिल करने की सलाह दी। बेंगलुरु से पत्नी के साथ श्रीनगर जा रहे नितिन ने कहा कि वह सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे।

इन्हें यहां से श्रीनगर के लिए फ्लाइट लेनी थी परंतु पता चला की खराब मौसम के कारण श्रीनगर की सभी फ्लाइट रद कर दी गई हैं। उन्हें श्रीनगर जाने का कार्यक्रम रद करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि घने कोहरे के कारण सभी फ्लाइट रद हो गईं।

जमने लगी डल झील, द्रास में पारा माइनस 26

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील जमने लगी है। जबकि लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास क्षेत्र में तापमान शून्य से 26 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। श्रीनगर में शनिवार की रात सबसे अधिक ठंडी रही। न्यूनतम तापमान माइनस चार डिग्री रहा। बढ़ती ठंड का असर डल झील पर भी हुआ और वह मामूली रूप से जमी हुई थी। घरों के नलों का पानी भी जमा हुआ था। पहलगाम में माइनस 6.3 डिग्री, गुलमर्ग में माइनस 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। जम्मू में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री और माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री से दर्ज किया गया।

अस्पताल से 28 दिन बाद घर आईं लता

मुंबई, प्रेट्र : भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर 28 दिन बाद अस्पताल से लौट आई हैं। भारत रत्न लता को 11 नवंबर को सांस में दिक्कत की शिकायत के बाद यहां के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद उन्हें न्यूमोनिया होने की बात सामने आई थी। रविवार को घर वापसी के बाद उन्होंने प्रार्थनाओं एवं शुभकामनाओं के लिए प्रशंसकों का धन्यवाद किया।

लता ने कहा, 'पिछले 28 दिन से मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। मुझे न्यूमोनिया हुआ था। चिकित्सकों की राय थी कि मुझे अस्पताल में कुछ समय रुकना चाहिए और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही घर जाना चाहिए। आज मैं माई-बाबा के आशीर्वाद से घर वापस आ गई हूं। मैं अपने शुभचिंतकों की हृदय से आभारी हूं। आपकी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं ने असर दिखाया। मैं आप सबको नमन करती हूं।' लता ने अपना इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया। 28 सितंबर, 1942 को जन्मी लता मंगेशकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं।

प्रशंसकों ने जताई खुशी : लता मंगेशकर के स्वस्थ होने और घर वापस आने की खबर के बाद प्रशंसकों में भी खुशी की लहर देखी गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, 'यह जानकर खुशी हुई कि आप स्वस्थ हैं। तुम जियो हजारों साल।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप हमेशा खुश रहें।'

न्यूज गैलरी

वडोदरा में नाबालिग से दुष्कर्म में दो गिरफ्तार

अहमदाबाद : वडोदरा में 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रविवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों की पहचान किशन मथासूर्या (28) और जासो सोलंकी (21) के रूप में की गई है। लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को 28 नवंबर को अंजाम दिया गया था। प्रेट्र

भाई की हत्या में महिला गिरफ्तार

मुंबई : जीजा की मदद से भाई की हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के आरोप में 29 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित रेशमा सुशील ओहाल ने पुलिस को बताया कि भाई देवेंद्र अखाड़े बेरोजगार था और शराब पीने का आदी था। इतना ही नहीं वह परिजनों को मारता-पीटता था। पिछले रविवार को जीजा की सहायता से देवेंद्र का गला घोंटने के बाद उसका शव चेंबूर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। प्रेट्र

बाइक सवार युवकों ने लूटा 50 किलोग्राम प्याज

गोरखपुर : गोरखपुर स्थित अलहदादपुर तिराहे पर रविवार दोपहर बाइक सवार युवकों ने रिक्शा चालक को धमकी देकर 50 किलोग्राम प्याज लूट लिया। राजघाट पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। रहमतनगर निवासी फिरोज अहमद राईन आलू-प्याज के थोक व्यापारी हैं। महेवा मंडी में उनकी दुकान है। कुशीनगर के जगदीशपुर का रहने वाला यमुना उनकी दुकान पर काम करता है। रविवार दोपहर एक बजे यमुना दुकान से रिक्शे पर सात बोरी प्याज लेकर गोलघर के एक होटल में आ रहा था। अलहदादपुर तिराहे के पास बाइक सवार दो युवकों ने रिक्शा रोका और यमुना को जान से मारने की धमकी देकर एक बोरी प्याज (50 किलोग्राम) लेकर पांडेयहाता की तरफ फरार हो गए। (जासं)

साध्वी प्राची ने पं. नेहरू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

मेरठ : अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली साध्वी प्राची एक बार फिर सीमाएं लांघ गईं। एक निजी कार्यक्रम में रविवार को मेरठ पहुंचीं साध्वी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह बयान कि आज देश दुष्कर्म की घटनाओं की राजधानी बन गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साध्वी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने देश में इस तरह के माहौल के लिए जवाहर लाल नेहरू को दोषी ठहराया। उन्होंने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। (जासं)

पुलवामा मुठभेड़ में वांछित चालक का आत्मसमर्पण

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पुलवामा के द्रबशाला में आतंकियों की मदद करने वाले वांछित चालक ने शनिवार रात को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उससे पूछताछ जारी है। 25 नवंबर को सुरक्षाबलों ने द्रबशाला में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों इरफान अहमद शेख और इरफान अहमद राथर को मार गिराया था। जांच में पता चला कि ये आतंकी किसी की मदद से द्रबशाला तक पहुंचे थे। वहां से चालक 34 वर्षीय मुजफ्फर अहमद निवासी अच्छन पुलवामा में अपने वाहन में बैठाकर आतंकियों को पुलवामा तक पहुंचाया। शनिवार देर शाम चालक ने स्वयं बीएसएफ महानिरीक्षक श्रीनगर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कुबूल किया कि उसने दोनों आतंकियों को पुलवामा पहुंचाया था। सूत्रों ने बताया कि वानी काफी देर से हिजबुल के लिए काम कर रहा है। इससे पहले वह आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का ओवर ग्राउंड वर्कर था। आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते उसे वर्ष 2010 में पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसने आठ महीने कठुआ जेल में सजा काटी है।

एनआइए ने दोदे नहर से बरामद किए पाकिस्तानी ड्रोन के पुर्जे

जागरण संवाददाता, तरनतारन

- पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगाने के मामले में 22 सितंबर को गिरफ्तार हुए थे चार आतंकी

पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगाने के मामले में पिछले चार दिनों से एनआइए तरनतारन में जांच कर रही है। एनआइए की टीम ने दोदे नहर से पाकिस्तानी ड्रोन के पुर्जे बरामद किए हैं। ये पुर्जे आतंकी रोमनदीप सिंह की निशानदेही पर बरामद किए गए।

कस्बा चोहला साहिब के समीप 22 सितंबर को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था कि पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से पंजाब में असलहा और गोला बारूद पहुंच चुका है। असलहा, गोला बारूद और जाली करंसी की बड़ी खेप के साथ पकड़े गए चारों आतंकियों के तार कस्बा झब्बाल निवासी रोमनदीप सिंह से जगजाहिर हुए थे।

रोमनदीप कहने को झब्बाल में आटा चक्की चलाता था, परंतु उस पर पंजाब में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की योजना बनाने वाले पाकिस्तान में बैठे केजेडएफ के मुखी आतंकी रंजीत सिंह नीटा का हाथ था। ड्रोन नष्ट करने के बाद रोमनदीप सिंह ने सारे मामले की जानकारी नीटा को फोन पर दी थी। शनिवार को गांव दोदे स्थित अपरबारी दोआब नहर में आठ गोताखोरों की टीम ने उस ड्रोन की बैटरी और अन्य पुर्जे बरामद किए, जो अगस्त में बंद राइस मिल में जलाने के बाद फेंके गए थे।

चार पूर्व आतंकियों के तार भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े : खडूर साहिब लिंक रोड पर चार सितंबर को हुए बम धमाके के मामले में एनआइए ने अब तक नौ आतंकी गिरफ्तार किए हैं। इनसे पूछताछ में कई ऐसे सुबूत सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि जिले से संबंधित चार पूर्व आतंकियों के तार पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मुखी रंजीत सिंह नीटा के साथ जुड़े हुए हैं। रविवार को एनआइए की टीम ने उन चारों पूर्व आतंकियों का रिकॉर्ड भी स्थानीय पुलिस से कब्जे में लिया। कहा जाता है कि इन चार पूर्व आतंकियों की कॉल डिटेल पाकिस्तान में सामने आई है।

सेना से जुड़ा हो सकता है इंसास राइफल चुराने वाला आरोपित

नईदुनिया, होशंगाबाद : मध्य प्रदेश के पचमढ़ी स्थित सेना शिक्षा कोर से गुरुवार रात तीन बजे दो इंसास राइफल, तीन मैगजीन और बीस कारतूस चुराने वाले आरोपितों में से एक सेना से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, एक आरोपित 2017-2018 में पचमढ़ी में प्रशिक्षण ले चुका है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। एसपी एमएल छारी ने बताया कि पिपरिया के एक एटीएम से रुपये निकालते समय मिले फुटेज से आरोपितों की पहचान हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, मामले में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। आर्मी इंटेलीजेंस, एटीएस व पुलिस की एक टीम पंजाब व हरियाणा में आरोपितों की तलाश कर रही है। वहीं, सेना के अधिकारी गेट पर तैनात जवानों से भी पूछताछ कर रहे हैं। मामले को लेकर सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण के अधिकारियों ने अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी है।

एडीजी आशुतोष राय ने बताया कि आरोपित वर्तमान में सेना का जवान है या नहीं, इसकी जानकारी उसके पकड़ में आने के बाद ही हो सकेगी। आरोपितों की तलाशी जारी है।

सीटेट में बिहार के छह सॉल्वर समेत 10 गिरफ्तार

- हर सॉल्वर को मिलने थे ढाई लाख रुपये, एडवांस में दिए गए थे 50 हजार
- दारोगा का बेटा है सरगना, पिछले साल भी हुआ था गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : एसटीएफ बरेली और मुरादाबाद पुलिस ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में 10 साल्वर दबोच लिए। ये अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। इनमें छह साल्वर बिहार के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना सचिन समेत छह लोग एसटीएफ को चकमा देकर भाग गए।

मुरादाबाद में रविवार को 52 परीक्षा केंद्रों पर सीटेट कराई गई। एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने बताया कि सुबह एसटीएफ बरेली के इंस्पेक्टर अजय कुमार यादव को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद जिले के थाना मझोला के डी-30 कांशीराम नगर कालोनी निवासी दारोगा डालचंद्र के बेटे सचिन राणा ने बिहार से सॉल्वर बुलाए हैं।

एसटीएफ ने पुलिस के साथ सबसे पहले हिंदू कॉलेज में छापा मारा। यहां से सुशांत सहगल और विक्की कुमार, इसके बाद आशियाना कालोनी के आरआरके स्कूल से मुकेश, मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज से चंदन आनंद, पाकबड़ा के वेदराम इंटर कॉलेज से राजमणि, कटघर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से चंदन को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा मुरादाबाद के नाजिम, दानिश, विपिन कुमार और अमरोहा के राजकुमार कश्यप को हिंदू डिग्री कॉलेज के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरोह में शामिल राजकुमार ने अपने लिए भी सॉल्वर बैठाया था। पकड़े गए लोगों के पास एक कार, बाइक, मोबाइल फोन, पहचान पत्र, एटीएम, चेकबुक, डाइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड मिले हैं।

> गिरोह का सरगना सचिन राणा 2018 में यूपी टेट के दौरान भी पकड़ा गया था। इस बार वह ढाई लाख रुपये में तय करके सॉल्वर लाया था। 50 हजार रुपये सभी को एडवांस में दिए गए थे। बाकी रकम आंसर शीट देखकर दी जानी थी। जिन लोगों के स्थान पर सॉल्वर परीक्षा दे रहे थे, उन्हें भी मुल्जिम बनाया जाएगा।
> **-अमित पाठक, एसएसपी, मुरादाबाद।**

सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता ने कहा, कभी नहीं आऊंगी रोहतक

जागरण संवाददाता, रोहतक

- राज्य मंत्री अनूप धानक के समर्थकों पर लगाए दरवाजा तोड़ने के प्रयास के आरोप

रोहतक के सर्किट हाउस में शनिवार रात हुई घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ता ने खुद की जान को खतरा बताया है। उनका कहना है कि हरियाणा में महिलाओं को ऐसा सम्मान मिलता है यह कभी सोचा भी नहीं था। अब वह कभी रोहतक में नहीं आना चाहेंगी। उन्होंने पुलिस पर भी पक्षपात के आरोप लगाए हैं। क्योंकि शिकायत के बाद भी एफआइआर दर्ज नहीं की गई। वहीं पुलिस का तर्क है कि महिला अधिवक्ता को गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

मूलरूप से पंजाब के मोहाली की नवरत्न चौधरी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। शनिवार को वह पीजीआइ में दांत का इलाज कराने के लिए आई थी। शाम चार बजे का अप्वाइंटमेंट था। देर होने के कारण उन्होंने सर्किट हाउस में कमरा लेकर वहीं रुकने का फैसला किया। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि रात करीब 10 बजे कुछ लोगों ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने बामुश्किल अपनी जान बचाई। महिला अधिवक्ता ने यह आरोप हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक के लोगों पर लगाया है। इस मामले को लेकर देर रात तक सर्किट हाउस में हंगामा चलता रहा, जिसके बाद उन्होंने लिखित में पुलिस को शिकायत दी थी। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि उन्होंने रात में एसपी को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। ऐसे में कैसे महिलाओं को सुरक्षित कहा जा सकता है। महिला अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने लिखित शिकायत लेकर केस दर्ज नहीं किया। एफआइआर के इंतजार में शाम तक रोहतक में रुकना पड़ा। रात में भी डर की वजह से नहीं सो सकी। आरोप लगाया है कि उन पर समझौते के लिए दबाव डाले जा रहे हैं और सर्किट हाउस से भी जबरदस्ती कमरा खाली करा लिया गया।

पुलिस का तर्क, ली जाएगी कोर्ट से राय: पुलिस का कहना है कि शिकायत ले ली गई है, लेकिन अभी तक की जांच में आया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान भी हो चुकी है। वह भी सर्किट हाउस में रुके हुए थे। उन्होंने ही गलती से दरवाजा खटखटा दिया था।

मोक्षदा एकादशी का अनुष्ठान

उत्तर प्रदेश में मंदिरों की पावन नगरी वाराणसी में रविवार को गंगा नदी के राजा घाट पर मोक्षदा एकादशी के अवसर पर अनुष्ठान करते श्रद्धालु। विष्णु पुराण के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेट्र

छत्तीसगढ़ में जमानत पर छूटे आरोपित ने युवती को मार डाला

नईदुनिया, कोरबा : उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाने की खबरों के बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। कोरबा के बुधवारी बस्ती में रहने वाली 32 साल की एक महिला की सिरफिरे प्रेमी ने जमानत पर छूटने के बाद हंसिया से हत्या कर दी। दो दिन तक जीवन के लिए जूझ रही युवती ने रविवार को दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मूलतः मुंगेली के लोरमी की रहने वाली 32 वर्षीय युवती को उसके पति ने त्याग दिया था। वह इन दिनों कोरबा के बुधवारी बस्ती में रहती थी। पुलिस के अनुसार लोरमी में ही रहने वाले इंद्रपाल टोंडे (40) पुत्र श्यामसुंदर से उसकी पुरानी जान पहचान थी। वह भी पत्नी से अलग रह रहा था। इंद्रपाल महिला से एक तरफा प्यार करने लगा। चोरी छिपे उसने महिला की नहाते समय वीडियो बना ली और दबाव बनाने लगा। युवती के न मानने पर उसने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर दिया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इंद्रपाल को पखवाड़ा भर पहले जेल भेजा था। दो दिन पहले जेल से जमानत पर छूटने पर उसने हंसिया से वार कर युवती की हत्या कर दी।

मप्र में फिर लागू होगा जिला सरकार मॉडल

तैयारी

उमा भारती सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा विभागों की 36 अधिसूचनाएं की थीं निरस्त, जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या हर जिले में होगी 20

भोपाल, स्टेट ब्यूरो

2004 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन उमा भारती सरकार ने जिला सरकार मॉडल को खत्म करने के लिए जिन 36 अधिसूचनाओं को निरस्त किया था, कमलनाथ सरकार उन अधिसूचनाओं को फिर वजूद में लाने जा रही है। प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तरुण भनोत ने जिला योजना समितियों को सशक्त बनाने के लिए समिति को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की मंशा से विभागों से अधिकार दिलवाने की अधिसूचनाएं जारी कराने का अध्ययन कराया है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मप्र जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत करने की तैयारी है। इसमें जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या को 20 करना प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिला सरकार मॉडल को फिर लागू करने का सैद्धांतिक फैसला कर लिया था। इसके लिए योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की पहल पर मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने सभी विभागों के साथ दो बार बैठक की। इसमें उन्होंने जिला योजना समितियों को फिर सशक्त बनाने के निर्देश दिए। इसके मद्देनजर विभाग ने जो निर्देश दिए, उसमें 2004 में एक दर्जन से ज्यादा विभागों की जिन 36 अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया था, उन्हें फिर से वजूद में लाने की प्रक्रिया करने की बात नहीं थी। इस वजह से आज तक किसी विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। विभाग की ओर से जब जिला सरकार के गठन को लेकर कार्रवाईयों की समीक्षा की गई तो यह बात सामने आई कि किसी भी विभाग ने निरस्त अधिसूचनाओं की बहाली के लिए कोई पहल ही नहीं की। इसके बिना समितियों को अधिकार संपन्न बनाया ही नहीं जा सकता है।

15 से ज्यादा विभागों के थे अधिकार: विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जिला सरकार के माध्यम से जिलों को हर तरह के अधिकार दिए थे। इसमें प्रशासनिक से लेकर वित्तीय अधिकार तक थे। इसके लिए पशुपालन, वाणिज्यिक कर, उद्योग, सहकारिता, संस्कृति, वित्त, धर्मस्व, राजस्व, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास, परिवहन, आदिम जाति कल्याण और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकार दिए गए थे।

मुख्यमंत्री की मंशा है जिलों के काम जिले में निपटें : भनोत

मध्य प्रदेश के वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तरण भनोत का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा है कि जिलों में होने वाले कामों के लिए लोगों को प्रदेश मुख्यालय तक नहीं आना चाहिए। छोटी-छोटी जरूरतें वहीं पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए जिला योजना समितियों को वैसे ही अधिकार दिए जाएंगे, जो पहले कांग्रेस सरकार में हुआ करते थे। मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें और बेहतर बनाया जा रहा है।

गुलदार ने तीन दिन में ली दूसरी जान

जागरण संवाददाता, कोटद्वार : कोटद्वार के बीरोंखाल में रविवार को गौशाला के बाहर खड़े मासूम को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। मासूम का शव गांव से करीब सौ मीटर दूर मिला है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इससे पहले शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में एक महिला को गुलदार ने निवाला बनाया था। घटना शाम करीब सवा छह बजे की है। देवकुंडई निवासी अनिकेत मां के साथ गोशाला गया था। मां गोशाला के भीतर गाय का दूध निकाल रही थी, जबकि अनिकेत बाहर खड़ा था। इसी दौरान अनिकेत पर गुलदार ने हमला कर दिया। अनिकेत का शोर सुनकर जैसे ही उसकी मां गोशाला से बाहर आई, गुलदार अनिकेत को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गया। काफी तलाश के बाद अनिकेत का शव गोशाला से करीब सौ मीटर दूर मिला। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि गुलदार के हमले की सूचना मिलते ही वन कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया है।

सबरीमाला में श्रद्धालुओं का आना जारी, आय 69 करोड़ के पार पहुंची

2018-19 के तीर्थयात्रा सत्र में इसी अवधि के मुकाबले 27 करोड़ रुपये ज्यादा है राजस्व

सबरीमाला, प्रेट्र : सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। दो महीने तक चलने वाले तीर्थयात्रा सत्र के पहले 20 दिनों में ही मंदिर की आय 69 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है।

तीर्थस्थल की देखरेख करने वाले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) ने कहा है कि छह दिसंबर तक राजस्व 69.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2018-19 के तीर्थयात्रा सत्र में इसी अवधि के मुकाबले 27 करोड़ रुपये ज्यादा है। टीडीबी सदस्य विजयकुमार ने कहा कि पूर्व के सत्र में इस अवधि के दौरान राजस्व 41.84 करोड़ रुपये था। अरवना प्रसादम की बिक्री 28.26 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। पूर्व की अवधि में इस मद में 4.2 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। हुंडी से 23.58 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

पिछले वर्ष 28 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के माकपा की अगुआई वाली वाम मोर्चा सरकार के निर्णय के बाद मंदिर परिसर और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अप्रत्याशित विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में पूजा की अनुमति दी है।

इस साल सरकार ने शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर 10 से 50 साल की महिलाओं को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।

मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का विरोध करने वाले श्रद्धालुओं के कारण इस साल भी भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई को कोच्चि से वापस लौटना पड़ा। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने भी उन्हें संरक्षण देने से मना कर दिया।

24.49 प्रतिशत भूभाग भारत का वनों से आच्छादित है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार। यह आकलन फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 2017 में आई थी।

नौकरी, पीएम आवास और शस्त्र लाइसेंस की शर्त पर दफनाया शव

उन्नाव कांड ▸ लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी, दो दारोगा और चार कांस्टेबल निलंबित

अंतिम संस्कार न करने पर अड़े थे परिजन, मंत्रियों और अफसरों के मनाने पर माने

जागरण टीम, उन्नाव

शनिवार रात को दुष्कर्म पीड़िता की बड़ी बहन के नहीं पहुंचने का हवाला देकर रविवार को अंतिम संस्कार करने की बात कहने वाला परिवार सुबह मुकर गया। शर्त रखी कि मुख्यमंत्री के आने व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने पर ही अंतिम संस्कार होगा। कमिश्नर लखनऊ व आइजी रेंज वार्ता के लिए गांव पहुंचे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कमलरानी वरुण भी मौजूद रहीं। अंत में दो पीएम आवास, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शस्त्र लाइसेंस का भरोसा देने पर परिवार अंतिम संस्कार को तैयार हुआ। युवती का शव खेत में ही बाबा-दादी की समाधि के पास दफनाया गया। वहीं लापरवाही को लेकर उन्नाव स्थित बिहार थाना प्रभारी, दो दारोगा और चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।

उन्नाव जिले में रविवार को भारी सुरक्षा के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। प्रेट्र

पीड़िता का मोबाइल खोलेगा कई राज

मौके से फारेंसिक टीम को मिला दुष्कर्म पीड़िता का अधजला मोबाइल घटना के कई राज खोलेगा। इसमें आरोपितों के साथ ही अन्य लोगों से हुई बातचीत भी सामने आएगी। इससे पुलिस को जांच में आसानी होगी। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय होने की बात सामने आने से उसके वाट्सएप व फेसबुक को भी खंगाला जाएगा। इससे अन्य लोगों की भूमिका भी साफ होगी।

अधिकारी सुबह अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो परिवार सीएम को बुलाने व एक सदस्य को नौकरी देने की शर्त पर अड़ गया। जानकारी पाकर डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय और एसपी विक्रांत वीर के बाद कमिश्नर मुकेश मेश्राम और आइजी लखनऊ रेंज एसके भगत पहुंच गए। कमिश्नर ने पीड़िता के पिता की बात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से कराई। तब परिवार तैयार हुआ। हालांकि, परिवार इस पर अड़ गया कि मांगें माने जाने की बात कमिश्नर लिखित में दें। कमिश्नर ने लिखित में दिया कि पिता-भाई को अलग-अलग पीएम आवास, भाई को सरकारी नौकरी के साथ शस्त्र लाइसेंस भी मिलेगा। साढ़े 12 बजे के बाद श्रम व सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरुण की मौजूदगी में पीड़िता को दफनाया गया। सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा शव पर राजनीति कर रही है। शनिवार को पीड़िता के पिता को चेक देते वक्त स्वामी प्रसाद को सपा के हंगामा-प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था।

बहनें बोलीं, सही इलाज न मिलने से बिगड़ी हालत: मांगें माने जाने के बाद भी पीड़िता की बहनें सरकार पर हमलावर हैं। बड़ी बहन ने आरोप लगाया कि लखनऊ में पीड़िता को सही इलाज नहीं मिला। इससे हालत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। छोटी बहन ने कहा कि एक सप्ताह में मांगें पूरी नहीं होने पर परिवार विधानसभा भवन के बाहर धरने पर बैठ जाएगा।

सुरक्षा घेरे में रहेगा दुष्कर्म पीड़िता का परिवार: दुष्कर्म पीड़िता का परिवार हर समय सुरक्षा घेरे में रहेगा। परिवार के आने-जाने में उनके साथ गार्ड साथ होंगे। घर के बाहर भी पुलिस टीम होगी। जवानों की ड्यूटी आठ घंटे में बदलेगी। एसपी ने सुरक्षा घेरा अगले आदेश तक बनाए रखने को कहा है।

रातभर पीड़िता के घर के आगे डटे रहे सपा नेता: प्रियंका वाड्रा के पीड़िता के गांव पहुंचने के बाद सपा नेता व कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए। सपा नेता, विधायक और एमएलसी शनिवार की पूरी रात ठंड में पीड़िता के घर के सामने तख्त डालकर बैठे रहे। रविवार को सबसे पहले शव को श्रद्धांजलि दी।

वाट्सएप चैटिंग वायरल निशाने पर वकील

जागरण संवाददाता, रायबरेली : उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता की मौत के दूसरे दिन उसका एक वकील निशाने पर आ गया है। वाट्सएप चैटिंग के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इसके बाद मीडिया ने वकील से जब सवाल दागे तो उन्होंने इन संदेशों को सामान्य बताते हुए तफ्तीश का हिस्सा कहा। सीओ सिटी ने मामले से पल्ला झाड़ लिया।

रविवार शाम सोशल साइट पर कुछ वाट्सएप चैटिंग के स्क्रीन शॉट वायरल हुए। बताया जाता है कि यह वार्तालाप उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील के बीच हुई थी। इनमें तमाम बातें मुकदमे को लेकर लिखी हैं। यही नहीं संदेश में लिखा गया है कि 'सही वक्त पर सही निर्णय लेने वाले ही सफल और सुखी होते हैं।' दो लाख लेने की बात भी चैटिंग में लिखी है। उधर, जब मामला गर्माया तो वकील ने अपने बयान में कहा कि पुराने वकील ने हमे मैटर में इंगेज किया था। 156/3 (न्यायालय से मुकदमे का आदेश) होने तक हम लोग वकील थे। उसके बाद भी वह प्रार्थना पत्र लिखवाने हमारे पास आती थी। उसके तमाम परिचित भी समझौते की बात करते थे। यह चैट वही है। देर शाम वकील का फोन बिजी हो गया।सीओ सिटी गोपीनाथ सोनी से जब पूछा गया कि वाट्सएप चैटिंग मामले में पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो है लेकिन जब तक शिकायत या सूचना दर्ज न कराई जाए, तब तक हम सीधा हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। जिस थाने में मुकदमा दर्ज है, अगर वहां की पुलिस सहयोग मांगेगी तो जरूर करेंगे।

जब सब चिंतित, सब मुस्तैद तो फिर न्याय में देरी क्यों

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▸ आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, जीरो पेंडेंसी के लिए न्यायपालिका की मौजूदा कार्यक्षमता बढ़ानी होगी

▸ न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भरने के अलावा अतिरिक्त न्यायाधीश भी करने होंगे नियुक्त

हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म कर जलाने वाले आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर जताई जा रही खुशी को न्याय के इंतजार में हताश और त्वरित न्याय के लिए छटपटा रही जनता की अभिव्यक्ति करार दिया जा रहा है। न्याय में देरी के लिए न्यायपालिका पर अंगुलियां उठ रही हैं। घटना के बाद न्यायपालिका के मुखिया, कानून मंत्री और मुठभेड़ में आरोपितों को मार गिराने वाली पुलिस के आला अधिकारियों तक के बयान आ चुके हैं। सभी ने अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए चिंता जताई है। सवाल है कि जब अपराध पर काबू करने, दंड विधान तैयार करने और अपराधी को सजा देकर अंजाम तक पहुंचाने वाले सभी चिंतित, सजग और मुस्तैद हैं तो फिर न्याय में देरी क्यों हो रही है। इसका कारण आम जनता को मालूम हो या न हो, लेकिन न्याय प्रणाली में शामिल संस्थाओं को मालूम है। हर सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट बताती है कि कमी कहां है और उससे निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है।

गत चार जुलाई को आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य पाने के लिए न्यायपालिका की मौजूदा कार्यक्षमता बढ़ाने और न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भरने के अलावा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने होंगे। यानी समस्या और समाधान दोनों मालूम हैं। पिछले साल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी देश में 10 लाख की आबादी पर औसतन 19 जज हैं। देश भर की अदालतों में करीब तीन करोड़ मामले लंबित हैं। इन्हें जल्दी निपटाने के लिए जजों की संख्या में वृद्धि तो भविष्य की बात है, अभी 5000 से ज्यादा मंजूर पद ही खाली हैं। इसके अलावा 25 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल मंजूर 1079 पदों में से 410 रिक्त हैं। सबसे ज्यादा रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं जहां 160 में से 60 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक खाली है।

लंबित न्याय की समस्या का विश्लेषण कर आर्थिक सर्वेक्षण में हल पेश किया गया है। उसमें न्यायिक सुधार पर जोर देते हुए पांच साल में मुकदमों की 100 फीसद निस्तारण दर हासिल करने और पुराने मुकदमों का ढेर खत्म करने के लिए कार्यक्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त जजों की जरूरत बताई गई है। जिला एवं सत्र न्यायालयों में दिसंबर 2018 तक कुल 3.04 करोड़ मामले लंबित थे। यहां जजों के कुल 22750 पद मंजूर हैं। मात्र 17819 (79 फीसद) जज ही काम कर रहे हैं और बाकी पद खाली हैं। एक जज वर्ष भर में औसतन 746 मामले निपटाता है। ऐसे में 100 फीसद निस्तारण दर प्राप्त करने के लिए 2279 जजों की और जरूरत है। इसके अलावा पांच साल में सभी लंबित मामले खत्म करने के लिए 8152 अतिरिक्त जजों की जरूरत होगी। इसी तरह हाई कोर्ट में इसके लिए 361 अतिरिक्त जजों की जरूरत है। पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा और बंगाल में मुकदमों का निस्तारण बहुत खराब है। ऐसे में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति में इन राज्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई गई है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद भरने में सरकार की भूमिका सीमित होती है। फिर भी कई बार कोलेजियम की सिफारिशें लंबे समय तक स्पष्टीकरण के आदान-प्रदान में लटकी रहती हैं।

सरकार दुष्कर्म और पॉक्सो कानून में बच्चों के यौन उत्पीड़न के मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना लागू करने जा रही है। इस पर कुल 767.25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। केंद्र 474 करोड़ रुपये देगा देगा। 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव है। इस पर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।

अभी हाल में टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है इसमें भी जस्टिस सिस्टम में खाली पड़े पदों की बात है। यह रिपोर्ट पुलिस, जेल और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन करने के बाद स्थिति पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस महकमे में 22 फीसद, जेलों में 33 से 38 फीसद और न्यायपालिका में 20 से 40 फीसद पद खाली हैं। हालांकि न्यायपालिका का यह आंकड़ा 2016-17 तक का है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में जजों के मंजूर पदों के हिसाब से मार्च 2018 तक 4071 कोर्ट कक्षों की कमी थी। रिपोर्ट व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर बल देती है। यह रिपोर्ट न्यायपालिका पर होने वाले खर्च की भी तस्वीर पेश करती है जिसके मुताबिक, भारत में न्यायपालिका पर जीडीपी का 0.08 फीसद खर्च होता है। सिर्फ दिल्ली को छोड़कर जहां 1.9 फीसद बजट है, बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश न्यायपालिका पर एक फीसद से कम खर्च करते हैं।

देश में दुष्कर्म की घटनाओं पर राजनीति न हो : रविशंकर

जागरण संवाददाता, पटना

▸ केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, राहुल के बयानों से खराब होती है देश की छवि

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में महिला हिंसा, बलात्कार और पॉक्सो के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कानून हैं। ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए चिंता करनी चाहिए। लेकिन, राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की छवि पर असर पड़ता है। वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कई राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है। क्या वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं? ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वह पिछले दिनों राजस्थान हाई कोर्ट के भवन के उद्घाटन समारोह में गए थे। वहां राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। वहां कहा गया कि महिला हिंसा और दुष्कर्म मामले में त्वरित सुनवाई कैसे हो, इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी करने की जरूरत है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में अभी 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं। महिला हिंसा, दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत सुनवाई के लिए 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने हैं जिनमें 400 पर सहमति बन गई है। कहा, देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया जाएगा कि वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में छह माह के भीतर सुनवाई पूरी कराएं। वह रविवार को पटना के गर्दनीबाग में उपडाकघर के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली में भीषण अगलगी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि घटना में बिहार के लोग प्रभावित हुए हैं। जख्मी लोगों के बेहतर इलाज का प्रबंध किया जाना चाहिए।

रविशंकर प्रसाद। फाइल

हैदराबाद मुठभेड़ में मानवाधिकार आयोग की जांच दूसरे दिन जारी

हैदराबाद, प्रेट्र : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के चार आरोपितों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जांच रविवार को लगातार दूसरे दिन जारी रखी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपितों के परिजनों को नारायणपेट जिले से शहर लाया गया। मानवाधिकार आयोग की टीम के उनका बयान दर्ज करने की संभावना है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मानवाधिकार आयोग की जांच जारी है।

शुक्रवार तड़के हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बारे में बहस छिड़ने के एक दिन बाद आयोग ने तथ्य का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी थी। टीम ने शनिवार को महबूबनगर जिले के सरकारी अस्पताल का दौरा किया था, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद चारों आरोपितों के शवों को रखा गया है। आयोग की टीम में फॉरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। चारों आरोपितों के शवों का महबूबनगर के सरकारी जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया गया है और उसकी वीडियोग्राफी की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।

मप्र में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने खुद को लगाई आग, गंभीर

नईदुनिया, छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शनिवार रात छेड़छाड़ से परेशान 21 वर्षीय युवती ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। युवती की हालत गंभीर है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, रात में ही आरोपित युवक भी संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गया।

पुलिस के अनुसार, युवती गांव से आकर शहर में किराए के कमरे में रहती है। युवक गोल्डी (24) उसे लगातार परेशान कर रहा था। छेड़छाड़ के साथ उसने युवती को बदनाम करने की धमकी दी थी। इससे तंग आकर युवती ने खुद को आग लगा ली। बाद में खुद आग बुझाकर चाची को फोन कर इस बारे में सूचना दी। युवती एक साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। कोचिंग जाते समय युवक उसे परेशान करता था।

सीएसपी अशोक तिवारी ने बताया कि गोल्डी को भी गंभीर रूप से झुलसने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह मैदान में आग जला रहा था। लकड़ियों पर मिट्टी का तेल डालने के दौरान आग भभकने से वह झुलस गया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर गोल्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शिकायत के बाद युवक ने भी आत्मघाती कदम उठाया होगा। मामले में जांच जारी है।

मेडिकल कराने के लिए नौ घंटे भटकी दुष्कर्म पीड़िता: मप्र के रायसेन जिले की दुष्कर्म पीड़िता शनिवार रात दो बजे से रविवार सुबह 11 बजे तक सरकारी अस्पताल में पति और एक छोटे बच्चे के साथ मेडिकल के लिए भटकती रही। महिला के साथ गांव के ही आरोपित वीरेंद्र राजूपत ने 4-5 दिन तक दुष्कर्म किया था, लेकिन डर के चलते महिला ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने दो दिन पूर्व कीटनाशक दवा पी ली। इलाज के दौरान महिला ने पति को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित वीरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर मौजूद न होने के कारण दुष्कर्म पीड़िता को परेशान होना पड़ा। बाद में उसे भोपाल ले जाया गया। रायसेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके शर्मा ने बताया कि मामले में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात के गुलबर्ग हत्याकांड के दोषी को जमानत

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने गुलबर्ग हत्याकांड में आजीवन कैद की सजा पाने वाले भरत राजपूत को जमानत पर रिहा कर दिया है। 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगा मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में भरत राजपूत समेत 11 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। इन सभी पर 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में हुए दंगा व हत्या का दोष सिद्ध हुआ था। इनके अलावा 13 अन्य आरोपित को दोषी पाए जाने पर दस-दस साल की सजा सुनाई थी।

राजपूत के वकील ने जस्टिस बेला त्रिवेदी एवं जस्टिस एसी राव के समक्ष कहा कि एक अन्य अभियुक्त लाखासिंह चूडास्मा को गत 30 जुलाई को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। भरत राजपूत का नाम 2002-03 में गवाहों की ओर से दिए गए बयानों में शामिल नहीं है। इसके अलावा गवाहों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश शपथ पत्रों में भी उसके नाम का उल्लेख नहीं है। विशेष अदालत में दंगा मामलों के स्थानांतरण के बाद पहली बार वर्ष 2008 में राजपूत का नाम शामिल किया गया था।

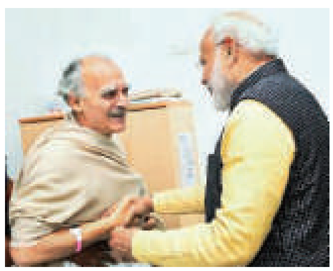

पुणे के अस्पताल में अरुण शौरी से मिले पीएम

पुणे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम पुणे के अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी से मुलाकात की और उनके साथ लगभग 15 मिनट बिताए। यह जानकारी पीएम ने स्वयं ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'रविवार शाम मैंने पुणे में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।' पुणे से 60 किमी दूर लवासा स्थित अपने बंगले में एक दिसंबर को टहलने के दौरान गिरने के बाद शौरी को पुणे के रूबी हाल क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक पीएम का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। एयरपोर्ट जाने से पहले उन्होंने 45 मिनट अस्पताल में बिताए। 1999-2004 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शौरी मोदी की आर्थिक नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। प्रेट्र

राजस्थान में शुरू हुआ 'पानीपत' का विरोध, प्रतिबंध लगाने की मांग

राज्य ब्यूरो, जयपुर

▸ फिल्म में महाराजा सूरजमल के बारे में दिखाए गए दृश्यों को लेकर जाट समाज ने जताई नाराजगी

फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'पानीपत' पर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल के चरित्र को गलत ढंग से दिखाए जाने का आरोप लगाकर जाट समाज फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यही नहीं सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी फिल्म में गलत तथ्य दिखाए जाने पर आपत्ति की है।

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह तो महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी से हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करते हुए फिल्म में महाराजा सूरजमल जैसे महापुरुष का गलत ढंग से चित्रण किया गया है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत में जाट समुदाय के विरोध को देखते हुए फिल्म पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा, पेशवा और मराठा जब पानीपत युद्ध हारकर घायल अवस्था में लौट रहे थे तो महाराजा सूरजमल और रानी किशोरी ने छह माह तक पूरी मराठा सेना और पेशवाओं को अपने यहां पनाह दी थी। विश्वेंद्र सिंह ने मांग की है कि यदि किसी वंश या महान व्यक्ति पर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसे रिलीज करने से पूर्व उनके स्वजनों और समाज से अनुमति ली जाए। सरकार चाहे तो इसके लिए एक समिति बना दे।

एक और फिल्म विवाद में फंसी। फाइल

वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर फिल्म में महाराजा सूरजमल के बारे में गलत चित्रण की निंदा की है। वहीं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस फिल्म से राजस्थान में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने ट्वीट कर फिल्म के विवादित अंशों के बारे में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी का ध्यान आकर्षित किया है। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे का गृह जिला धौलपुर है जो भरतपुर के नजदीक ही है। वहीं राजे और बेनीवाल दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं और महाराजा सूरजमल का राजस्थान के जाट समुदाय सहित सभी वर्गों में बड़ा सम्मान है।

यह है आपत्ति : फिल्म में बताया गया है कि सूरजमल ने अफगानों के खिलाफ मराठों की मदद की, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बाद में पेशवा सदाशिव भाऊ का साथ नहीं दिया।

जोधा अकबर पर भी हो चुका है विवाद : ज्ञात हो, गोवारिकर की ही फिल्म 'जोधा अकबर' पर भी विवाद हो चुका है। यह फिल्म आज तक राजस्थान में प्रदर्शित नहीं हो पाई है।

एनकाउंटर को सजा देने का तरीका नहीं बनाया जाए : तथागत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने किसी भी अपराध के आरोपितों के एनकाउंटर को गलत ठहराया है। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए और अदालत से उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि तथागत रॉय का यह बयान हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के आरोपितों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा-'मैं कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि मुठभेड़ या कंगारू कोर्ट आपराधिक न्याय के निपटारे में मानक संचालन प्रक्रिया हो सकती हैं। इस तरह के एनकाउंटर को सजा देने का तरीका नहीं बनाया जाना चाहिए। आरोपितों को पकड़कर उन्हें अदालत से सजा दिलाई जानी चाहिए।' गौरतलब है कि गत 27 नवंबर को महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। महिला चिकित्सक का जला हुआ शव बरामद हुआ था। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने बताया कि चारों आरोपित मुठभेड़ मारे गए।

तैयारी

छत्तीसगढ़ में पांच वर्ष में खड़े किए गए 525 मोबाइल टावर, देश के 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में लगाए गए 2343, बस्तर में अभी बीएसएनएल के 644 समेत कुल 841 टॉवर

नक्सलियों से लड़ने को मोबाइल नेटवर्क का जाल

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ समेत देश के नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में मोबाइल नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। बीते पांच वर्षों में इन राज्यों में कुल 2343 टॉवर खड़े किए गए हैं। इनमें 525 अकेले छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। यहां के लिए कुल 532 टॉवर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए थे, लेकिन सुरक्षाकारणों से सात टावर नहीं लगाए जा सकें हैं। वहीं झारखंड में सबसे ज्यादा 816 टावर लगाए गए हैं।

गृह विभाग के अफसरों ने बताया कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सूचनातंत्र को मजबूत करने के लिए 2014 में मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया था। इसके तहत दो बार में कुल 2355 टॉवर स्वीकृत किए गए। इसमें से मार्च 2017 में 2199 और नवंबर 2018 तक 156 टावर स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं। अफसरों के अनुसार करीब 39 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले बस्तर में करीब 841 टॉवर लगाए गए हैं। इनमें से 644 बीएसएनएल के हैं। निजी कंपनियों के करीब 197 टॉवर हैं। इनमें से अधिकांश वहां के शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके बावजूद बस्तर अब भी पूरी तरह मोबाइल नेटवर्क में नहीं आ पाया है। नक्सली खतरे की वजह से अंदनी क्षेत्रा में टावर नहीं लग पा रहे हैं। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से निश्चित प से नक्सलियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अभी नेटवर्क नहीं होने के कारण सूचनाओं के अदान- प्रदान में काफी दिक्कत होती है।

नक्सली करते हैं मोबाइल नेटवर्क और फोन का विरोध : नक्सली मोबाइल फोन और नेटवर्क को अपने लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि पूर्ववर्ती सरकार में जब मोबाइल बांटा गया तो नक्सलियों ने पहले मोबाइल न लेने का फरमान जारी किया। मोबाइल छीनने और मोबाइल रखने वालों को प्रताड़ित करने की भी कई घटनाएं हुईं।

फैक्ट फाइल

▸ 42% है छत्तीसगढ़ में टेलीकॉम का कवरेज एरिया।

▸ 19.14% है बस्तर संभाग में कवरेज एरिया।

▸ 31 लाख 86 हजार 946 है बस्तर की आबादी।

राज्य के पांचों संभागों में टेलीकॉम कवरेज की स्थिति

संभाग	क्षेत्रफल	नेटवर्क	प्रतिशत
बस्तर	39104.50	7484.45	19.14
बिलासपुर	25830.31	13779.69	53.35
दुर्ग	20784.01	12005.94	57.77
रायपुर	21242.85	11349.51	53.43
सरगुजा	28201.14	11715.44	41.54

(नोट- क्षेत्रफल व नेटवर्क एरिया वर्ग किमी में)

नक्सल प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावर

राज्य	स्वीकृत	स्थापित
आंध्र प्रदेश	62	62
बिहार	250	250
छत्तीसगढ़	532	525
झारखंड	816	816
महाराष्ट्र	65	65
मध्यप्रदेश	22	22
ओडिशा	261	256
तेलंगाना	173	173
उत्तर प्रदेश	78	78
पश्चिम बंगाल	97	96
कुल	2355	2343

ट्विटर बना अखाड़ा, आइएएस और आइपीएस अधिकारी भिड़े

हैदराबाद एनकाउंटर

नईदुनिया, कवर्धा

हैदराबाद एनकाउंटर पर बहस सोशल मीडिया पर तेज है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और कर्नाटक पुलिस की आइजी डी. रूपा शनिवार को ट्विटर पर आमने-सामने हो गए।

दरअसल, आइपीएस डी. रूपा ने संस्कृत का एक श्लोक पोस्ट किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ होता है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूं। इस श्लोक के जवाब में री-ट्वीट करते हुए आइएएस अवनीश शरण ने लिखा, आप जैसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यह आशा नहीं थी मैम...। सॉरी...। अवनीश कुमार शरण के री-ट्वीट के बाद आइपीएस रूपा ने नाराजगी भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, यह संस्कृत के खिलाफ आपके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यहां धर्म का मतलब सही के साथ खड़ा होना है। कई जगह पुलिस विभाग का तो 'दुष्ट शिक्षक, शिष्ट रक्षक' सिद्धांत और लोगो है। इसका भी यही मतलब है, जो इस श्लोक में है और मैंने तो इसे किसी संदर्भ के साथ जोड़ा ही नहीं है। सत्यमेव जयते। ट्वीट-री-ट्वीट के बाद तो मानो कमेंट और सवालों की ट्वीट पर बाढ़-सी आ गई। जवाब में आइएएस अवनीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने बैचमेट और राज्य की आइएएस प्रियंका शुक्ला के एक ट्वीट का स्क्रीन शेयर किया, जिसमें लिखा है, गलत, बहुत गलत है, और हमेशा गलत रहेगा...। कड़ी सजा के लायक रहेगा...। पर गलत को भी गलत तरीके से सजा देना भी क्या सही कहलाएगा?

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

साहित्य में विचार और भाव दोनों का समावेश होता है

लापरवाही की आग

दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे एक कारखाने में लगी आग से 40 से अधिक लोगों की मौत वास्तव में नियम-कानूनों की घोर अनदेखी का नतीजा है। इस अवैध कारखाने में आग भले ही शार्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन वहां हुई मौतों का जिम्मेदार दिल्ली का प्रशासन भी है। देश की राजधानी में भी अवैध रूप से कारखाने चलना कुशासन की पराकाष्ठा ही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो उनकी भी होनी चाहिए जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी है कि कोई फैक्ट्री नियम-कानूनों का उल्लंघन करके न चले। यह अभागी फैक्ट्री केवल चोरी-छिपे ही नहीं चलाई जा रही थी, बल्कि वहां सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं थे और वह भी तब जब वहां ज्वलनशील उत्पाद निर्मित किए जा रहे थे। वास्तव में इसी कारण इतने अधिक लोग मारे गए। इन मौतों पर अफसोस जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा करना एक तरह से कर्तव्य की इतिश्री करना ही है। इस तरह से कर्तव्य की इतिश्री अर्थात जिम्मेदारी के निर्वहन का दिखावा इसके पहले भी न जाने कितनी बार किया जा चुका है। चंद महीने पहले करोलबाग इलाके में एक होटल में आग लगने से एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। उसके पहले बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में करीब 20 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई थी। अब एक और फैक्ट्री में आग लगने से हुई व्यापक जनहानि यही बता रही है कि पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया गया।

हाल के वर्षों में दिल्ली में नियम-कानूनों को धता बताने अथवा सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण आग लगने की इतनी अधिक घटनाएं घट चुकी हैं कि ऐसा लगता है कि राजधानी के हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे तब थे जब उपहार सिनेमाघर में लगी आग ने दर्जनों लोगों की जिंदगी लील ली थी। जब नियमों के अनुपालन के मामले में देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है तब इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि दूरदराज के इलाकों में कैसी दयनीय दशा होगी। इस दयनीय दशा के प्रमाण आए दिन मिलते भी रहते हैं। ऐसे प्रमाण भ्रष्ट नौकरशाही और साथ ही वोट बैंक की राजनीति की देन हैं। सुनियोजित विकास विरोधी इसी गंदी राजनीति के कारण अवैध बसाहट और व्यावसायिक ठिकानों का बेतरतीब जाल सारे देश में फैलता जा रहा है। यही जाल तरह-तरह के हादसों को जन्म देता है। ये हादसे केवल लोगों की जान ही नहीं लेते, बल्कि देश की बदनामी भी करते हैं। विडंबना यह कि इसके बावजूद हम विकसित देश बनने का दम भरते हैं।

लोकतंत्र की जीत

अंगुली पर गिने चुने कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ दें तो नक्सलियों के गढ़ में भी बंपर वोटिंग होना झारखंड के लिए शुभ संकेत है। जंगल, पहाड़ों, नदी-नालों के बीच बसे गांवों से भी बड़ी संख्या में मतदाता निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के प्रति उनका यह उत्साह संकेत दे गया कि वे अपने अधिकार के प्रति न सिर्फ सजग हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रति संकल्पित भी हैं। वे विकास के पक्षधर हैं और समाज के तानाबाना को बिगाड़ने में जुटे असामाजिक तत्वों से छुटकारा चाहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर सुदूर इलाकों के मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसने अंतिम व्यक्ति तक को मतदान के प्रति जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैनर-पोस्टर, विचार गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक समेत प्रचार के अन्य माध्यमों के जरिये उन तक पहुंचने और मतदान के महत्व से उन्हें अवगत कराने में सफलता पाई। मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपनी पंसद का उम्मीदवार चुने। इस कार्य में स्थानीय पुलिस-प्रशासन और अर्द्धसैनिक बलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने बीहड़ों में भी अमन-चैन की कमान थाम रखी थी। अलबत्ता नक्सलियों ने कुछ क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश भी की, परंतु अर्द्धसैनिक बलों की सजगता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया और मीलों पैदल चलकर भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इससे इतर शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों से कम वोटिंग चिंतनीय है। तमाम तरह की सुविधाओं के बावजूद उनका घर से नहीं निकलना कई सवालों को जन्म देता है। जरूरत है ऐसे मतदाताओं को अपने गिरेबां में झांकने और लोकतंत्र के महत्व को समझने की। उनके मतदान करने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।

नक्सलियों ने कुछ क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन अर्द्धसैनिक बलों की सजगता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। मतदाता मीलों पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदान के प्रति उनका यह उत्साह संकेत दे गया कि वे अपने अधिकार के प्रति न सिर्फ सजग हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के प्रति संकल्पित भी हैं

इतिहास पर अनुकरणीय पहल

हृदयनारायण दीक्षित

ब्रिटिश लेबर पार्टी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए औपनिवेशिक उत्पीड़न को उजागर करने की जरूरत बता रही है ताकि नई पीढ़ी उन अत्याचारों के बारे में जान सके

विश्व इतिहास में तमाम गलतियां और रक्तपात हैं। बहुत कुछ श्रेष्ठ भी है। दोनों का सम्यक बोध उपयोगी है, लेकिन इतिहास लेखन में बड़ी घटनाओं की भी योजनाबद्ध उपेक्षा होती है। ब्रिटेन के इतिहास लेखन में भी ऐसा ही हुआ है। ब्रिटिश चुनाव इसी 12 दिसंबर को हैं। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद व ब्रिटिश राज के अन्याय का सही इतिहास लिखने के लिए एक शैक्षिक बोर्ड गठित करने की घोषणा की है। पार्टी घोषणा पत्र के अनुसार सत्ता में आने के बाद यही सही इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 1922 के आसपास दुनिया की 20 प्रतिशत जनसंख्या पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस दौरान भारत सहित तमाम देशों की जनता पर क्रूर अत्याचार किए थे। लेबर पार्टी की यह घोषणा ब्रिटिश श्रेष्ठतावाद पर हमला है। बहस तीखी है। ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे भारत में भी इस पर चर्चा जरूरी है। सांसद शशि थरूर सहित तमाम भारतीयों ने इसका स्वागत किया है।

ब्रिटिश राज के अन्याय और उत्पीड़न का सबसे बड़ा शिकार भारत था। गांधी जी ने 1908 में लिखा था, 'कर्जन के अनुसार भारत साम्राज्यरूपी भवन का कलश है। भारत के कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व है। इसलिए संघर्ष जरूरी है।' तब ब्रिटेन विश्व व्यापार का नियंता था। अन्य उपनिवेशों की तुलना में भारत में इंग्लैंड के माल की ज्यादा ब्रिकी थी। गांधी जी ने 1913 में लिखा था, 'भारत इंग्लैंड के माल का सबसे बड़ा ग्राहक है। भारत तैयार माल का 14.5 प्रतिशत खरीदता है, ऑस्ट्रेलिया आठ प्रतिशत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका छह-छह प्रतिशत।' भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहां से तैयार माल भारत आता था। अंग्रेजी सत्ता की शोषण नीति भयावह थी। दो बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे सौलिसबरी ने भारत के संबंध में कहा था, 'इस देश के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर ले जाया जाता है। बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। अगर उसका खून निकालना ही है तो चीरा ऐसी जगह लगाया जाना चाहिए जहां खून ज्यादा हो या कम से कम पर्याप्त मात्रा में हो। जहां वह पहले से ही कम हो ऐसी जगह नहीं।' ब्रिटेन की युवा पीढ़ी अपने पूर्वज शासकों द्वारा किए गए उत्पीड़न से भलीभांति अवगत नहीं। ऐसे में ब्रिटिश स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाने की पहल स्वागतयोग्य है।

भारत में अंग्रेजी सत्ता का इतिहास रक्तरंजित है। जलियांवाला बाग नरसंहार में निहत्थे बच्चे भी मारे गए थे। ब्रिटिश राज में 1807 तक श्रमिकों की भी खरीद फरोख्त होती थी। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान अमानवीय यातना शिविर चलाए गए थे। 1948 में ब्रिटिश सैनिकों ने मलेशिया में 24 लोगों को मारा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों लोगों का उत्पीड़न हुआ। अंग्रेजी उपनिवेशवाद का इतिहास भयावह है। ब्रिटिश चुनावों के दौरान ऐसे इतिहास को खंगालने और नई पीढ़ी को पढ़ाने की घोषणा वास्तव में साहसिक है।

अवधेश राजपूत

भारत के लिए भी यह मार्गदर्शी है। यहां आक्रमणकारियों के अत्याचारों के तथ्यगत विवरण भी छिपाए जाते हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी उदार मानी जाती है। ब्रिटेन के उदारवादी भी अपने देश की सत्ता के अन्याय को जनता के सामने लाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन भारत के उदारवादी मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गोरी, बाबर और औरंगजेब सहित तमाम उत्पीड़कों की करतूतों पर भी पर्दा डालते हैं। भारत के उदारवादी ब्रिटिश उदारवादियों से भिन्न हैं। वे अपने अतीत की गलतियों को भी सामाजिक जागरूकता और शिक्षण की परिधि में लाने के हिमायती हैं। उनके उलट भारत में उदारवादी विदेशी हमलावरों और बादशाहों की गलतियों को ढकना ही अपना कर्तव्य मानते हैं। श्रीराम जन्मभूमि मामले में एक पक्ष ने कहा कि शासक बाबर ने गलत किया या सही, लेकिन अब हम उसकी गलती नहीं सुधार सकते।' गलती सुधारने के लिए ही इतिहास का महत्व है। इतिहास की गलती सुधारने में ही वर्तमान का भविष्य है। भारत के विकृत इतिहास में भारतीय पराक्रम की चर्चा कम है। बंकिम चंद्र ने लिखा है, 'यहां पारसियों समेत यवन, वाहलिक, शक, हूण, अरब और तुर्क सभी आए और कुछ दिनों के बाद खदेड़े गए।' भारतीय पराक्रम का यह तथ्य इतिहास का भाग नहीं है। यहां आक्रमणों का सिलसिला नहीं थमा। मोहम्मद बिन कासिम का हमला (712 ई.) फिर गजनी द्वारा 17 बार, मोहम्मद गोरी (1173 ई.), तैमूर (1398 ई.), बाबर (1526 ई.) नादिरशाह (1738 ई.) और अहमदशाह अब्दाली (1761 ई.) के हमले रक्तिम इतिहास हैं। उदारवादी इतिहास के क्रूर हमलावरों का सुंदर चित्रण करने के पक्षधर हैं।

लेबर पार्टी अपने ही पूर्वजों द्वारा किए गए उत्पीड़न पर शोध की जरूरत बता रही है। वहीं भारत में विदेशी हमलावरों के अत्याचारों पर खुली चर्चा में भी उदारपंथी बाधक हैं। अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत युद्ध हुआ। राष्ट्रभक्त मराठा लड़े। अब्दाली क्रूर था। हालिया रिलीज फिल्म पानीपत में अब्दाली के रूपचित्रण पर भी उदारवादी अनुदार हो रहे हैं कि उसका चित्रण गलत हुआ है। औरंगजेब ने मंदिरों का ध्वंस कराया। अत्याचार किए। उसकी भी तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। बाबर को महान बताने वाले भारी संख्या में हैं। उसने रामजन्म भूमि मंदिर तुड़वाया। उसने भारत भूमि की निंदा की। यहां मरना भी उसे गवारा नहीं था। डॉ. आंबेडकर ने पाकिस्तान पर लिखी अंग्रेजी किताब 'डॉ. आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज खंड-आठ में ऐसे शासकों/हमलावरों को मंदिर तोड़क व अत्याचारी बताया है, लेकिन भारत के छद्म इतिहासकार ऐसे शासकों के मानवता विरोधी वास्तविक इतिहास पर पर्दा डालते हैं।

भारतीय इतिहास का लेखन 'उपयोगितावादी दृष्टिकोण' से हुआ है। हमारे इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास परंपरा को मिथक बताते रहे हैं। वे यूरोपीय तर्ज के इतिहास लेखन को ही आदर्श बताते रहे हैं, लेकिन यूरोपीय इतिहास लेखन एकपक्षीय है। वह सत्य से परे है तभी लेबर पार्टी ने ब्रिटिश इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत बताई है। यहां भारत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ माह पहले भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत में अंग्रेजी राज के समय का इतिहास भी विकृत है। सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों के साथ भी इतिहास में न्याय नहीं हुआ। ब्रिटेन में इतिहास का पुनर्लेखन राष्ट्रीय बहस का विषय है। भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की गंभीर बात भी भगवाकरण कही जाती है। भारत चाहता है कि अंग्रेज अपने शासन काल के उत्पीड़न पर खेद प्रकट करें। यह तभी संभव है जब ब्रिटिश इतिहास में उपनिवेशवाद की सही तस्वीर सामने आए। यहां भी मध्यकालीन हमलावरों के असल चरित्र को उजागर करने की दरकार है। बात लंदन से चली है। भारत पहुंच गई है। इससे प्रेरणा लेना अच्छा रहेगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

मातृभाषा में हो प्रारंभिक शिक्षा

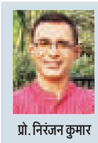

प्रो. निरंजन कुमार

मातृभाषा में बच्चे कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में उन्हें मुश्किल होती है

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की वकालत करने के बाद राज्य में एक नया विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने उन्हें तेलुगु भाषा विरोधी करार देना शुरू कर दिया है। उनका यह दांव भले ही एक राजनीतिक धींगामुश्ती में बदल जाए, लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा को लेकर एक व्यापक विमर्श अवश्य शुरू कर दिया है। जगन की ऐसी पहल के उलट कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देशवासियों से मातृभाषाओं के अधिकाधिक इस्तेमाल और उन्हें बढ़ावा देने की अपील की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मातृभाषा में शिक्षा देने की वकालत करते रहे हैं। 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के संशोधित मसौदे में भी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अहम सिफारिशें हैं, पर मातृभाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर शिक्षा नीति तैयार वाली कस्तूरीरंगन समिति ने शायद गंभीरता से विचार नहीं किया। यह बिंदु है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का। हालांकि मातृभाषा किसे कहें, इसे लेकर एक विवाद भी है। क्या है मातृभाषा की भारतीय संकल्पना? मातृभाषा में शिक्षा क्यों जरूरी है? इस संदर्भ में शिक्षाशास्त्र के शोधों के क्या निष्कर्ष हैं? राष्ट्रहित में क्या किया जाना चाहिए?

पिछले कुछ दशकों से भारत में सरकारी स्कूली शिक्षा में काफी गिरावट आई है। दूसरी तरफ निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह महानगरों को तो छोड़िए, छोटे शहरों और कस्बों तक में चौतरफा उग आए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम जहां अपने-अपने राज्यों की भाषाएं या कहें कि स्थानीय अथवा मातृभाषा हुआ करता था, वहीं अब लगभग सभी निजी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो गया है। हालांकि मातृभाषा की अवधारणा को ही लेकर कुछ विद्वान विवाद खड़ा करते हैं। वास्तव में मातृभाषा की भारतीय संकल्पना को पश्चिमी नजरिये से देखना उचित नहीं होगा। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रवींद्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि प्रयोजन की दृष्टि से मातृभाषा के दो आयाम हैं। पहले रूप में मातृभाषा का अर्थ है मां की भाषा अर्थात झूले-पालने की भाषा, जिसके द्वारा शिशु अपने भाषाई बोध एवं जीवन बोध का निर्माण करता है, लेकिन पश्चिम से अलग भारत जैसे बहुभाषी देश में मातृभाषा का एक और भी आयाम है। वह भाषा भी मातृभाषा है जो सड़क, बाजार और व्यापक सामाजिक जीवन की भाषा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार, संस्कार और जातीय इतिहास एवं परंपरा से जुड़ता है। उदाहरण के लिए अयोध्या में रहने वालों की मातृभाषा एक तरफ अवधी है तो दूसरी तरफ हिंदी भी। इसी तरह धनबाद में रहने वाले आदमी की मातृभाषा एक तरफ 'खोरठा' भाषा है तो हिंदी भी उसकी भाषा है। यही स्थिति कर्नाटक में भी देखी जा सकती है जहां एक बड़ी आबादी 'तुलु' नामक भाषा तो बोलती है, लेकिन व्यापक प्रयोजनों के लिए कन्नड़ का प्रयोग करती है। यही चीज तेलंगाना में 'लंबाडी' भाषा बोलने वालों और तेलुगु के संदर्भ में देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रादेशिक भाषाएं भी एक स्तर पर मातृभाषा का ही रूप हैं और जो सरकारी स्कूलों में शिक्षण का माध्यम भी हैं।

शिक्षाशास्त्र के विभिन्न शोध बताते हैं कि बच्चों के पूर्ण मनो-बौद्धिक विकास के लिए आरंभिक शिक्षण मातृभाषा में ही होना चाहिए। यूनेस्को ने भी जोर देकर कहा है कि आरंभिक शिक्षण मातृभाषा में होने से बोध एवं संज्ञान क्षमता बढ़ती है। छोटे बच्चों के संदर्भ में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि गणित या सामान्य चीजें भी अंग्रेजी में उन्हें नहीं समझ आतीं, जबकि वही चीज हिंदी या उनकी मातृभाषा में बताई जाए तो उनके लिए ज्यादा कठिनाई नहीं आती। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण एवं संज्ञान सहज तथा शीघ्र हो जाता है। इससे बच्चे कठिन चीजें भी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि इतर भाषाओं में बच्चों को रटना पड़ता है, जो उनके पूर्ण मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है।

नई शिक्षा नीति मसौदे में भी मातृभाषा की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि जहां तक हो सके आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा में भी शिक्षण माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने की बात है, लेकिन ये सिफारिशें केवल एक सदिच्छा के रूप में हैं, इनको लागू करने लेकर कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रारंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए। दिल्ली में ही एक स्कूल है सरदार पटेल विद्यालय जो दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से है। इस स्कूल में कक्षा पांच तक की पढ़ाई हिंदी में होती है। यहां के विद्यार्थी न सिर्फ अकादमिक ज्ञान में श्रेष्ठ और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सफल हैं, बल्कि आचरण, मूल्य और संस्कारों में भी वे एक प्रतिमान के रूप में देखे जाते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया आदि देशों की तरक्की का एक बड़ा कारण उनकी आरंभिक शिक्षा का मातृभाषा में होना भी है।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद देश में शिक्षा का पूरा मॉडल औपनिवेशिक प्रभाव से प्रभावित शिक्षाविदों के हाथ में रहा। इन तथाकथित अभिजात्य लोगों की दृष्टि में अंग्रेजी और पश्चिमी चिंतन पद्धति ज्यादा बेहतर थी। यहां तक कि गरीबों-निम्न वर्ग की वकालत करने वाले मार्क्सवादी बुद्धिजीवी भी भारतीय भाषाओं में शिक्षण के मुद्दे पर उदासीनता या हिकारत का भाव रखते थे। 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग तक ने प्रारंभिक शिक्षण को मातृभाषा में करने की सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से मातृभाषाएं या भारतीय भाषाएं उपेक्षित ही रहीं। गांधी जी ने कहा था कि 'यदि मैं तानाशाह होता तो विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना तुरंत बंद कर देता। सभी अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। जो आनाकानी करते, उन्हें बर्खास्त कर देता।' समय आ गया है कि सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सभी निजी स्कूलों में भी प्रारंभिक शिक्षण मातृभाषा में अनिवार्य कर दिया जाए। एक समर्थ एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए यह अपरिहार्य है। उम्मीद है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर विचार करेगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महानता का रहस्य

शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विद्वान स्वामी रामतीर्थ के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग काफी प्रेरणादायी है। कहते हैं कि एक बार वे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के क्रम में उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर एक लाइन खींची और अपने शिष्यों से पूछा, 'इस रेखा को बिना स्पर्श किए हुए कौन छात्र इसे छोटा कर सकता है?' थोड़ी देर के लिए पूरी कक्षा शांत रही। प्रश्न गूढ़ था और इस कारण छात्र विस्मित थे। कुछ देर के बाद एक विद्यार्थी आगे बढ़ा और ब्लैकबोर्ड पर खींची गई रेखा के सामानांतर एक बड़ी-सी लाइन खींच दी। परिणामस्वरूप पहले वाली रेखा छोटी हो गई। इसके बड़े निहितार्थ थे।

इस उपक्रम की समाप्ति के बाद इसका सार समझाते हुए स्वामी रामतीर्थ ने अपने शिष्यों से कहा, 'जीवन में महानता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। न ही उसे अपमानित और नीचा दिखाने की आवश्यकता है, बल्कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे आध्यत्मिक, चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए कि सामने वाले को खुद का कद बौना प्रतीत होने लगे। इस प्रकार से हासिल महानता सर्वश्रेष्ठ और ऐसा महान व्यक्ति कालजयी होता है।'

लेकिन दुर्भाग्यवश हम व्यावहारिक जीवन में ऐसा कर नहीं पाते हैं और जीवन की अंतिम सांस तक दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ने की कोशिश में मन को दुखी करते रह जाते हैं। दूसरों के प्रति छल-प्रपंच, ईर्ष्या और द्वेष के जहर से खुद के जीवन की शांति का गला घोंट देते हैं। इतना ही नहीं गला-काट प्रतियोगिता के वर्तमान परिवेश में खुद को सफलता के शीर्ष पर देखने की अंधी चाह में हम पता नहीं कितनी कुत्सित योजनाएं बना बैठते हैं। मानवता के प्रति सद्भाव, प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति और अन्य मानवीय गुणों के अभाव में ही हम मर्यादित आचरण की सीमा लांघ जाते हैं। खुद को निरंतर परिमार्जित करते रहने, मानव मात्र के कल्याण के भाव के साथ धैर्यपूर्वक सात्विक और संयमित जीवन के जीने में ही सच्ची महानता का रहस्य छिपा होता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

धरती को बचाने की मुहिम

शशांक द्विवेदी

उम्मीद है कि विश्व के सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन पर तेजी से काम करेंगे, क्योंकि यह एक बेहद गंभीर समस्या है

दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप-25 सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश हिस्सा ले रहे हैं। इस बार यह स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। इस आशय का पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित हुआ था। सच्चाई यह है कि पर्यावरण सीधे-सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा मसला है। दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी बातें हो रही हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर उसका प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र करीब तीन दशक पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कोशिशों में जुट गया था, लेकिन कुछ देशों के रवैये के कारण उसके प्रयास अभी भी पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ सके हैं। कॉप-25 संयुक्त राष्ट्र का 25वां जलवायु सम्मेलन है।

इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी देशों को उनके वादों को याद दिलाना है जिसमें उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही थी। साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में दुनिया को आगाह करना और उससे निजात पाने के रास्ते खोजना है। संयुक्त राष्ट्र की तीन अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन, सूखा और चक्रवातों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे दुनिया के साढ़े तीन करोड़ लोगों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। 2017 में कार्बन उत्सर्जन में चीन पहले, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर थे। इसमें चीन की हिस्सेदारी 27.2 फीसद, अमेरिका की 14.6 फीसद, भारत की 6.8 फीसद और रूस 4.7 की फीसद थी। इस तरह से दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों का था। हालांकि कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर हुई है। भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो रहा है, बल्कि लक्ष्य पाने की दिशा में उसका काम 15 फीसद ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पिछले दो वर्षों में देश के कई इलाकों में बेमौसम बरसात और सूखे की वजह से किसान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

जाहिर है प्लास्टिक को ना कहने के साथ ही सौर, पवन जैसी वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देकर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी काबू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा तभी कुछ हद तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कुछ कमी आ पाएगी। कुल मिलाकर पिछले कई वर्षों से जलवायु सम्मलेन एक रस्म अदायगी बन कर रह गए हैं। फिर भी कॉप-25 सम्मलेन से एक उम्मीद है कि विश्व के सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन पर तेजी से काम करेंगे, क्योंकि यह एक वैश्विक और बेहद गंभीर समस्या है।

(लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं)

बेटियों की सुरक्षा

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सही है, लेकिन उन बेटियों की सुरक्षा भी अनिवार्य है। आज बेटियां जन्म भी ले रही हैं, पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, किंतु हम उनके सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन बेटियों के साथ अपराध की खबरें सुनने को मिलती हैं। हैदराबाद की घटना के बाद उन्नाव की बेटी को जमानत पर छूटे आरोपित ने जिंदा जला दिया। आखिर न्याय की जंग लड़ रही बेटी जीवन की जंग हार ही गई। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज की पहचान कभी नहीं हो सकतीं। समाज को ऐसे कुकृत्य पर शर्मसार होना चाहिए, लेकिन समाज के लोग एक बार संज्ञान लेते हैं फिर भूल जाते हैं। पुलिस-प्रशासन भी ऐसे मामलों में जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ढिलाई बरतते हैं। पुराने समय में बेटियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। पति के देहांत के बाद पत्नी भी अग्नि में जल कर सती हो जाती थी। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों के अथक प्रयास से समाज में जागृति आई और इन कुरीतियों से समाज को मुक्ति मिली। महिलाओं और बेटियों को भी बराबर का सम्मान मिलने लगा। आज फिर समाज में बेटियों की सुरक्षा की मुहिम चलाना आवश्यक हो गया है। समाज को आत्मचिंतन करना होगा कि क्या हम सभ्य समाज में रह रहे हैं। सरकार को भी कानून में बदलाव कर उसे और सख्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई अपराधी छूट न सके। ऐसे उपाय करने जरूरी हैं, जिससे ऐसे अपराध ही न हों। इसमें अहम भूमिका शिक्षा की है। ज्यादातर ऐसे जघन्य अपराध अशिक्षित वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। जन-जन तक शिक्षा का प्रसार करना करना जरूरी है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

मेलबाक्स

नागरिकता निर्धारण की कसौटी

संजय गुप्त का आलेख 'नागरिकता निर्धारण का सही तरीका' पढ़ा। अमेरिका में नागरिकता दिए जाते समय वास्प (डब्लूएएसपी-व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट) कसौटी का पालन किया जाता है। यानी वे लोग जो उत्तरी यूरोप से आने वाले श्वेत प्रोटेस्टेंट हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शेष लोगों को नागरिकता कानून के अंतर्गत 15 वर्ष निवास की अवधि पूरी करनी होती है। बाद में उनका संस्कृतीकरण यानी देशज संस्कृति में रंगने का काम किया जाता है। वास्प समुदाय अमेरिकी जीवन के साथ शीघ्र एकरूप हो जाता है। कोई समस्या पैदा नहीं करता। अतः वह वहां प्राथमिकता पाने वाला समुदाय है। इसी प्रकार भारत के मामले में वही स्थिति हिंदू एवं यहां उत्पन्न अन्य मतों-जैन, बौद्ध, सिख की है। ये सभी भारत को पुण्यभूमि मानते हैं। इससे भावात्मक संबंध महसूस करते हैं। पारसी भी 14 सौ साल से हिंदुस्तान से गहरा लगाव प्रगट करते आ रहे हैं। उनके व्यवहार से यह सिद्ध होता रहा है। ईसाई भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण शरणार्थी बनने के पात्र हैं। इसके विपरीत मुसलमानों को इस्लामी मुल्कों में किसी धार्मिक अत्याचार का शिकार नहीं बनना पड़ता है। सरकार ने जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर कोई कानून प्रस्तावित किया है।

अजय मित्तल, मेरठ

सुस्त न्याय प्रणाली

भारत एक ऐसा देश है जहां अपराधियों को भी सुधारने का मौका दिया जाता है। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन कभी-कभी हमको यह नियम कानून के ऊपर सोचने को मजबूर कर देता है। क्योंकि इन्हीं कानून की वजह से कभी-कभी दोषियों को सही वक्त पर सजा नहीं मिल पाती है। ऐसे में सरकार को इस पर कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय प्रणाली में तेजी आ सके।

satyamrai276304@gmail.com

नारी सम्मान

नारी आधुनिकरण के दौर में हर क्षेत्र में अव्वल है, परंतु उसका बराबरी के साथ चलना कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों को नागवार लगता है। प्रश्न तो समूचे समाज की व्यवस्था पर उठता है और यह सवाल बदलाव की अपेक्षा करता है। यह बदलाव उस मानसिकता को बदलने की कवायद को लेकर है जिसमें घर के भीतर से ही बेटी तथा बेटों के साथ बराबरी का व्यवहार निहित हो। अगर बेटी के लिए नियम कानून घर में है तो बेटों पर भी वह लागू हों। पाठ्यक्रम में ऐसे मूलभूत बदलाव लाए जाएं जिसमें नारी सम्मान का ज्ञान सम्मिलित हो।

anandche621@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

55 प्रतिशत लड़कियों को देश भर में इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके अभिभावक उन्हें छोटे-भाई बहनों को घर में समुचित तरीके से संभालने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं।

आजकल

डॉ. मोनिका शर्मा
स्वतंत्र टिप्पणीकार

चिंताजनक है लड़कियों को समग्र शिक्षा नहीं मिलना

देश भर में शिक्षा के मामले में लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार अब भी कायम है। हालांकि इसके कई कारण हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक पहलू इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। हाल ही में आई एक गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) की एक रिपोर्ट 'एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड' के मुताबिक घरेलू जिम्मेदारियां भी बेटियों की शिक्षा में बड़ी बाधा बन रही हैं। देश के चार हिस्सों से चुने गए चार राज्यों- बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा से 20-20 गांवों का अध्ययन करने पर सामने आया है कि देश में स्कूल जाने वाली बच्चियों में से 76 प्रतिशत और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों में से 90 प्रतिशत बच्चियां घरेलू कार्यों में शामिल होती हैं जिस कारण उन्हें समुचित शिक्षा नहीं हासिल हो पाती है

प्रतीकात्मक

हालिया जारी क्राई की एक रिपोर्ट बताती है कि समाज में लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराने के मामले में भेदभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल छोड़ने वाली हर चार लड़कियों में से एक घर के लिए पैसे कमाती है। हर दस में से एक लड़की घर में छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। नतीजन आज भी ऐसी लड़कियों की तादाद काफी है जो मुश्किल से प्राइमरी स्कूल तक ही जा पाती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 14 वर्ष की उम्र से पहले ही दो तिहाई बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं और आज भी महज 58 प्रतिशत बच्चियां उच्च प्राथमिक स्तर तक जा पाती हैं। सवाल यह है कि कम उम्र में ही ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ बच्चियों के हिस्से क्यों? आखिर शिक्षित होने और सबल बनने के मोर्चे पर बेटियां कब तक जूझती रहेंगीं? वो भी तब जबकि हमारे देश में स्त्रियों के जीवन से जुड़ी कई समस्याओं की वजह उनका शिक्षित न होना ही रहा है।

शिक्षा, जीवन में बदलाव व बेहतरी का सर्वोत्तम माध्यम है। सोच बदलने से लेकर सजग और सशक्त व्यक्तित्व गढ़ने तक शिक्षा की महती भूमिका है। भारत जैसे देश में तो महिलाओं की शिक्षा के आंकड़ों की अहमियत और बढ़ जाती है, जहां आधी आबादी को शिक्षित होने का बुनियादी हक पाने के लिए भी अनगिनत उलझनों से जूझना पड़ता है। स्कूल जाने और उच्च शिक्षा पाने तक, कितने ही पड़ावों पर भेदभाव भरा व्यवहार बच्चियों के हिस्से आता है। घर-परिवार के कामकाज का दायित्व भी उनकी पढ़ाई में बड़ी रुकावट बनता है। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति, सामाजिक असुरक्षा के चलते कम उम्र में शादी या छोटे भाई-बहनों की देखभाल जैसे कई कारणों से बेटियां समुचित शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। हमारे सामाजिक ढांचे में आज भी ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां और बंधन बिना सोचे-समझे बेटियों की झोली में डाल दिए जाते हैं। घर के कमजोर आर्थिक हालातों के कारण सबसे पहले बेटियों की पढ़ाई छूटती है। इस अध्ययन के मुताबिक 21 फीसद बच्चियों को पैसे की कमी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा है।

उल्लेखनीय है कि हमारे यहां स्कूल जाने वाली बच्चियों में से 49.4 फीसद उन परिवारों से हैं जिनकी आय पांच हजार रुपये प्रति माह या उससे कम है। ऐसे घरों में अधिकतर अभिभावक मजदूरी या खेती कर परिवार चलाते हैं। इसीलिए बेटियों को छोटे भाई-बहनों की देखभाल और दूसरे घरेलू कामों में लगा देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों में से 95.4 प्रतिशत, हरियाणा में 81.7, आंध्र प्रदेश में 72.7 और बिहार में 60 फीसद अभिभावक बच्चियों को घर के कामों में व्यस्त कर देते हैं। देश भर में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों में से 55 प्रतिशत लड़कियों को छोटे भाई-बहनों का ख्याल रखने के लिए स्कूल से दूरी बनानी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में 69.7 फीसद, गुजरात में 67.7 प्रतिशत, हरियाणा में 33.3 प्रतिशत और बिहार में 31.5 प्रतिशत लड़कियां इसी वजह से स्कूल छोड़ देती हैं। बचपन में ही बच्चों को संभलाने का दायित्व उन्हें घर की चहारदीवारी तक समेट देता है। यह वाकई चिंतनीय है कि घर-परिवार के ऐसे हालात बेटियों को स्कूल से दूर कर देते हैं।

हमारा सामाजिक ढांचा भी बेटियों की शिक्षा में बाधा बनता है। जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वे भी कहीं न कहीं बेटियों की पढ़ाई से ज्यादा उनके विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। गांवों-कस्बों में आज भी सामाजिक रूप से लड़कियों पर जल्द से जल्द घर बसाने का दबाव होता है। खासकर गरीब परिवारों के अभिभावक उनकी शादी कर एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होने की सोचते हैं। क्राई की इस रिपोर्ट में बिहार से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक स्कूल छोड़ने वाली सभी बच्चियों में से 20 फीसद बच्चियों के माता-पिता उनकी जल्दी शादी कराने के इच्छुक हैं। साथ ही गुजरात में 3.9, आंध्र प्रदेश में 21.2 और हरियाणा में 11.7 प्रतिशत माता-पिता बच्चियों की शादी जल्द करना चाहते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इसकी एक बड़ी वजह असुरक्षा के हालात भी हैं। दूर-दराज के इलाकों में स्कूल आते-जाते लड़कियों के साथ छेड़छाड़, और यहां तक कि दुष्कर्म की घटनाएं भी आए दिन सामने आती हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें बच्चियों के साथ बर्बर हादसे हुए हैं। देश भर में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में से 25.2 फीसद लड़कियां स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। अनहोनी का भय लड़कियों के स्कूल तक पहुंचने की हिम्मत पर भारी पड़ता है, जबकि अपने सपने साकार करने का अधिकार मिलना बेटियों के भावी जीवन की बेहतरी के लिए ही नहीं, व्यक्तित्व विकास के लिए भी जरूरी है। शिक्षित बेटियां अपने अधिकारों को लेकर भी सजग बन पाती हैं।

हालांकि बीते कुछ बरसों में महिला साक्षरता के आंकड़े बदले हैं और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी का ग्राफ बढ़ा है। हर क्षेत्र में शिक्षित बेटियों के बढ़ते आंकड़ों ने देश की अर्थव्यवस्था में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। सुखद है कि मौजूदा समय में बेटियां शिक्षित हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी। तकरीबन हर क्षेत्र में अपना दखल भी रखती हैं। पर बुनियादी स्तर पर उन्हें आज भी ऐसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो सामाजिक- पारिवारिक ढांचे में बदलाव आए बिना नहीं जीती जा सकती।

निस्संदेह इस बदलाव में हर परिवार की भूमिका तो अहम है ही, समग्र रूप से समाज की भागीदारी भी जरूरी है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात क्या होगी कि बेटियों की शिक्षा अपने ही घर के हालातों से जूझते हुए हाशिये पर चली जाय। बड़ों की जिम्मेदारियां निभाने में उन्हें शिक्षित होकर सम्मान और पहचान पाने का हक भी ना मिले, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा ना हो पाए। इसीलिए बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि घर के भीतर उनको ऐसे दायित्वों से मुक्त रखा जाय जो उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं। साथ ही समाज में भी समानता और सुरक्षा का माहौल बने, शैक्षणिक संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया जाय, ताकि बच्चियों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। हमें यह भी समझना होगा कि देश को महिला शिक्षा का लाभ केवल आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं मिलता, सामाजिक और पारिवारिक उन्नति में भी बेटियों की शिक्षा का बड़ा योगदान होता है।

आर्थिक भेदभाव से मुक्त हो शिक्षा

डॉ. गुंजन राजपूत
प्राध्यापक, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर

इसी वर्ष प्रकाशित नीति आयोग की स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार सरकारी स्कूलों के नामांकन अनुपात में भारी गिरावट आई है। इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन लंदन द्वारा जारी वर्ष 2017 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार भारत के सरकारी स्कूलों में नामांकन दर में गिरावट आई है। यहां पिछले पांच वर्षों में यह आंकड़ा 122 से 108 छात्र प्रति विद्यालय की दर से घटा है। इसके विपरीत निजी स्कूलों में यह संख्या 202 से बढ़कर 208 पहुंच गई है।

इसके अलावा यूडीआइएसई यानी यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 तक सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन नौ प्रतिशत तक गिर गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2015 की अवधि में कुल छात्र नामांकन में गिरावट नहीं हुई, वरन निजी स्कूलों के नामांकन में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो सरकारी स्कूल में घटी है। पिछले एक दशक में स्कूलों के स्वामित्व में भारी बदलाव हुआ है। निजी स्कूलों की वैसे तो विभिन्न श्रेणियां हैं, परंतु एक श्रेणी ग्रामीण और शहरी भारत में तेजी से बढ़ रही है, और वह है 'बजट निजी स्कूलों' की। ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ उत्कृष्ट निजी स्कूल हैं जहां समुचित आधारभूत संरचनाएं, अच्छे शिक्षक, कम शिक्षक-शिष्य अनुपात जैसे प्रबंधन होते हैं, परंतु यहां के शुल्कों का भुगतान करना हर किसी के बस की बात नहीं है।

इसके विपरीत सामाजिक बदलावों पर अध्ययन करने वाली एक संस्था एफएसजी की 'बजट प्राइवेट स्कूल' की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसे अधिकांश स्कूल एक मालिक या एक परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आज भी शुल्क संग्रह, शिक्षक भर्ती एवं आधारभूत संरचना जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद एफएसजी की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार ये बजट स्कूल निकटतम भविष्य में 60 लाख से एक करोड़ बच्चों को शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। इस बदलाव के व्यापक कारणों में भिन्नता है, लेकिन इसकी गहरी समझ हासिल करना भी आवश्यक है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा वर्ष 2018 की बजट प्राइवेट स्कूल पर की गई एक शोध रिपोर्ट बताती है कि इन स्कूलों की जगह-जगह पर पहुंच, अंग्रेजी पर जोर, कम शिक्षक अनुपस्थिति और स्कूलों की अधिक जवाबदेही, इन स्कूलों की प्रसिद्धि का कारण है। भारत जैसे देश में जहां 2.6 करोड़ बच्चे 15 लाख विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां शिक्षा गहन रूप से व्यक्तिगत हो चुकी है।

ऐसे में क्या हम इस 'बजट प्राइवेट स्कूलों' को विकसित करने में निवेश करेंगे या सरकारी स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? मुफ्त शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की तुलना में कमतर होते जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति समाज में बड़े पैमाने पर भेदभाव और शोषण को जन्म देती है। इससे समाज में एक विभाजक रेखा बन रही है जो पूरे समाज को विभाजित कर रही है। ऐसे में जहां एक साधन संपन्न अमीर वर्ग अच्छी गुणवत्ता को शिक्षा को 'खरीदने' में सक्षम है तो वहीं निम्न या मजदूर वर्ग किफायती स्कूलों पर शिक्षा के लिए निर्भर है।

हालांकि सरकारी ढांचे की मौजूदा दशा के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अब तो क्षेत्रीय सरकारी स्कूल केवल हाशिये के समुदाय के लिए ही बचे हैं, जहां के अभिभावक आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं हैं। ऐसे में हमें सरकारी ढांचे की जवाबदेही को मजबूत बनाना होगा जो कि इन सरकारी स्कूलों के ढांचे को कमजोर करता है। एक संबंधित विशेषज्ञ का कहना है कि निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माता-पिता को यह एहसास होना चाहिए कि सरकारी तंत्र उनके बिना कभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं करेगा।

फिनलैंड जैसा देश जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में विश्व में अग्रणी माना जाता है, उसने इस तथ्य को समझ लिया था कि विषम शिक्षा प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र के समानता के धागे को कमजोर कर देती है। शायद यही कारण है कि फिनलैंड ने इस संबंध में अपना नजरिया बदला और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। हमें भी इस विषय पर गौर करना चाहिए।

खरी-खरी

जलती-बुझती मोमबत्तियां

विजी श्रीवास्तव

चौराहे पर जाकर लोग अक्सर मोमबत्तियां जलाते रहते हैं। पर इससे उसे क्या मतलब! आज बुधिया खुश है कि उसे भी एक मोमबत्ती मिल गई। वह दौड़ती हुई झुग्गी में घुसी और मां के सामने अपनी नन्हीं हथेली फैला दी। मां ने पूछा- अरे वाह, इतनी बड़ी मोमबत्ती कहां से लाई तू? बुधिया ने बताया- चौराहे पर एक दीदी मोमबत्ती बांट रही थी, तो मैंने भी उनसे एक ले ली।

बुधिया के बाल मन में उठ रहे कई प्रश्नों का जवाब भी उसे चाहिए था। बोली- मां, लेकिन इतने सारे लोग उजाले में मोमबत्ती क्यों जला रहे थे? मां कहती है- वो बड़े लोग हैं। जब कुछ खास होता है, वे उजाला करते हैं। बुधिया बोली- हां उनके यहां जन्मदिन पर भी तो मोमबत्ती जलती है। मां ने सोचा यही मौका है बेटी को कुछ व्यावहारिक ज्ञान देने का- एक लड़की के साथ बुरा काम कर मार डाला था, उस पर नाराजगी जता रहे हैं ये लोग।

बुधिया बोली- अम्मा, बुरा काम क्या होता है। मां बोली- गंदे लोग जब दूसरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसे बुरा काम कहते हैं। बुधिया इतने में कहां संतुष्ट होने वाली थी- मां, मेरी सहेली कह रही थी कि हमारी बस्ती में भी इस साल दो लड़कियों को मार डाला था। बुधिया की बात पर मां को याद आया कि दो नहीं, कई लड़कियों की लाशें पुलिया के नीचे मिली थीं। बुधिया के प्रश्नों की बौछार नहीं थमी। बोली- मां उनके लिए किसी ने मोमबत्ती क्यों नहीं जलाई? मां के शब्दकोष में हैसियत और सभ्यता वगैरह शब्द थे ही नहीं, तो वो क्या बोलती। इधर बुधिया की वकालत जारी थी- अंधेरा होने पर तुम मुझे दुकान वाले अंकल के पास मोमबत्ती लेने भेजती हो न, तो वहां जो भैया हैं, वह भी मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। पर वह तो भोत अच्छे हैं। मुझे टॉफी भी देते हैं।

बुधिया की बात पर मां सन्न थी। वह दुकानदार से लड़ने जा सकती थी, उस लड़के की रिपोर्ट लिखवा सकती थी। मगर वह बोली- तू अब कभी वहां मत जाना।

मां को शायद डर है कि वह कुछ बोली तो उसे उधारी पर राशन मिलना बंद हो जाएगा। उस शैतान लड़के का बाप और बड़ा शैतान है, जो खुद उसके साथ छेड़छाड़ करता है।

अब बुधिया की मां मोमबत्ती की तरह जल रही थी और बेबसी का मोम पिघलकर उसकी आंखों से झर रहा था।

ट्वीट-ट्वीट

पुणे में इलाज करा रहे बीमार अरुण शौरी की कुशलक्षेम पूछने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए। वास्तव में राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। विरोधियों और आलोचकों की खैर-खबर लेते रहना चाहिए।
संजीव पालीवाल@sanjeevpaliwal

दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर जो ब्योरा सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि यह त्रासदी घटने के लिए अपना इंतजार ही कर रही थी। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम, दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह बात कितना सालती है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी हमारा तंत्र लोगों की जिंदगी नहीं बचा पाता।
राज बब्बर@RajBabbarMP

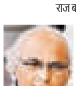

किसी भी देश के विकास का एक अहम पहलू यही है कि वहां बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। हैदराबाद के बाद हमें उन्नाव में भी शर्मसार होना पड़ा। यह शर्मनाक, संताप से भरा और संवेदनाशून्य होने की पराकाष्ठा है।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश डायरी

हम उदास हुए तो सियासत मुस्कुराई

उत्तर प्रदेश का मौसम यूं तो बढ़िया है, आजकल। गुलाबी ठंड और गुनगुनी धूप। किसान धान बेचकर रबी की बोआई में व्यस्त हैं। बहरहाल, कुदरत की इस तमाम मेहरबानी के बावजूद बलिया से बुंदेलखंड तक उदासी भी पसरी हुई है। उन्नाव की एक बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसने सबकी आंखें नम कर दीं। आम-ओ-खास, सब आहत हैं। दुखी हैं। गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं, पर बेटी की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इसके विपरीत बेहद शातिराना अंदाज में कुछ आंखें चमक रही हैं। मीडिया के कैमरे तलाश रही हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है, मानो यह हादसा उनके लिए अवसर जैसा है।

ये उन बड़े नेताओं की आंखें हैं जो हर वक्त सिर्फ सत्ता और कुर्सी के सपने देखने की आदी हैं। ऐसे कई नेता लोकसभा चुनाव के बाद से उदासी में डूबे चल रहे थे। कार्यकर्ताओं से मिलना-जुलना तक बंद कर रखा था। कई नेता दिल्ली से लखनऊ का रास्ता भूल गए थे। ऐसा लगने लगा था, मानो राजनीति से संन्यास ले लिया, पर उन्नाव का हादसा होते ही सब चैतन्य हो गए। दिल्ली वाले नेता झटपट लखनऊ आ गए और लखनऊ वाले नेता घर से निकलकर विधानभवन के द्वार तक आ पहुंचे। पीछे-पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम भी। कई महीने बाद नेताजी को सामने पाकर कार्यकर्ता धन्य हो गए और उत्साह में भ्रमवश 2012 से पहले वाले माइंडसेट में पहुंच गए। जीपीओ से लेकर भाजपा कार्यालय तक सपाई और कांग्रेसी शक्ति प्रदर्शन करने लगे। राहगीरों के साथ अभद्रता। जब अति हो गई तो पुलिस ने डंडे सीधे करके इनका बुखार उतारा।

कुछ नेता पीड़ित परिवार के जख्म गहरे करने उन्नाव जा पहुंचे और फोटो-बाइट करके ही लौटे। नेता लगभग अभिनेता ही होते हैं। उन्हें पता था कि हादसे पर प्रदेश गमगीन है, इसलिए वे भी गमगीन होने का अभिनय कर रहे थे, पर आंखों की चमक बार-बार होठों के कोनों पर फूट रही थी। यह ठीक है कि आम आदमी की याददाश्त

कमजोर होती है, पर इतनी भी कमजोर नहीं कि सपा संस्थापक का एक लड़की के दुष्कर्म हादसे पर सिर्फ कुछ वर्ष पहले वाला डायलॉग भूल जाए- 'लड़कों से गलती हो जाती है।' एक बड़े नेता की इस बेहयाई पर पूरी दुनिया ने थू-थू की थी, पर नेताजी या उनके उत्तराधिकारियों ने इसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। यह दुस्साहस नेता के अलावा शायद ही कोई कर सके कि ऐसी घटिया बात को भूलकर लड़कियों के सम्मान-सुरक्षा पर बयानबाजी करे। कांग्रेस नेताओं ने तो जिंदा लड़कियां तंदूर में भी झोंकीं, इसके बावजूद उसके नेता लड़कियों की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। मायावती के व्यवहार पर सब अंगुलियां उठाते हैं, पर इस प्रकरण में उनका व्यवहार मर्यादित एवं संजीदगी भरा रहा। वह राज्यपाल से मिलीं और उन्नाव हादसे पर अपनी पार्टी की राय एवं मांग से सबंधित पत्र सौंपा। इस हादसे पर जितना दुखी और शर्मिंदा हुआ जाए, कम है। सामाजिक शोक का अतिरेक विस्फोटक भी हो सकता था, पर योगी सरकार की संवेदनशीलता एवं सूझबूझ ने हालात काबू कर लिए। इस प्रकरण में अपनी विचित्र कार्यशैली को लेकर उन्नाव पुलिस कठघरे में हैं, यद्यपि इसी पुलिस ने लड़की को आग के हवाले किए जाने की हृदय विदारक वारदात के बाद आरोपितों को आनन-फानन में दबोचकर सरकार की फजीहत किसी हद तक बचा ली। 90 फीसद जली लड़की बचाई नहीं जा सकी, पर लखनऊ और दिल्ली में उसे श्रेष्ठतम इलाज दिलाया गया। उसकी मृत्यु के बाद परिवार की सहायता के लिए भी सरकार तत्पर दिखी। अंतिम संस्कार के समय प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। लड़की के जीवन का अंत करके आग अपना वीभत्सतम रूप दिखाकर ठंडी पड़ चुकी थी, अन्यथा बाइट-कैमरा प्रेमी नेताओं ने इसे हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहावत है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, वे इतिहास दोहराने को अभिशप्त होते हैं। उन्नाव हादसे की आंच पर सियासी रोटियां सेंकते नेताओं को देखकर लगा कि उन्होंने 2012, 2014, 2017 और 2019 के जनमत से कोई सबक नहीं सीखा। जाहिर है, ये दल और नेता 2022 और 2024 में इतिहास दोहराने को अभिशप्त हो रहे हैं। अभी भी समय है। हादसों को राजनीति का अवसर मानने की मानसिकता से उबरिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद का हिस्सा बनिए।

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और हिंदू-मुस्लिम समाज की राय के विपरीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करवाने की जिद पूरी कर ली। इस मुहिम में शामिल मुसलमानों के कुछ स्वयंभू नेताओं की मजबूरी समझी जा सकती है। वैसे इन नेताओं को अयोध्या के मुसलमानों ने इस छह दिसंबर को एक बार फिर आइना दिखा दिया, जब इनकी लाख कोशिश के बावजूद रामनगरी के मुसलमान शोक दिवस मनाने को राजी नहीं हुए। हिंदुओं ने कई दिन पहले ही शौर्य दिवस न मनाने की घोषणा कर दी थी। जिस हाशमी परिवार ने करीब 70 वर्ष बाबरी मस्जिद के लिए अदालती लड़ाई लड़ी, उसके मौजूदा मुखिया इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही इस राय पर कायम हैं कि यह फैसला देश के हित में है और इस पर पुनर्विचार याचिका जैसी कवायद उन कुछ लोगों की छटपटाहट मात्र है जो 1992 से अब तक इस मुद्दे पर धंधा-पानी चलाते रहे।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

न्यायिक प्रक्रिया में देरी हैदराबाद एनकाउंटर को मिले जनसमर्थन की एक वजह है?

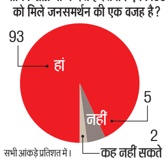

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दिल्ली में आग की घटना प्रशासनिक चूक का नतीजा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ऐसे जन ना जानते भ्रातृ-पुत्र का धर्म,
जो बन करके जानवर करते हैं दुष्कर्म।
करते हैं दुष्कर्म देश होता शर्मिंदा,
जलना तो इस दैत्य वंश को चहिए जिंदा।
इक मां अपना पूत देखती होगी कैसे,
नारी संग व्यवहार कर रहा है जो ऐसे!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

डॉ. गजेंदर सिंह
जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ

दवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर हो जोर

अणुओं की जटिल बनावट में सुधार कर या मौजूदा दवाओं के वर्गीकरण का विस्तार करने और अनेक दवाओं के नए-नए प्रयोग की खोज को इंक्रीमेंटल इनोवेशन में शामिल किया जा सकता है ताकि खास किस्म की दवाओं को अधिकतम प्रभावी बनाया जा सके

स्वास्थ्य रक्षा के विभिन्न पैमानों पर भारत की स्थिति निराशाजनक है। वर्ष 2020 तक गैर-संचारी रोग के 73 फीसद मामले मौत का कारण बनेंगे। डायबिटीज के तेजी से बढ़ते हुए रोग के तौर पर उभरने के साथ इसके करीब 50 फीसद रोगियों का बोझ भारत को उठाना होगा। आम तौर पर दूसरी सबसे बड़ी बीमारी के रूप में कैंसर भी ज्यादा पीछे नहीं है। जाहिर तौर पर इस रोग के बढ़ते बोझ का मुकाबला करने के लिए हमें नीतियों से आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए।

हालांकि, हम नए-नए आविष्कारों के बारे में यह सोचते हैं कि इससे रातोंरात बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस की एक संबंधित रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए नए आविष्कारों में से 70 फीसद आविष्कार इंक्रिमेंटल इनोवेशन की श्रेणी के तहत आते हैं। इंक्रिमेंटल इनोवेशन में मौजूदा दवाओं के वर्गीकरण के विस्तार की प्रक्रिया, दवा के विकल्पों की संख्या में बढ़ोतरी, पहले से बाजार में मौजूद दवाओं के रोगी के शरीर पर पड़ने वाले नए असर संबंधी खोज और मौजूदा दवाओं की माध्यमिक विशेषताओं में सुधार को शामिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अक्सर डॉक्टरों के अनुभवों और मरीज की जरूरतों पर आश्रित होती है। इंक्रिमेंटल इनोवेशन में मौजूदा दवाओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया के विस्तार को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए जटिल अणुओं की बनावट में सुधार किया जाता है। मरीजों की सेहत में जल्दी सुधार के लिए मौजूदा दवाओं को फिर से तैयार करने का नया फॉर्मूला ईजाद किया जाता है। उपलब्ध दवाओं के नए उपयोग की खोज की जाती है। उदाहरण के लिए दवाओं के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को सुधारने का एक तरीका यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि मरीज दवा की खुराक समय पर लें। रोग के बोझ को देखते हुए भारत को इस दिशा में पहले से अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

प्रतीकात्मक

स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए इंक्रिमेंटल इनोवेशन आज प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आखिर आज इसकी अहमियत क्यों इतनी बढ़ गई है। संक्षेप में कहा जाए तो स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में पहले से मौजूद दवाओं का प्रयोग साधारण और सर्वसुलभ बनाने की जरूरत है। दरअसल वर्ष 2050 में बुजुर्गों की आबादी भारत की जनसंख्या का लगभग 20 फीसद होगी। यानी अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज करना होगा, जिससे खर्च में बढ़ोतरी होगी। रेगुलर चेकअप कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी और बड़ी संख्या में मरीजों की देखभाल करनी होगी। चिकित्सा विज्ञान ने नए युग में प्रवेश कर लिया है, जहां नवीनतम तकनीक और नई रिसर्च से मरीजों की देखभाल का तरीका बदलता जा रहा है। उदाहरण के लिए कैंसर को लीजिए। वर्ष 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006-2016 के दौरान 10 साल की अवधि में कैंसर के इलाज में नवीनतम तकनीक की उपलब्धता में काफी असमानता देखी गई। कैंसर से लड़ने के लिए 270 दवाओं में से एक तिहाई भी भारत के पास नहीं थी। भारत में मेडिकल साइंस में प्रगति का अभाव इंक्रिमेंटल इनोवेशन की सख्त जरूरत को उभारता है। टीबी के इलाज में मौजूदा दवाओं में सुधार से मरीजों की मौत के मामलों में कमी आई है। इस संबंध में स्पष्ट नतीजों को उभारने के लिए जरूरत के अनुसार निवेश करने व ऐसी नीति बनाने की जरूरत होगी, जिससे प्रभावी इलाज के लिए नई दवाओं तक मरीजों की पहुंच अनिवार्य रूप से हो।

कई दशकों से मौजूदा दवाओं के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करने की नीति बनाने के क्षेत्र में कई रुकावटें थीं, जिससे दवाओं के शीर्ष वैश्विक आविष्कारकों में भारत का स्थान प्रभावित होता था। देश के सामने इस समय दवाओं के शोध और विकास के लिए पर्याप्त धन का प्रवाह न होना एक गंभीर मुद्दा है। भारत स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्रों में, जिसमें दवाओं का शोध और विकास भी शामिल है, विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले कम राशि खर्च करता है। हमें अपने फार्मास्युटिकल इनोवेशन इकोसिस्टम को विभिन्न आयामों में मजबूत करने की जरूरत है। जहां इंक्रिमेंटल इनोवेशन मौजूदा दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर रहा है, वहीं भारत अब भी बुनियादी समस्याओं से ही जूझ रहा है। दवाओं की घटिया क्वॉलिटी और खराब नीतियों से इंक्रिमेंटल इनोवेशन का ट्रेंड भारत में शुरू करने के रास्ते में रुकावट आ रही है। बीते वर्षों में ब्रांडेड जेनेरिक्स में छोटे-छोटे सुधार और अपग्रेडेशन से मलेरिया और टीबी के मरीजों के इलाज में नई तकनीक के शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इंक्रिमेंटल इनोवेशन से ही भारत में इलाज के खर्चे में कमी आई है। इससे जीवनस्तर में भी काफी सुधार आया है।

आज भारत को ऐसे माहौल की जरूरत है, जहां इलाज के लिए नई-नई और प्रभावशाली दवाएं मरीजों तक पहुंचे। इलाज के लिए अच्छी और प्रभावशाली दवाओं को जेनेरिक्स और ब्रांडेड जेनेरिक्स के पक्ष और विपक्ष तक सीमित नहीं करना चाहिए। बेहतर इलाज के लिए हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को प्रभावशाली दवाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह इलाज के लिए बेहतर दवाओं को चुन सके।

202 साल पुराने कोलकाता के हिंदू स्कूल में प्राथमिक स्तर पर अब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। स्कूल शिक्षा आयुक्त ने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि अगले अकादमिक वर्ष से स्कूल में बांग्ला के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 दिसंबर 2019

डाटागीरी

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वच्छ पेयजल की दरकार

स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पेयजल बेहद जरूरी है। आज इंसानों में होने वाली ज्यादातर बीमारियों की वजह दूषित जल बनता है। भारत के ग्रामीण इलाकों की बहुतायत आबादी अभी भी स्वच्छ पेयजल के लिए मोहताज है। अलग-अलग जगहों के पानी में पाए जाने वाले प्रदूषक विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में अभी भी 55,511 ग्रामीण बस्तियां के पेयजल में आयरन, आर्सेनिक आदि संदूषक बहुत मात्रा में मौजूद हैं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

भारत के विभिन्न राज्यों की कुल ग्रामीण बस्तियों में से 55,511 ग्रामीण बस्तियों के लोग खराब गुणवत्ता का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। संसद में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 27 नवंबर, 2019 तक स्थिति यह है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3.22 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों और ग्रामीण आबादी के कुल 3.73 प्रतिशत लोग कम गुणवत्ता के पानी का प्रयोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आयरन पानी में पाया जाने वाला प्रमुख संदूषक है, जिससे 18,000 से अधिक ग्रामीण बस्तियां प्रभावित हैं। इसके बाद खारापन (लवणता) है, जिससे लगभग 13,000 ग्रामीण बस्तियां के लोग प्रभावित हैं। वहीं, आर्सेनिक (12,000 बस्तियां), फ्लोराइड (लगभग 8000 बस्तियां) और अन्य भारी धातुओं से भी कई ग्रामीण बस्तियों के लोग प्रभावित हैं।

राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित : रिपोर्ट में राज्यों के हिसाब से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रामीण बस्तियां इससे प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 16,833 बस्तियों के लोग खराब पानी पीने को मजबूर हैं। इनमें से अधिकांश (12,182) बस्तियां खारे पानी से प्रभावित हैं।

बंगाल और असम में भी असर : रिपोर्ट के मुताबिक, आर्सेनिक और लौह प्रदूषक के मामले में बंगाल और असम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में कुल 30,000 ग्रामीण बस्तियां आर्सेनिक और लौह प्रदूषण से प्रभावित हैं, जिसमें से 20,000 बस्तियां केवल असम और बंगाल में हैं। बंगाल में आर्सेनिक से प्रभावित बस्तियां (6,207) सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद असम (4,125), बिहार (804), पंजाब (651) और उत्तर प्रदेश (650) हैं। लौह प्रदूषक से असम में सबसे ज्यादा बस्तियां (5,113) हैं। इसके बाद बंगाल (5,082), त्रिपुरा (2,377), बिहार (2,299) और ओडिशा (2,377) का नंबर आता है।

ये राज्य बेहतर : रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे राज्य जहां पर पेयजल किसी भी प्रकार के प्रदूषक से प्रभावित नहीं हैं, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

भारत में पेयजल की समस्या से ग्रसित बस्तियां (कुल 55,511)

आयरन	18,406
खारापन	13,255
आर्सेनिक	12,457
फ्लोराइड	7,873
भारी धातुएं	2,115
नाइट्रेट	1,405

आर्सेनिक से ग्रसित बस्तियां

बंगाल	6,207
असम	4,125
बिहार	804
पंजाब	651
उत्तर प्रदेश	650

लौह प्रदूषकों से ग्रसित बस्तियां

असम	5,113
बंगाल	5,082
त्रिपुरा	2,377
बिहार	2,299
ओडिशा	2,100

बक्सर में उतरा रहा कानपुर से गंगा में बहाया 'पाप'

सच सामने ▸ आनन-फानन की तैयारियां ही खोल रहीं प्रधानमंत्री की समीक्षा से पहले नमामि गंगे की पोल

प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कानपुर में गंगा की 'धुलाई' से निकली गंदगी बहकर पहुंची

राजीव द्विवेदी, उन्नाव

पोल खोल-पांच

नमामि गंगे समीक्षा की... जागरण पड़ताल

सरकार खुश हो, इसलिए अफसर गंगा की सफाई के लिए कागजी काम तो पूरा करते रहे, लेकिन गंगा की गोद में गिरने वाली गंदगी और जहर को रोकने के लिए जमीनी काम पूरा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधूरी कार्ययोजना बनी तो उन्नाव उससे भी आगे निकला। यहां योजना बनी, लेकिन उस पर अमल ही नहीं हुआ। अब जब पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और दस केंद्रीय मंत्रियों के साथ नमामि गंगे की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब आनन-फानन में तैयारियां हो रही हैं। ये तैयारियां ही पोल खोल रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए कानपुर में गंगा की 'धुलाई' में बहाया गया कचरा उन्नाव के अनवरत बहने वाले कचरे के साथ गंगा में बहता हुआ आगे जा रहा है। गंगा और पांडु के संगम से थोड़ा पहले बक्सर में दोनों जिले से बहाए गए ये पाप उतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कानपुर आने से पहले गंगा को निर्मल-अविरल दिखाने की पूरी कवायद की जा रही है। नरौरा से लेकर बैराज तक, हर स्तर पर गंगा में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसी ही कवायद उन्नाव में हो रही है। कानपुर सीमा से बांगरमऊ, सफीपुर, सिकंदरपुर सरोसी, सिकंदरपुर कर्ण, बीघापुर और सुमेरपुर ब्लाक से सटे 34 गांवों का सीवेज और गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। समीक्षा को देखते हुए उन्नाव के अधिकारी अब इसे बंद करने की कवायद में जुटे हैं। कानपुर से बहाई गंदगी उन्नाव के गांवों की यह गंदगी लेकर आगे बढ़ रही है।

शुक्लागंज और उन्नाव का सीवेज, फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी व औद्योगिक कचरा गंगा में जहर घोल रहा है। बंथर इंडस्ट्रियल एरिया के आगे गहरा गांव के पास जेल ड्रेन में गंदा पानी शहर के सीवेज के साथ औद्योगिक कचरे का सच लेकर बह रहा है। यह नाला जाजमऊ और बक्सर घाट के बीच में गंगा में गिरता है। यहां गंगा की रेती काफी कचरा सोख लेती है।

लोनी इतनी भारी हुई कि चल नहीं पाती : उन्नाव से निकली लोनी नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे से इतनी भारी हो चुकी है कि बहना तो दूर वह ढंग से चल नहीं पाती। दही चौकी इंडस्ट्रियल एरिया में लोनी ड्रेन रुकी सी दिखती है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह नदी केवल बरसात में ही रायबरेली सीमा के अंदर घुस पाती है। अन्य दिनों में इतनी भारी होती है कि रायबरेली सीमा के पहले ही सूख जाती है।

गांवों का पानी गड्ढे में : प्रधानमंत्री के दौरे के पहले प्रशासन ग्राम पंचायतों में गड्ढे खुदवाकर वहां गंदा पानी इकट्ठा करवा रहा है। पंचायतराज अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि गंगा किनारे के गांवों में गंदा पानी रोकने के लिए वहीं गड्ढे बनवाए गए हैं। नाली का पानी सूखे तालाबों में गिराया जा रहा है। माघ मेले को देखते हुए गंगा में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

उन्नाव में 2018 से नमामि गंगे : उन्नाव में दिसंबर 2018 में नमामि गंगे योजना के काम को स्वीकृति मिली। पूर्णता के लिए अक्टूबर 2021 का लक्ष्य मिला। इसमें जल निगम निर्माण खंड को दो एसटीपी एक उन्नाव और दूसरा शुक्लागंज में बनाना है, जिनकी लागत 167.35 करोड़ रुपये होगी। एक साल में एक एसटीपी की डिजाइन ही बनी है, जिसे आइआइटी रुड़की ने बनाया है। एक को एनओसी मिली है। डकारी के एसटीपी के लिए कोई काम नहीं शुरू हुआ है। उन्नाव एसटीपी से सिटी ड्रेन को जोड़कर शहर के छोटे-बड़े 48 नालों का पानी शोधन के लिए जाएगा। वहीं, शुक्लागंज में 65.18 करोड़ रुपये से पांच एमएलडी का एसटीपी बनेगा लेकिन यहां जमीन तक तय नहीं हो पाई है। देखी गई जमीनें मानक के अनुरूप न होने पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनओसी नहीं दी है।

वजीदपुर में बने 36 एमएलडी के कामन इफ्यलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में पड़ा टेनरियों से निकला कचरा। इस प्लांट में ड्रेनेज और टेनरी वेस्ट दोनों शोधित होते हैं। धीरज गुप्ता

गंगा में छोड़ा गया पानी (क्यूसिक में)

तारीख	नरौरा	कानपुर बैराज
30 नवंबर	1880	7451
03 दिसंबर	5728	5980
04 दिसंबर	5728	11557
05 दिसंबर	8862	8789
06 दिसंबर	8862	7459
07 दिसंबर	10395	13815
08 दिसंबर	13355	10516

उन्नाव में जमीन तय हो गई है और एनओसी मिल गई है। शुक्लागंज में जमीन खोजी जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनजीटी व आबादी के मानक पूरे होने पर ही एनओसी देगा।
– मोहित चक, अधिशासी अभियंता जल निगम निर्माण खंड

गंगा में गंदगी या नाले का पानी गिराना मना है। माघ मेले से पहले फैक्ट्रियों के नाले टेप कराए जाएंगे। गंगा में पानी बैराज से छोड़ा गया होगा, इसका प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है।
– राकेश सिंह, एडीएम

जीएनडीयू के वैज्ञानिकों ने ब्रेस्ट कैंसर की दवा विकसित करने में पाई सफलता

हरीश शर्मा, अमृतसर

- 12 साल की मेहनत के बाद एमर्जिंग लाइफ साइंस विभाग को मिली कामयाबी
- अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ने भी लगाई मुहर

अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (जीएनडीयू) के एमर्जिंग लाइफ साइंस विभाग ने 12 साल की रिसर्च के बाद ब्रेस्ट कैंसर को मात देने वाली दवाई तैयार की है। इसका चूहों पर प्रयोग सफल रहा है। अब दो तरह का कंपाउंड (दवा तैयार करने का मटीरियल व फार्मूला) अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर को भेजा गया है। अमेरिकी संस्थान ने इस पर मोहर लगा दी है। अब इसका मानव शरीर पर परीक्षण करने के लिए रिसर्च शुरू कर दी है।

जीएनडीयू के एमर्जिंग लाइफ साइंस विभाग के इंचार्ज प्रो. पलविंदर सिंह ने बताया कि यह रिसर्च 2006 में शुरू हुई थी। करीब पांच साल तक ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित अलग-अलग महिलाओं के केस स्टडी किए गए और उनमें कैंसर के कारणों का डाटा इकट्ठा किया। फिर चूहों में उसी तरह की बीमारी के ट्यूमर तैयार कर प्रयोग शुरू किए। सैकड़ों बाहर असफलता हाथ लगी। 2018 में करीब 12 साल की मेहनत रंग लाई और दो तरह की दवाई तैयार की। इसका चूहों पर परीक्षण किया। परिणाम अच्छा आया और चूहों से बीमारी खत्म होने लगी। फिर अमेरिकी इंस्टीट्यूट को दवाई तैयार करने का मटीरियल और फार्मूला भेजा गया। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अब दवा का मानव शरीर पर टेस्ट करने के लिए रिसर्च कर रहा है, ताकि कैंसर को खत्म किया जा सके।

...तो भारत होगा दुनिया का पहला देश : अमेरिकी इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट जीएनडीयू के साथ साझा करेगा। अगर मनुष्य पर भी टेस्ट सफल रहा तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, जिसने ब्रेस्ट कैंसर की दवाई की सबसे पहले खोज की।

पांच-पांच चूहों के कई ग्रुप बनाकर किया प्रयोग : प्रो. पलविंदर सिंह ने बताया कि मानव शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने या बढ़ने से कई ऐसे स्टेज हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का जीवाणु पैदा होने लगता है। उन सभी कारणों को लेकर मटीरियल तैयार किया गया था। बाद में पांच-पांच चूहों के कई ग्रुप बनाकर प्रयोग शुरू किए। इसमें धीरे-धीरे सफलता मिलती गई।

जीएनडीयू ने दोनों कंपाउंड पेटेंट के लिए भेजे : जीएनडीयू की टीम ने लंबी रिसर्च के बाद यह कंपाउंड तैयार किया है, इसलिए इसका पेटेंट करवाया जा रहा है। कंपाउंड पेटेंट के लिए भेजे गए हैं। इससे कोई दूसरा देश या इंस्टीट्यूट इस पर अपना दावा नहीं कर सकेगा।

अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। फाइल

अब हाथों से मोड़िए धूप

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ

- लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्र को मिली सफलता
- घर-प्रतिष्ठान की खिड़कियों के लिए शीशे का किया आविष्कार
- रिमोट से बदलेगा ग्लास का रंग और पारदर्शिता

कभी-कभी घर और दफ्तर में बैठे-बैठे धूप चुभने लगती है। आपको उठकर पर्दा गिराना पड़ता या जगह बदलनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपनी जगह बैठे-बैठे ही आप धूप का रुख बदल सकते हैं। यह खिड़कियों में लगने वाले विशेष ग्लास और एक रिमोट के जरिये संभव होगा। यह आविष्कार लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के शोध छात्र गोविंद पाठक ने किया। इस ग्लास में आप इच्छानुसार रंग और अवस्था बदल सकते हैं। ग्लास को पारदर्शी अवस्था देकर दिन में उजाला और रात में खूबसूरती का आनंद भी ले सकते हैं।

इस तरह ईजाद की डिवाइस : गोविंद पाठक ने बताया कि लिक्विड क्रिस्टल में नैनो पार्टिकल और पॉलीमर मिलाकर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एवं स्मार्ट विंडो को तैयार किया गया है। इस विधि में लिक्विड क्रिस्टल के मिश्रण को दो ग्लास स्लाइड्स के बीच भरकर अल्ट्रावायलट किरणें डाली जाती हैं। यह ग्लास कंडक्टिंग होने के चलते विद्युत से प्रभावित होते हैं। यह तापमान से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग किया जाना वाला पदार्थ थर्मोट्रॉपिक होता है, जो तापमान के साथ रंग और अवस्था बदलता है। इस डिवाइस में विभिन्न प्रकार की आकृतियां फोटो आइसोमराइजेशन से बनाई जा सकती हैं, जिससे कंपनी को ग्लास पर लोगो डिजाइन करने में आसानी होगी। चूंकि लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ कम ऊर्जा पर संचालित होते हैं, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण में भी सहायक साबित होगा।

इस तरह किया जा सकता है प्रयोग : इमारत की खिड़कियों पर यह डिवाइस लगाकर इसे रिमोट से संचालित किया जा सकेगा। इस विद्युत रिमोट से लिक्विड क्रिस्टल के अणु दिशा बदलते हैं और शीशे के अंदर होने वाले रासायनिक क्रिया उसे पारदर्शी से अपारदर्शी और फिर अपारदर्शी से पारदर्शी बना देंगे। इसका प्रयोग जल्द ही कार के शीशों और सेना के जवानों द्वारा पहने जाने वाले हेलमेटों में भी किए जाने की तैयारी है। गोविंद का कहना है कि भारत जैसे देश जहां अलग-अलग मौसम में तापमान में अंतर बहुत अधिक हो जाता है, वहां ये डिवाइस उपयोगी साबित होगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्र गोविंद पाठक। जागरण

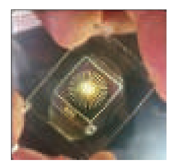

वह डिवाइस, जिसे गोविंद पाठक ने तैयार किया है। जागरण

मिल चुका है यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड

लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध छात्र रहे गोविंद पाठक जल्द ही बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज संस्थान में रिसर्च एसोसिएट पद पर अपनी सेवाएं देंगे। वर्ष 2018 में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंसेज (आइएपीएस) द्वारा यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड से भी नवाजा गया है। वह सफलता का श्रेय लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव मनोहर और डॉ. अतुल श्रीवास्तव को देते हैं।

एनआरसीई ने विकसित की सर्रा रोग के उपचार की विधि

वैभव शर्मा, हिसार

- टेबेनस मक्खी के कारण फैलता है यह रोग, पशुओं के खून में ट्राईपैनसोमा-इवेनसाई नामक परजीवी छोड़ती है मक्खी
- इस बीमारी से देश में हर साल 400 करोड़ रुपये के पशुधन की होती है हानि

देश में घोड़ों, गाय, भैंस, ऊंट जैसे अन्य पालतू जानवर हर साल सर्रा नामक बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। संक्रामक टेबेनस मक्खी से फैलने वाले इस रोग के कारण पशुओं में खून की कमी, कार्य क्षमता में कमी, गर्भपात आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस बीमारी पर पिछले लंबे समय से हरियाणा के हिसार जिले के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र कुमार अध्ययन कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस रोग के उपचार के लिए विभिन्न तकनीकें विकसित की हैं, जिसमें एलाइजा विधि, पीसीआर विधि व आरटी पीसीआर विधि शामिल हैं। इन तकनीकों की मदद से जल्द से जल्द रोग की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही अब इस रोग से पशुओं को निदान दिलाने के लिए नई और बेहतर दवाओं के खोज पर अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

इन राज्यों में ज्यादा मिलते हैं इसके केस: एनआरसीई के निदेशक डॉ. बीएन त्रिपाठी बताते हैं कि सर्रा रोग के अधिकांश मामले गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में हर साल मिलते हैं। खास बात है कि अभी तक यह भी नहीं पता था कि इससे कितने धन की हानि होती है। एनआरसीई की रिसर्च में सामने आया कि देश में 4000 करोड़ रुपये का पशुधन प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो जाता है। वहीं, सर्रा रोग भारत, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिणी चीन, जावा, फिलीपींस, ईरान और अरब देशों में पाया जाता है।

सर्रा रोग के लक्षण : टेबेनस मक्खी जब परजीवी को जानवर में छोड़ती है तो यह परजीवी लसिका उत्तकों में विभाजित होते हैं और विभाजन के बाद ये परजीवी इन्हीं ऊतकों में अपना स्थान बना लेते हैं। बाद में परजीवी जानवर के परिसंचरण तंत्र को धीरे-धीरे समाप्त करने लगता है। इसके कारण पहले पशुओं को बुखार आता है। बाद में कमजोरी, पशु आहार लेना बंद कर देता है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। पशुओं के पैरों, छाती और पेट पर सूजन आ जाती है। खून की कमी के कारण इस रोग में त्वचा का रंग भी प्रभावित होता है और पीलिये की स्थिति बन जाती है। इस रोग में जब परजीवी शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है तो इन अंगों में रक्तस्राव होने लगता है और एनीमिया की स्थिति बन जाती है। इस रोग के कारण पशुओं के पिछले पैरों में पक्षाघात हो जाता है। रोग की तीव्र अवस्था में ज्यादातर एक से दो सप्ताह के बीच पशु की मृत्यु हो जाती है।

ट्राईपैनसोमा-इवेनसाई नाम के परजीवी से होता है रोग

टेबेनस मक्खी में ट्राईपैनसोमा-इवेनसाई नाम का परजीवी पाया जाता है। इन मक्खियों का चक्रित विकास न होने के कारण यह एक-एक कर पशु का रक्त चूसती हैं। इस तरीके से परजीवी को एक पशु से दूसरे पशु में फैलाता जाता है। बरसात के मौसम में इस मक्खी के अधिक प्रजनन के कारण यह रोग अधिक फैलता है। यह रोग अगस्त के अंत से शुरू होकर शीत ऋतु तक चलता है। संक्रमित जानवरों में तनाव की स्थिति में यह रोग जल्दी पनपता है। इस रोग को फैलने का मुख्य कारण टेबेनस मक्खी को माना जाता है।

मदरसों के बच्चों को भी सिखाई जाएगी संस्कृत और फ्रेंच

डीपी आर्य, सोनीपत

- पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के सोनीपत शहर के मदरसे से होगी शुरुआत
- भवन बनकर तैयार, नए सत्र से शुरू होंगी कक्षाएं

मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते भी सुनाई देंगे। यही नहीं संस्कृत के साथ यहां के बच्चे फ्रेंच और अंग्रेजी में भी बातचीत करते दिखाई देंगे। मदरसा प्रबंधन बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के सोनीपत के जामियातुल इमाम अहमद अस-सरहिंदी अल-इसलामिया मदरसा से इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मदरसा कैंपस में भवन बनकर तैयार हो चुका है। नए सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी।

सोनीपत के ईदगाह कॉलोनी स्थित मदरसे के प्रधानाचार्य मौलाना मुहम्मद इमरान रब्बानी मदनी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मदरसा बोर्ड ने उनके मदरसे का चुनाव किया है। यहां बच्चों को संस्कृत, फ्रेंच व अंग्रेजी भी सिखाई जाएंगी। इसमें केवल मुस्लिम छात्रों को ही शिक्षा दी जाएगी। मदरसे में होने वाली संस्कृत की पढ़ाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता दी जाएगी, जबकि फ्रेंच और अंग्रेजी बोलचाल (स्पीकिंग) का प्रमाणपत्र अहमदाबाद मदरसा बोर्ड देगा। नए सत्र से इन तीनों भाषाओं की तालीम मदरसे में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्कृत पढ़ाने के लिए आचार्य अहमदाबाद से आएंगे। इसके लिए अहमदाबाद के प्रोफेसर एसएस पांडेय से करार किया गया है। अभी दिल्ली के एक मदरसे में फ्रेंच व अंग्रेजी बोलने की शिक्षा दी जा रही है।

प्रधानाचार्य मौलाना मदनी का कहना है कि इस्लाम में किसी जुबान, तहजीब या भाषा की तालीम पर रोक नहीं है। हमको तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है। मुस्लिम युवाओं को दीनी तालीम के साथ ही ऐसी दुनियावी तालीम भी देनी होगी, जिससे वह दुनिया के किसी भी मुल्क में रोजगार पा सकें। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अब संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की तालीम को शुरू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मदरसे के छात्रों को तो इसकी तालीम दी ही जाएगी। किसी दूसरे स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र भी यहां से तालीम पा सकेंगे।

मध्य प्रदेश के भीकनगांव में तेल-गैस मिलने के संकेत

सेटेलाइट के माध्यम से ओएनजीसी की टीम ने शुरू की खोज

नईदुनिया, भीकनगांव

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील सहित आसपास के क्षेत्रों में तेल व गैस की संभावनाओं को देखते हुए ओएनजीसी ने खोजबीन शुरू की है। जांच के लिए ओएनजीसी का विशेष दल चार दिन से यहां डेरा डाले हुए है। यहां खोदाई करके तेल व गैस के भंडारों का पता लगाया जा रहा है।

अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड के जिगनेश पटेल ने बताया कि जिन किसानों के खेत में ये होल किया जा रहा है, उनकी सर्वे रिपोर्ट तत्काल बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिन में किसानों के खाते में मुआवजा राशि जमा की जाती है। यदि किसान के खेत में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो उनकी निर्धारित जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों के परिवार में शिक्षित व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति न हो तो उन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी कि यहां से निकले नमूनों की जांच के लिए उन्हें कहां भेजा जाएगा और किस तरह से तेल-गैस का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

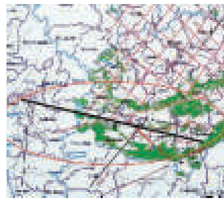

मप्र के भीकनगांव में नक्शे में लाल घेरे में बनी काली लाइन, जिस पर सर्वे किया जा रहा है। नईदुनिया

हैदराबाद भेजेंगे मिट्टी व रिपोर्ट

जिगनेश पटेल ने बताया कि भीकनगांव क्षेत्र में कई स्थानों पर मशीनों की सहायता से कार्य प्रारंभ कर दिया है। जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक खनिजों की जांच की जाएगी। इस दौरान मिली मिट्टी व अन्य तत्वों को जांच के लिए हैदराबाद लैब में भेजा जाएगा। आधुनिक तकनीक द्वारा जीपीएस और गूगल मैप की सहायता से यह कार्य किया जा रहा है।

इस तरह से लगाया जाता है पता

पटेल ने बताया कि जमीन में होल करते समय सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। तीन-तीन किमी की दूरी पर 200 फीट गहरा गड्ढा किया जा रहा है। संभावना होने पर तीन किमी के बीच 60-60 मीटर की दूरी पर 90 फीट गहरा गड्ढा किया जाता है। इसके बाद सेंसर लगाकर नियंत्रित विस्फोट किए जाते हैं। विस्फोट के समय केबल युक्त सेंसर से 15 से 20 किमी क्षेत्र में जो कंपन पैदा होता है उससे आंकड़े जुटाए जाते हैं। विस्फोट से उत्पन्न तरंगें धरती के भीतर करीब छह किमी तक जाती हैं। तरंगें भूगर्भ से होकर लौटती हैं तो इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनमें खनिज, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोकार्बन व कच्चे तेल का आकलन किया जा रहा है।

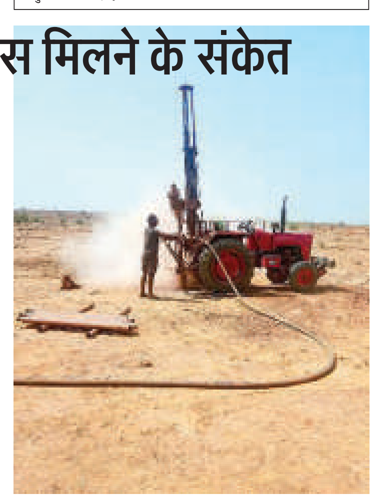

मप्र के भीकनगांव में तेल व गैस भंडार का पता लगाने के लिए किया जा रहा है होल। नईदुनिया

150 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोल प्लांट झारखंड के रांची में रूक्का डैम में लगाया जाएगा। अब तक केवल केरल में महज दो मेगावॉट और महाराष्ट्र में 500 किलोवॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है।

एचआइवी के रेड रिबन को ग्रीन कर रहा 'सिनी'

रंग ला रहे प्रयास ▶ निचले स्तर पर सरकारी तंत्र के क्षमता संवर्धन में 2002 से जुटा है चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट

विनोद श्रीवास्तव, रांची

स्वस्थ समाज

झारखंड में 2002 से कार्यरत चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी) की पहुंच आज राज्य के करीब छह लाख बच्चों के बीच है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के मानकों पर बच्चों को विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए सिनी जहां गांव स्तर पर कार्यरत सरकारी तंत्र के निचले पायदान को तकनीकी सहयोग दे रहा है, वहीं उनकी क्षमता का संवर्धन भी कर रहा है। बच्चों से संबद्ध सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी अंतिम स्तर तक पहुंचाने की कोशिश है। इसी कड़ी में सिनी ने एचआइवी ग्रसित माताओं के बच्चों को एचआइवी निगेटिव करने में 95 फीसद तक सफलता पाई है।

पांच वर्ष तक के बच्चों की समुचित देखभाल परिवार में ही हो, सिनी इसे सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही किशोरावस्था में उचित पोषण के माध्यम से एनीमिया से बचाव, स्वच्छता आदि की जानकारी दे रहा है। लैंगिक आधारित हिंसा और भेदभाव, बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि के खिलाफ पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता सिनी की कार्ययोजना में शामिल है। स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए गर्भवती माताओं की समुचित देखभाल जरूरी है, इसे केंद्र में रखकर सिनी सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से हर स्तर की सुविधाएं उन तक पहुंचा रहा है।

कुपोषण जांच केंद्रों में विशेष देखभाल : संस्था के प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर सुमंत्र के अनुसार, किसी भी कार्यक्रम अथवा परियोजना की सफलता के लिए जरूरी है कि उससे जुड़ी नीतियों के तंत्र को मजबूत किया जाए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे (एसआरएस 2017) का हवाला देते हुए सुमंत्र बताया कि 1000 में से 30 बच्चों की मौत जन्म लेते ही हो जाती है। इनमें से दो तिहाई कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण जांच केंद्रों (एमटीसी) में ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल होती है, परंतु जानकारी के अभाव में कई अभिभावक इसका लाभ नहीं उठाते। सिनी अपने नेटवर्क के जरिये ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें केंद्र तक ले जाने में मदद कर रहा है।

प्रतीकात्मक

माताओं की काउंसिलिंग का असर

बोकारो के कुछ क्षेत्रों में कम वजन के बच्चों के जन्म लेने की सूचना आम थी। सिनी ने जब इसकी पड़ताल की, बारू पंचायत में प्रथम दृष्टया ऐसे चार मामले सामने आए। 11 मार्च को जन्म लेने वाली एक बच्ची का वजन महज डेढ़ किलोग्राम था। इससे इतर चार मई को जन्मी एक और बच्ची, 26 मई को जन्मे दो बच्चों का वजन क्रमश : दो, 1.6 और 2.3 किलोग्राम था। सिनी की टीम ने लगातार दो महीने तक संबंधित बच्चों की माताओं की काउंसिलिंग की। उन्हें कंगारू मदर केयर तथा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जानकारी दी गई। इसका काफी सकारात्मक प्रभाव दिखा और बच्चों का वजन सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ गया।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

उत्तराखंड में खनन नीति के मानकों में बदलाव की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में एक बार फिर खनन नीति के मानकों में बदलाव की तैयारी है। खनन कारोबारियों द्वारा स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट की नदी से दूरी के मानक में इसे बढ़ाने के अनुरोध पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसके बाद शासन में इस पर कवायद तेज हो गई है।

प्रदेश में खनन का बहुत बड़ा कारोबार है। यह राजस्व देने वाले मुख्य विभागों में शामिल है। खनन के पट्टों के वितरण को लेकर बीते वर्षों में उठे सवालों को देखते हुए खनन पट्टों की नीलामी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में पट्टों की नीलामी की बात कही गई। शुरुआत में तो विभाग ने दावा किया कि इससे उसे खासा मुनाफा हुआ है, लेकिन जब पट्टों को लेने का समय आया तो खनन कारोबारियों ने इन्हें उठाने से हाथ पीछे खींच दिए। खनन कारोबारियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखते हुए शासन ने अक्टूबर अंत में नीति में बदलाव किया। माना गया कि इससे कार्य गति पकड़ेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब खनन कारोबारी नई नीति के कुछ बिंदुओं को लेकर कारोबारियों ने फिर आपत्ति जताई है। इस पर नवंबर में हुए कैबिनेट की बैठक में कुछ संशोधन किए गए।

हल्का होगा तोप के गोलों को ले जाने वाला बॉक्स

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

आइआइटी कानपुर में तैयार किया गया पैकिंग स्ट्रक्चर। सौजन्य : आइआइटी

तोप के खाली गोलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बॉक्स अब इतना हल्का होगा कि उसमें डेढ़ टन गोले अधिक पैक किए जा सकेंगे। आइआइटी कानपुर ने पॉली एथिलीन मैटेरियल का एक ऐसा पैकिंग स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे न केवल अधिक सामग्री ले जाई जा सकेगी बल्कि उन्हें ले जाना भी सुरक्षित होगा। गोले बनाने वाली कंपनियों को जल्द ही इसका लाभ मिलने लगेगा।

अभी स्टील के बॉक्स में खाली गोलों को भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। एक बॉक्स में 30-30 किलो के दो गोले रखे जा सकते हैं, जबकि एक ट्रक में इन गोलों का सात टन वजन आता है। ऐसे में तीन टन वजन के स्टील के बॉक्स में चार टन के खाली गोले रखे जा सकते हैं। आइआइटी के मैटेरियल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, डिजाइन के प्रोफेसर गिरिजेश माथुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रो. बिशाख भट्टाचार्या, प्रो. जे. रामकुमार, गणित विभाग के शिव्यांश टंडन व बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के चेतन लोधी ने दो साल शोध के बाद पॉली एथिलीन मैटेरियल का ऐसा पैकिंग बॉक्स बनाया है, जिसमें साढ़े पांच टन वजन के खाली गोले रखे जा सकते हैं। इसकी पैकिंग का वजन तीन टन की बजाय महज डेढ़ टन यानी आधा होगा। प्रो. गिरिजेश माथुर ने बताया कि अधिक गोले ले जाने की क्षमता के चलते जो काम तीन ट्रक से लिया जाता था, उस काम के लिए दो ट्रक ही पर्याप्त होंगे। स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पॉली एथिलीन प्लास्टिक मैटेरियल का होने के बाद भी इस पर गोलों का वजन भी नहीं पड़ेगा। वह अपना वजन अपने ऊपर ही ले लेता है, जिस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक के ऊपर एक रखकर भेजी जाती हैं, उसी तरह खाली के अलावा भरे गोले भी रखे जाएंगे।

करतारपुर कॉरिडोर का एक माह पूरा, नहीं बढ़े श्रद्धालु

- **9** नवंबर को भारत में पीएम मोदी और पाक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था उद्घाटन
- **5** हजार श्रद्धालुओं को रोज दर्शन करने पर बनी थी सहमति
- **1745** श्रद्धालु सबसे ज्यादा गए हैं अब एक दिन में
- **10-15** फीसद श्रद्धालु दीदार से वंचित रह जाते हैं रोज

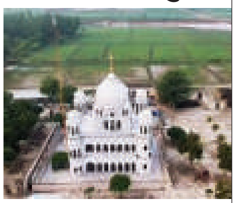

गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। फाइल

महेंद्र सिंह अर्लीभन्न, गुरदासपुर

भारत-पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौते के बाद बनाए गए करतापुर कॉरिडोर को एक महीना पूरा हो गया है। नौ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत व पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान से इसका उद्घाटन किया था। उनके ऐसा करने से दुनियाभर में फैले सिख श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी अरदास साकार हुई और सिख इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया था। नौ नवंबर से ही गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के खुले दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। रास्ता खुले 30 दिन हो गए हैं। श्रद्धालुओं की खुशी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लैंडपोर्ट अथॉरिटी की ढीली कार्यशैली व कड़ी शर्तों के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। कॉरिडोर के तीस दिन पूरे होने पर इससे जुड़े अहम पहलुओं पर एक नजर :-

एक महीने में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन : करतारपुर साहिब के दर्शनों की अभिलाषा हर एक सिख के मन में है, लेकिन पासपोर्ट की शर्त के कारण हजारों संगत चाहकर भी इसे पूरा नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि दोनों देशों में रोज पांच हजार श्रद्धालुओं के दर्शन करने पर जो सहमति बनी थी, वह आंकड़ा आधा भी नहीं हो रहा। रास्ता खुलने के बाद एक दिसंबर ही ऐसा दिन रहा, जब एक दिन में सबसे अधिक 1745 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण अब भी अधूरा : पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उद्घाटन से पहले इसके 31 अक्टूबर तक पूरा होने का समय तय किया गया था। यही कारण है कि रास्ता खुल गया और सबसे अहम हिस्सा पैसेंजर टर्मिनल अब भी अधूरा है। निर्माण मुकम्मल न होने के कारण इसमें ड्यूटी कर रहे कस्टम विभाग के अधिकारी और स्टाफ, सुरक्षा एजेंसियों समेत इमिग्रेशन के इलावा श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

टर्मिनल की छोटी पार्किंग बनी समस्या : श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु तेजबीर सिंह, महंगा सिंह, हरप्रीत सिंह, सरबपाल सिंह ने बताया कि दोनों देशों में रोज पांच हजार यात्रियों के जाने पर सहमति बनी है, लेकिन उस हिसाब से पैसेंजर टर्मिनल की पार्किंग काफी छोटी है। एक समय पर केवल एक हजार श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग है। पिछले दिनों जब 1745 श्रद्धालु पहुंचे तो बहुत से लोगों को बाहर सड़क पर ही वाहन लगाने पड़े थे।

इन हस्तियों ने किए अब तक दर्शन : एक महीने में दस हजार से ज्यादा श्रद्धालु नतमस्तक हो चुके हैं। इनमें सबसे उम्रदराज पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल हैं। वहीं, सबसे छोटी उम्र की श्रद्धालु लुधियाना की बिलावल कौर हैं। उसकी उम्र महज चार माह है। इसके अलावा कॉरिडोर के रास्ते पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सांसद और शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, मनीष तिवारी व भगवंत मान, फिल्म स्टार सनी देयोल और विधायक नवजोत सिद्धू, गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी के बाबा बलबीर सिंह, 17वीं पीढ़ी के बाबा सुखदीप सिंह बेदी ने भी दर्शन किए।

कई श्रद्धालु नहीं कर पाते दर्शन : पाकिस्तान की ओर से दी जाने वाली मंजूरी के बावजूद कई श्रद्धालु ऐसे हैं, जो गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब नहीं जा पाते। रोज 10-15 फीसद श्रद्धालु इसके दीदार से वंचित रह जाते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। पाकिस्तान से सूची उनको भेजने के अलावा इमिग्रेशन करतारपुर पैसेंजर टर्मिनल पर भी भेजी जाती है, लेकिन पुलिस इन्क्वायरी के अलावा ईटीए फॉर्म, दस्तावेजों में त्रुटियों और लेट होने के कारण बड़ी आपत्ति लगा दी जाती है। कई बार उनको टर्मिनल में ही रोक दिया गया। इसलिए वे दर्शन नहीं कर सके।

युवा वकीलों का 'लीगल क्लीनिक' दिला रहा इंसाफ

जागरण विशेष ▶ मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुहैया कराते हैं मुफ्त कानूनी मदद

दो महीने में 100 से ज्यादा लोगों को पहुंचा चुके हैं फायदा

कुलदीप भावसार, इंदौर

'क्लीनिक' शब्द सामने आते ही जेहन में सफेद कोट पहने किसी डॉक्टर का चेहरा सामने आ जाता है, जिनके पास लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे क्लीनिक भी हो सकता है जहां प्रवेश करते ही आपका सामना सफेद कोट वाले डॉक्टर से नहीं, बल्कि काला कोट पहने वकीलों से हो। जहां आपको गोली-दवाई नहीं, बल्कि कानूनी मदद मिले, वह भी पूरी तरह से मुफ्त। शहर में ऐसा ही 'लीगल क्लीनिक' चल रहा है। युवा वकील और सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रहे 40 से ज्यादा लोग इसे चलाते हैं। दो महीने पहले शुरू हुए इस 'लीगल क्लीनिक' से अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मदद मिल चुकी है।

यह लीगल क्लीनिक चल रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मध्य स्थित राधा नगर कॉलोनी में। हर शनिवार शाम छह बजे से यहां जरूरतमंद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन लोगों को मुफ्त कानूनी परामर्श दी जाती है। क्लीनिक में सीनियर वकील भी हैं जो युवा वकीलों के कामकाज का आकलन करते हैं। संस्था न्यायाश्रय के बैनर तले चलने वाले इस क्लीनिक की शुरुआत करीब दो महीने पहले हुई है। संस्था के वकील पंकज वाधवानी के मुताबिक, 2016 में संस्था की स्थापना के बाद से यह आभास होने लगा था कि पैसों के अभाव में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है।

न्यायालय में ऐसे लोगों की मदद के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण तो है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। संस्था से जुड़े वकीलों ने शुरुआत में गरीब बस्तियों में जाकर लोगों में कानूनी जागरूकता लाने का प्रयास किया, लेकिन यह नाकाफी रहा। इसके बाद संस्था से जुड़े लॉ स्टूडेंट्स, वकील और सीनियर वकीलों ने 'लीगल क्लीनिक' शुरू करने का फैसला लिया। इनमें सिविल जज परीक्षा की तैयारी करने वाले, कानून के अंतिम वर्ष के छात्र, सरकारी वकील, सीनियर वकील आदि शामिल हैं।

पूरे सप्ताह करते हैं प्रचार : क्लीनिक में सेवा दे रहे वकील राहुल सुखानी, जयंत दुबे, अभिषेक भार्गव ने बताया कि क्लीनिक के सदस्य कोर्ट में रोज के कामकाज के साथ ही जरूरतमंद लोगों को संस्था की जानकारी भी देते हैं। ऐसे लोग जो पैसों के अभाव में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाते उन्हें क्लीनिक का पता देकर शनिवार को संपर्क करने को कहा जाता है। क्लीनिक में उनकी समस्या सुनने के बाद संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले क्लीनिक के सदस्य (वकील) को वह केस सौंप दिया जाता है। क्लीनिक के सदस्य राशि एकत्रित कर संस्था के माध्यम से फीस व अन्य खर्च वहन करते हैं।

चक्कर काट रहे थे, नहीं मिल रहा था पीएफ : मिल क्षेत्र निवासी रामप्रसाद यादव कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। करीब चार साल पहले रिटायर हो गए थे। उनका बकाया पीएफ जारी नहीं हो रहा था। वे विभाग में चक्कर लगाकर परेशान थे। एक वकील के माध्यम से वे लीगल क्लीनिक पहुंचे। यहां के सदस्यों ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पूछा कि कितना पीएफ जमा है और जारी क्यों नहीं किया जा रहा। आवेदन प्रस्तुत होने के डेढ़ महीने बाद ही पीएफ की पूरी रकम जारी कर दी गई।

कोर्ट जाए बगैर हो गया समझौता : द्वारकापुरी निवासी महिला छोटी बच्ची के साथ लीगल क्लीनिक पहुंची। उसने सदस्यों को बताया कि उसका पति दो साल से जीजा के पास उदयपुर रहने चला गया है। न वो तलाक दे रहा है न ही बच्ची के लिए भरण पोषण देता है। क्लीनिक के सदस्यों ने महिला के पति को कानूनी नोटिस जारी कर बताया कि उसके खिलाफ घरेलू हिंसा सहित अन्य प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। असर यह हुआ कि पति तुरंत इंदौर आया और पत्नी और बेटी को साथ उदयपुर ले गया।

मध्य प्रदेश के इंदौर में लीगल क्लीनिक के युवा सदस्य। नई दुनिया

कब्जा करने वाले भाग गए

दिल्ली में छोटा-मोटा काम करने वाली महिला के स्कीम 71 स्थित प्लाट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। महिला ने शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला लीगल क्लीनिक पहुंची और अपनी परेशानी बताई। क्लीनिक के सदस्यों ने उसे सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत करने की सलाह दी। इसके अलावा खुद थाने पर बात की। पुलिस हरकत में आई और अवैध कब्जा करने वाले प्लाट खाली कर भाग गए।

लीगल क्लीनिक का कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसे सराहा जाना चाहिए। गरीब और कमजोर वर्ग को इससे राहत मिल रही है।

– सुरेंद्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष इंदौर अभिभाषक संघ

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

अगले साल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मनेगा गीता जयंती महोत्सव : मनोहर लाल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्व को गीता का संदेश देने में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से पिछले चार सालों से लगातार इस महोत्सव को बड़े से बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतिम दिन रविवार शाम को बतौर मुख्य अतिथि सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के कर्म के सिद्धांत को नेताओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मनुष्य निर्माण में हर किसी व्यक्ति को गीता के सार का अनुसरण करना चाहिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मनुष्य को कर्म के सिद्धांत पर चलते हुए अपना कार्य करना चाहिए, फल की चिंता नही करनी चाहिए। नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने कहा कि हरियाणा की भूमि से पूरे विश्व का पवित्र ग्रंथ गीता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया गया है जो मनुष्य को जीने की राह दिखाता है और इस ग्रंथ में तमाम समस्याओं का समाधान निहित है।

18 हजार विद्यार्थियों ने किया गीता पाठ...

श्रीमद्भगवद गीता की 5157वी जयंती पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरा से 18 हजार स्कूली बच्चों ने कर्म करने का संदेश दिया। 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का छह मिनट तक एक साथ सस्वर पाठ किया। लगातार दूसरे वर्ष इतने बड़े स्तर पर यह आयोजन किया गया। पिछले वर्ष के वैश्विक गीता पाठ को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया। इस महाआयोजन के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रही। अश्वनी धनौरा

कुल्लू में बेघरों के लिए खुले आसमान के नीचे काटी रात

जागरण संवाददाता, कुल्लू : बेघरों की आवाज बुलंद करने के लिए रविवार को अपना घर छोड़कर लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात काटी। कुल्लू जिले के भुंतर मेला ग्राउंड में वर्ल्ड बिग स्लीप आउट डे पर करीब 70 लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। जानकारी के मुताबिक देश के करीब 26 शहरों में इसका आयोजन किया गया।

इस आयोजन का हिस्सा बने सहारा, मानव सेवा, और लोकतंत्र संगठनों के पदाधिकारियों महिमन चंद्र, राजेंद्र चौहान, पाविंद्र कुमार, शाम लाल हांडा, डिंपल, डीआर आनंद, राकेश शर्मा, माइकल, मेहता, दीपक कुमार, अरुण गर्ग ने बताया कि ज्यादातर बेघर लोग जो रात को सड़कों के किनारे फुटपाथ पर, बस स्टॉप पर पार्कों आदि में सोते हैं, ठंड में छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के अभाव में यह लोग मर जाते हैं। समाज भी ऐसे लोगों को देखता तो हर कोई है लेकिन असंवेदनशीलता के कारण इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। प्रत्येक शहर का प्रशासन भी ऐसे लोगों को अपने शहरों से खदेड़ने का काम ज्यादा करता है। इसी कारण ये लोग ज्यादातर एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं और हर जगह नई मुसीबतों का सामना करते हैं। वास्तविकता देखी जाए तो बेघरों में सबसे बड़ा तबका उन लोगो का है, जो विकास के नाम पर कहीं न कहीं से उजाड़े गए हैं।

देश की सबसे बड़ी निओनेटल नर्सरी बनाने की तैयारी

मिलेगी मदद

पीजीआइ रोहतक में नर्सरी में 82 बेडों की होगी व्यवस्था, नवजात बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज, वर्तमान में 22.1 फीसद बच्चों की पैदा होने के बाद उपचार के अभाव में होती है मौत

पुनीत शर्मा, रोहतक

पीजीआइ रोहतक में जल्द ही देश की सबसे बड़ी निओनेटल नर्सरी बनाई जाएगी। नर्सरी बनाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि बच्चे के पैदा होने के प्रथम माह में होने वाली मौत (निओनेटल डेथ) के आंकड़ों में कमी आएगी। देश की सबसे बड़ी निओनेटल नर्सरी बनाने के लिए अधिकारियों ने फिलहाल तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि नई नर्सरी में 82 बेडों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें नवजात बच्चों को होने वाले संक्रमण व अन्य गंभीर बीमारियों के दौरान पर्याप्त इलाज मिल सकेगा।

बच्चों की होने वाली मौत (चाइल्डहुड मॉरटेलिटी) रेट को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआइएमएस में देश की सबसे बड़ी निओनेटल नर्सरी बनाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन पीजीआइएमएस में करीब 40 बच्चे पैदा होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार, इनमें से करीब आधे बच्चों को नर्सरी की आवश्यकता होती है। बच्चे के पहली बार खुले वातावरण में आने पर उसके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। कई बार नवजात को पीलिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। 28 दिन तक के बच्चे के विशेष उपचार के लिए अब निओनेटल नर्सरी में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, नर्सरी के लिए स्टाफ की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि अन्य संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

एक माह से कम के 22.1 फीसद बच्चों की होती है मौत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में 22.1 फीसद नवजात की एक माह की उम्र से पहले मौत हो जाती है। सर्वे में बताया गया है कि इन नवजातों को अस्पतालों में पर्याप्त इलाज नहीं मिलता, संक्रमण फैलता है और बच्चों की मौत हो जाती है। उक्त आंकड़े को कम करने के लिए अब पीजीआइएमएस ने कदम बढ़ा दिए हैं।

स्टाफ नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी : पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ओपी कालरा ने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक, किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रति सप्ताह में 42 डिलीवरी होना आवश्यक है, जबकि वर्तमान में पीजीआइएमएस में करीब 40 डिलीवरी प्रति दिन होती हैं। निओनेटल नर्सरी बनाने के लिए तैयारियां तेज गति से चल रहीं हैं। स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनवरी माह में नर्सरी का शुभारंभ कर दिया जाएगा।

पीजीआइ रोहतक फाइल

माघ मेले में विकसित होगा संगम वॉक सर्किट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- संगम के साथ अक्षयवट, हनुमान व शंकर विमान मंडपम मंदिर जुड़ेगा
- श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मेले में पहली बार की जा रही तैयारी

माघ मेले में इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम वॉक सर्किट विकसित किया जाएगा। इसका रूट निर्धारित हो गया है। इससे श्रद्धालु रास्ता नहीं भटकेंगे और समय भी कम लगेगा। मेला 10 जनवरी से शुरू हो रहा है।

छह प्रमुख धार्मिक स्थल जोड़े जाएंगे सर्किट में : संगम तट पर 42 दिन चलने वाले माघ मेले के दौरान करीब पांच करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकसित किए जा रहे इस सर्किट में छह प्रमुख धार्मिक स्थल जोड़े जाएंगे। श्रद्धालु सर्किट से ही प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। इसके लिए साइनेज लगाए जाएंगे।

रामघाट से शुरू होगा : यह सर्किट रामघाट से शुरू होकर संगम नोज, अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कूप होते हुए बड़े हनुमान मंदिर और शंकर विमान मंडपम मंदिर पर समाप्त होगा। इसमें वाहन नहीं चल सकेंगे। सिर्फ पैदल ही आवागमन होगा। मार्ग पर दोनों ओर बेरिकेडिंग होगी। सुरक्षा के भी इंतजाम होंगे। सर्किट का आकर्षण बढ़ाने के लिए रंग-बिरंगे झंडे लगेंगे। संगम वॉक के लिए गाइड भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन विभाग इसका खाका तैयार कर रहा है। पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण करेगा और विद्युत विभाग एलईडी लगाएगा। साफ-सफाई का इंतजाम नगर निगम करेगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

इस बार माघ मेले में पांच करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। फाइल

- **06** प्रमुख धार्मिक स्थलों को इस विशेष सर्किट से जोड़ा जाएगा
- **05** किमी के करीब विकसित किया जा रहा यह विशेष सर्किट
- **10** जनवरी 2020 से संगम तट पर शुरू होगा 42 दिन का माघ मेला
- **06** प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम

संगम वॉक सर्किट श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खास होगा। इससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

– रजनीश कुमार मिश्र, मेलाधिकारी

अक्टूबर में भारतीय कंपनियों ने दोगुना ज्यादा कर्ज जुटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय कंपनियों ने अक्टूबर में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले दोगुना ज्यादा कर्ज जुटाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा दी जानकारी के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर में भारतीय कंपनियों ने विदेशी बाजारों से 341 करोड़ डॉलर (करीब 23,870 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में इन कंपनियों ने विदेशी बाजारों से 141 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई थी। आरबीआइ ने बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में जुटाई गई रकम में से 287 करोड़ डॉलर ऑटोमेटिक रूट से आए।

इंसान की तरह कंपनियों का भी जीवन चक्र होता है। इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया ने कंपनियों की एक तरह से आयु बढ़ा दी है।
— एमएस साहू
चेयरमैन, आइबीबीआइ

जीएसटी कमाई बढ़ाने पर मंथन शुरू

विमर्श ▶ सप्ताह के अंत तक मंत्रिसमूह द्वारा इस पर फैसला ले लिए जाने की उम्मीद

दरों में वृद्धि, दायरा बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीएसटी रेवेन्यू की लगातार धीमी रफ्तार से चिंतित राज्यों और केंद्र ने इसमें वृद्धि की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। इन संभावनाओं में जीएसटी की दरों में वृद्धि से लेकर इसका दायरा बढ़ाने तक के उपाय शामिल हैं। इन संभावनाओं पर विचार के लिए गठित मंत्रिसमूह द्वारा इस सप्ताह के अंत तक किसी नतीजे पर पहुंच जाने की संभावना है।

जुलाई, 2017 से लागू जीएसटी के लिए प्रति माह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू अर्जित करने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब तक केवल गिनती के महीनों में ऐसा हो पाया है। चालू वित्त वर्ष में केवल चार बार ऐसा हुआ है जब जीएसटी रेवेन्यू एक लाख करोड़ रुपये के पार हुआ हो। इसकी वजह से राज्यों के अनुमानित और वास्तविक रेवेन्यू का अंतर बढ़ रहा है।

सूत्रों के मुताबिक अब तक रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में जो सुझाव आ रहे हैं उनमें अधिकांश जीएसटी की दरों में वृद्धि करने से ही संबंधित हैं। इनमें जीएसटी दरों के चार

सरकार के सामने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। प्रतीकात्मक

स्लैब को पुनर्गठित करने और शुरुआती दर में वृद्धि जैसे सुझाव शामिल हैं। इनमें पांच परसेंट की दर को खत्म कर शुरुआती दर 10 परसेंट करने का सुझाव भी है। जबकि एक विचार इसमें एक परसेंट की वृद्धि कर इसे छह परसेंट करने का भी है। अलबत्ता जीएसटी का दायरा बढ़ाने का विकल्प भी इस मंथन में शामिल है। वृद्धि के लिहाज से दरों में अलग अलग प्रस्ताव चर्चा में हैं। जबकि अब तक जीएसटी से छूट हासिल वस्तुओं में से कुछ को इस दायरे में लाने की संभावना तलाशने पर भी चर्चा हो रही है। एक सुझाव 12 और 18 परसेंट के स्लैब को मिलाने का भी है।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति और मांग में कमी को देखते हुए जीएसटी की दरों में वृद्धि के किसी भी सुझाव पर अमल एक राजनीतिक निर्णय होगा। जानकारों का कहना है कि मांग में कमी के वक्त यदि दरों में वृद्धि होती है तो उत्पादों की कीमत बढ़ेगी जिसका मांग पर प्रतिकूल असर दिख सकता है। साथ ही जीएसटी काउंसिल के एक अधिकारी का मानना है कि खाद्य उत्पादों की महंगाई की दर में ऊपर का रुख बनने की वजह से जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं को टैक्स दायरे में लाने के नतीजे खराब हो सकते हैं। इस सूची में ज्यादातर उत्पाद खाद्य श्रेणी से ही आते हैं। अधिकारी का कहना है कि दरों में वृद्धि का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे रेवेन्यू में कितनी वृद्धि होती है और वह राज्यों को कितनी राहत दे सकता है।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में राज्यों का रेवेन्यू मूल रूप से अब जीएसटी पर ही निर्भर कर रहा है। साथ ही अनुमानित और वास्तविक रेवेन्यू के बीच का अंतर पाटने को केंद्र की तरफ से मिलने वाला मुआवजा भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से केंद्र की तरफ से राज्यों को यह मुआवजा मिलने में भी दिक्कत आ रही है।

इन परिस्थितियों में अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य लगातार केंद्र से जीएसटी रेवेन्यू में वृद्धि के उपाय तलाशने पर जोर दे रहे हैं। इसे देखते हुए ही सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के सात वित्त मंत्रियों को मिलाकर एक मंत्रिसमूह गठित किया है। इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने सभी राज्यों से रेवेन्यू की रफ्तार बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इन सभी सुझावों पर मंत्रिसमूह विचार करेगा और काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट पर 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित बैठक में विचार किए जाने की संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों, पांच यूटी में एक भी गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : लगभग 13 महीनों में देशभर में सोने गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होने वाली है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में सोने की शुद्धता की पहचान और हॉलमार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप में एक भी गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है।

इस बारे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सोने की शुद्धता की पहचान और हॉलमार्किंग सेंटर की स्थापना स्थानीय स्तर पर निजी कारोबारियों द्वारा की जाती है। जिन बाजारों में ऐसे केंद्रों की जरूरत महसूस हुई है, वहां निजी कंपनियों ने अपनी लाभ-हानि को देखते हुए वहां ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में देशभर के 234 जिलों में ऐसे सेंटर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 123 सेंटर महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली में इस वक्त 41 ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं।

करीब एक सप्ताह पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को एलान किया कि 15 जनवरी, 2021 से देशभर में सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। इसके लिए अधिसूचना अगले वर्ष 15 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी, और जौहरियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए एक वर्ष की मोहलत दी जाएगी। हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने से ग्राहकों को शुद्ध सोना मिलेगा। वर्तमान में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग ऐच्छिक है।

- **सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जनवरी, 2021 से होगी अनिवार्य**
- **पांच केंद्र शासित प्रदेशों में भी हॉलमार्किंग सेंटर नहीं**

सरकार के मुताबिक यह निजी कंपनियों का काम है। प्रतीकात्मक

क्या होती है हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए अधिकृत अथॉरिटी है। बीआईएस उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है। ब्यूरो ने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग के लिए तीन ग्रेड 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट में स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं। मंत्रालय के अनुसार ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सोने के गहनों की हॉलमार्किंग अनिवार्य है।

न्यूज गैलरी

विकास दर पांच फीसद से नीचे जाने के आसार

नई दिल्ली : रिसर्च फर्म आइएचएस मार्किट ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की विकास दर पांच फीसद से भी थोड़ा नीचे जा सकती है। सुधार की दिशा में हाल के दिनों में उठाए गए कदमों का असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। पिछले दिनों सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 4.5 फीसद पहुंच गई। यह छह साल का निचला स्तर है। इससे पिछली तिमाही में विकास दर पांच फीसद और सालभर पहले इसी तिमाही में सात फीसद रही थी। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती से यह गिरावट आई है। आइएचएस मार्किट का कहना है कि एनपीए सरकारी बैंकों के समक्ष बड़ी समस्या है। एनबीएफसी की मुश्किलें भी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। गौरतलब हैकि आरबीआइ ने भी पिछले दिनों मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया था। (प्रेट्र)

पीएम कौशल विकास योजना का तीसरा चरण अगले साल

नई दिल्ली : सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का तीसरा चरण शुरू करने की योजना बना रही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि तीसरे चरण की शुरुआत अगले वित्त वर्ष में की जाएगी। 2020 तक एक करोड़ लोगों के कौशल विकास के लक्ष्य के साथ 2015 और 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दो चरण शुरू किए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 11 नवंबर तक इस योजना के तहत 69 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। (प्रेट्र)

सीजी पावर जुटाएगी 5000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली : धोखाधड़ी के मामले में जांच का सामना कर रही सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने 5,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों से अनुमति मांगी है। इस फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की कमी पूरी करने व अन्य कारोबारी जरूरतों में किया जाएगा। फंड जुटाने की प्रक्रिया पर मतदान के लिए सीजी पावर ने 14 दिसंबर को शेयरधारकों की सालाना आम सभा बुलाई है। कंपनी ने बताया है कि 31 मार्च, 2019 तक उस पर शॉर्ट टर्म लोन समेत फंड आधारित कर्ज 2,455.39 करोड़ रुपये और नॉन-फंड आधारित कर्ज 1,380 करोड़ रुपये था। (प्रेट्र)

विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी बनेगी एयरटेल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारती एयरटेल की प्रमोटर कंपनी भारती टेलीकॉम ने सरकार से 4,900 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) हासिल करने की इजाजत मांगी है। कंपनी सिंगापुर स्थित सिंगटेल और कुछ अन्य विदेशी निवेशकों के माध्यम से यह रकम जुटाना चाहती है। अगर सरकार यह इजाजत देती है, तो कंपनी में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के पार चली जाएगी। इस बदले शेयरधारिता पैटर्न के हिसाब से देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल एक विदेश इकाई बन जाएगी। वर्तमान में प्रमोटर सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार की भारती टेलीकॉम में लगभग 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

घटनाक्रम से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि विदेशी निवेशकों द्वारा 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने के बाद कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत के ऊपर पहुंच जाएगी, जो इसे विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी में तब्दील कर देगा। भारती एयरटेल में भारती टेलीकॉम की करीब 41 प्रतिशत, विदेशी प्रमोटर इकाइयों की 21.46 प्रतिशत और आम शेयरधारकों की करीब 37 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रतीकात्मक

- **भारती टेलीकॉम ने सरकार से मांगी एफडीआइ से 4,900 करोड़ रुपये जुटाने की इजाजत**
- **टेलीकॉम विभाग द्वारा इसी महीने के अंत तक इसकी अनुमति दे दिए जाने की उम्मीद**

सूत्रों का कहना है कि भारती एयरटेल ने सिंगटेल और कुछ अन्य निवेशकों के माध्यम से यह रकम जुटाने की इजाजत मांगी है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) इसी महीने कंपनी को इसकी इजाजत दे सकता है। इससे पहले डीओटी ने भारती एयरटेल के एफडीआइ प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि कंपनी ने विदेशी निवेशकों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी।

एयरटेल में इस वक्त कुल विदेशी हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत है। सूत्र के मुताबिक अगर उसकी प्रमोटर भारती टेलीकॉम विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी बनती है, तो एयरटेल में विदेशी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत के पार चली जाएगी। एयरटेल इस बारे में पहले से ही सिंगटेल और अन्य निवेशकों से बातचीत कर रही है।

अगस्त में भारती एयरटेल ने शेयर बाजारों को बताया था कि भारती टेलीकॉम अपना कुछ कर्ज चुकाने के लिए वर्तमान प्रमोटर्स से कुछ रकम जुटाना चाहती है। कंपनी के प्रमोटर्स में सिंगापुर के सिंगटेल समेत कुछ अन्य विदेशी कंपनियां शामिल हैं। कंपनी का कहना था कि वह अपने शेयरधारकों से समानुपातिक आधार पर (जिस प्रमोटर की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी होगी उसी अनुपात में) पूंजी जुटाने का इरादा रखती है।

एयरटेल का कहना है कि विदेशी हिस्सेदारी में रत्तीभर की भी बढ़ोतरी उसे विदेशी इकाई में बदल देगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कंपनी के निदेशक बोर्ड ने विदेशी बाजारों से 300 करोड़ डॉलर (करीब 21,000 करोड़ रुपये) जुटाने की इजाजत दे दी है।

दो शीर्ष अधिकारियों के बगैर बजट की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगला आम बजट पेश होने में दो महीने से कम वक्त रह गया है और वित्त मंत्रालय में इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है। लेकिन इस प्रक्रिया में दो शीर्ष अधिकारियों की कमी है। इनमें पूर्णकालिक व्यय सचिव और संयुक्त सचिव (बजट) के पद शामिल हैं।

जीसी मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उप राज्यपाल बना दिए जाने के बाद व्यय सचिव का पद खाली हो गया था। अभी अतनु चक्रवर्ती इस्का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती इस वर्ष जुलाई में आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए थे। उससे पहले वे एक वर्ष से ज्यादा समय तक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव रहे। इसी तरह, संयुक्त सचिव (बजट) का पद भी पिछले तीन महीनों से खाली है। वित्त मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया इस वर्ष 14 अक्टूबर को शुरू कर दी थी। इसके तहत पिछले महीने कई बैठकों का दौर चला है। व्यय सचिव जब अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से मशविरा कर लेंगे, उसके बाद अगले वित्त वर्ष के बजट को प्रारंभिक तौर पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

22 करोड़ खर्च कर रेलवे का ऑर्डर पूरा करेगी सेल

- **एक रोलिंग टेबल के अभाव में रोकना पड़ता था उत्पादन**
- **सेल चेयरमेन ने रोलिंग टेबल बनाने का दिया आदेश, छह माह लगेंगे बनाने में**

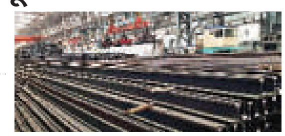

प्रतीकात्मक

भिलाई, नईदुनिया

देश की सबसे लंबी सिंगल 130 मीटर की रेल पटरी बनाने वाले भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के अच्छे दिन आने वाले हैं। रेलवे का आर्डर पूरा करने हेतु यूनिवर्सल रेल मिल की खामियों को सुधारने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने बीएसपी को जिम्मेदारी सौंपी है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में करीब 12,000 करोड़ की लागत से तैयार किए गए यूनिवर्सल रेल मिल में एक नया रोलिंग टेबल बनाया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान रेल पटरी रिजेक्शन की वजह से मशीन पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। रिजेक्ट रेल पटरी को काटकर हटाने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से उत्पादन प्रक्रिया घंटों बाधित होती है। इस वजह से रेल का आर्डर पूरा करने में बीएसपी प्रबंधन को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। भिलाई दौरे पर पहुंचे सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी को यहां के कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि नई रोलिंग टेबल से सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। इसको तैयार करने में छह माह का वक्त लगेगा। इस कार्य के लिए 22 करोड़ रुपये की लागत आएगी, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के जरिये इसकी रिकवरी छह माह के भीतर ही कर ली जाएगी। सेल चेयरमैन ने तत्काल इसे अमल में लाने का आदेश दे दिया। अब सेल व बीएसपी के उच्च अधिकारियों की कमेटी ड्राइंग डिजाइन तैयार कर छह माह के भीतर नई रोलिंग टेबल बनाने की दिशा में काम करेंगे।

अफसरों का कहना है कि रेल पटरी उत्पादन के दौरान तकनीकी खामी की वजह से इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल रेल मिल का उत्पादन रोकना पड़ता है। खराब रेल पटरी को काटकर हटाने तक पूरी प्रक्रिया रुकी रहती है। इसके विकल्प के रूप में समीप ही नया रोल टेबल बनाया जाएगा जिस पर खराब रेल पटरी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादन प्रक्रिया तत्काल बहाल हो जाएगी।

मेट्रिमोनियल साइट्स खंगाल रहा सेबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रंट रनिंग मामलों में संदिग्धों की तलाश के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अब मेट्रिमोनियल साइट्स की पड़ताल शुरू की है। इसका मकसद ऐसे मामलों में शामिल संदिग्धों के संबंधियों की तलाश करना और उनमें आपसी संबंध स्थापित करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों में भी सेबी संदिग्धों के फेसबुक पेज खंगाल रहा है, ताकि आपसी रिश्तों की पड़ताल की जा सके।

फिडेलिटी ग्रुप से जुड़े कई फंड्स के फ्रंट रनिंग मामलों में सेबी ने कारोबारी वैभव ढड्ढा के मेट्रिमोनियल प्रोफाइल की पड़ताल की है। सेबी ने वैभव ढड्डा की उसके परिवार से संबंध स्थापित करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जैनशुभबंधन डॉट कॉम पर प्रोफाइल खंगाली। सेबी ने पांच दिसंबर के अंतरिम आदेश में कहा कि इस वेबसाइट पर वैभव को अलका ढड्डा का पुत्र बताया गया है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट पर भी माता के रूप में अलका ढड्डा का ही नाम दर्ज है। इस तरह सूचना इकट्ठा करने और अलग-अलग प्रोफाइल पर जांच करने के बाद सेबी ने वैभव, अलका और वैभव की बहन आरुषि को पूंजी बाजार की गतिविधियों से रोक दिया है।

पीएमओ में शक्ति का केंद्रीकरण ठीक नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था इस वक्त विकास दर की ढलान के बीच है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इकोनॉमी को उस प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें सारी शक्तियां केंद्रित हो गई हैं और मंत्रियों को ताकत-विहीन कर दिया गया है। इससे इकोनॉमी को अभी और चोट पहुंचने के संकेत दिख रहे हैं।

इकोनॉमी को सुस्ती से उबारने के उपायों पर लिखे एक आलेख में राजन ने सुधारों को और गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय तंत्र, भूमि और श्रम बाजारों को और ज्यादा मुक्त करने की जरूरत है। इसके साथ ही निवेश और विकास पर सरकार को और ध्यान देना होगा। पूर्व गवर्नर ने यह भी सुझाया कि घरेलू उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए स्पर्धा को गति देनी होगी। यह तभी संभव होगा जब भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में शामिल हो। आर्थिक सुस्ती की समस्या का निदान तब शुरू होगा, जब सरकार पहले यह मान ले कि सुस्ती है।

राजन ने कहा, 'यह जानने के लिए कि क्या गलती हुई है, हमें सबसे पहले शक्तियों के केंद्रीकरण को लेकर वर्तमान सरकार की सोच से शुरुआत करनी पड़ेगी। केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि विचार और योजनाएं भी प्रधानमंत्री और पीएमओ कार्यालय में बैठे कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की ओर से आ रही हैं।' राजन के मुताबिक शक्तियों का ऐसा केंद्रीकरण उन मामलों में ठीक है जहां पार्टियों के राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब बात इकोनॉमी को राष्ट्रीय स्तर पर गति देने की बात हो, तो वहां इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की राय बहुत अहम होती है।

रघुराम राजन फाइल

- **आरबीआइ के पूर्व गवर्नर के मुताबिक नीतियों के निर्धारण और फैसलों में पीएमओ की भूमिका सबसे ऊपर हो गई है**
- **आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी आगे बढ़ने का दिया सुझाव**

पूर्व आरबीआइ गवर्नर ने एक अन्य उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी सरकार 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' यानी सरकार की कम से कम, शासन की ज्यादा से ज्यादा दखलअंदाजी के नारे के साथ सत्ता में आई थी। इस स्लोगन को अक्सर गलत समझा गया है।

इसका मतलब यह था कि सरकार पूरी दक्षता से काम करेगी, यह नहीं कि लोगों और निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। हुआ यह है कि कई मोर्चों पर सरकार की दखलअंदाजी घटी नहीं, बल्कि बढ़ गई है।

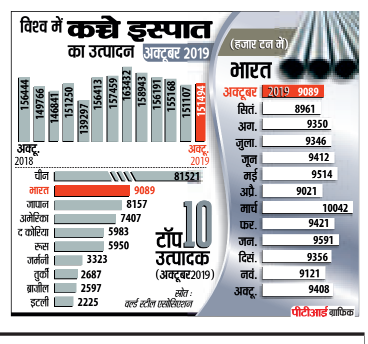

समीक्षा

चुनिंदा बड़े आंकड़ों से तय होगी निवेशकों की चाल

महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर, अमेरिका-चीन के कारोबारी सौदों पर भी निर्भर करेगा बहुत कुछ

नई दिल्ली, एजेंसियां : इस सप्ताह महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों का निवेशकों को इंतजार रहने वाला है। इसके साथ ही विदेशी बाजारों के घटनाक्रमों पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं। इसी आधार पर बैंक ने पिछले सप्ताह अपनी नीतिगत दरों में कटौती नहीं की, जबकि बाजार और आर्थिक विशेषज्ञ भी कम से कम 25 आधार अंकों की कटौती तय मानकर चल रहे थे।

शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि इस सप्ताह के शुरुआती सत्रों में निवेशकों के सामने विदेशी बाजारों से मिल रहे संकेतों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार पर चल रही तनातनी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर पिछले कुछ समय के दौरान अमेरिका के रुख को देखते हुए इस बारे में ठोस कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जानकार मानते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स 40,000-41,000 और निफ्टी 11,800-12,200 के दायरे में कारोबार करते दिखेंगे। सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के सीईओ जिमीत मोदी के विचार से शेयर बाजार इस पूरे सप्ताह अस्थिर रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि विदेशी बाजारों के कई हलचल और घरेलू बाजार में स्टॉक-केंद्रित घटनाक्रम से निवेशक प्रभावित रहेंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों पर इस सप्ताह दुनियाभर के शेयर बाजारों की नजर रहेगी।

पिछले सप्ताह से बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 348.66 अंक यानी 0.85 प्रतिशत टूट गया। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी पिछले सप्ताह 134.55 अंकों यानी 1.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आरबीआइ से निराशा हाथ लगने के बाद सप्ताह के आखिरी दो कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट कुछ ज्यादा रही। वहीं, पिछले सप्ताह बीएसई-100 में 1.39, बीएसई-200 में 1.44 और बीएसई-500 में 1.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई-मिडकैप 2.77 प्रतिशत और बीएसई-स्मॉलकैप 1.63 प्रतिशत टूट गए।

जानकार मानते हैं कि कमोडिटी मार्केट में तेजी की हवा दिख रही है। इनमें भी मेटल स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। एडलवाइज प्रोफेशनल इन्वेस्टर रिसर्च के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट साहिल कपूर का मानना है कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े सुधर रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपये का प्रदर्शन भी लगभग ठीक है। अगर अमेरिका और चीन में पहले चरण की सौदेबाजी हो जाती है तो स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी उम्मीद कम है।

इस सप्ताह बाजार के सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना है। प्रतीकात्मक

एफपीआइ निकाल रहे निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने दिसंबर में घरेलू बाजारों से कुल 244 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। डिपोजिटरी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजार से दिसंबर में अब तक 1,668.8 करोड़ रुपये निकाले। हालांकि इसी अवधि में उन्होंने डेट मार्केट में 1,424.6 करोड़ रुपये का निवेश भी किया है। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में एफपीआइ भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदार के तौर पर उभरे थे। नवंबर में इन निवेशकों ने 22,871.8 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।

शीर्ष 10 में पांच कंपनियों ने जोड़े 56,877 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसई सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 56,877.12 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सबसे आगे रही। इसका बाजार पूंजीकरण 26,360.5 करोड़ रुपये बढ़कर 7,96,612.51 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल), आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह बढ़ोतरी हुई। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी, आइटीसी और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। आरआइएल का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 2,567.36 करोड़ रुपये बढ़कर 9,85,707.52 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। कोटक महिंद्रा बैंक के पूंजीकरण में 11,443.51 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। यह बैंक सोमवार को 3,19,864.26 करोड़ रुपये पूंजीकरण के साथ बीएसई में कारोबार की शुरुआत करेगा। आइसीआइसीआइ बैंक का पूंजीकरण भी पिछले सप्ताह 8,329.51 करोड़ रुपये बढ़कर 3,39,341.06 करोड़ रुपये हो गया।

इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 8,176.24 करोड़ रुपये मजबूत होकर 3,04,543.53 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एसबीआइ के बाजार पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 19,678.8 करोड़ रुपये की गिरावट आई। इसके चलते बैंक का बाजार पूंजीकरण तीन लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया।

1985 को ढाका में हुई थी दक्षेस की स्थापना। पहले शिखर सम्मेलन में मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ने दक्षेस की स्थापना को लेकर एक घोषणा-पत्र पर दस्तखत किए थे।

न्यूज गैलरी

चीन की मदद से कोलंबो पोर्ट पर काम तेज करेगा श्रीलंका

कोलंबो : श्रीलंका की सरकार ने चीन की मदद से बनने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना कोलंबो पोर्ट सिटी की शनिवार को शुरुआत कर दी। चीन के राजदूत व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 269 हेक्टेयर में बनने वाली इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरी करने की बात कही। (एएनआइ)

शारजाह में इमारत से गिरने से भारतीय किशोरी की मौत

शारजाह : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह शहर में बीते शुक्रवार को एक इमारत की दसवीं मंजिल से गिरने से 15 वर्षीय भारतीय किशोरी की मौत हो गई। वह शारजाह के एक भारतीय स्कूल में पढ़ती थी। मामले की आत्महत्या के नजरिए से भी जांच हो रही है। (आइएएनएस)

म्यांमार की नेता आंग सान सूकी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के लिए रवाना

यंगून : रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के मामले में अपने देश का पक्ष रखने के लिए म्यांमार की नेता आंग सान सूकी नीदरलैंड्स के हेग शहर रवाना हो गई हैं। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में म्यांमार के खिलाफ यह मामला अफ्रीकी देश गांबिया ने दायर किया है। इसकी सुनवाई मंगलवार को शुरू होगी। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सूकी को विदा करने राजधानी नेपिता के हवाई अड्डे पहुंचे। (रायटर)

मलेशिया में 27 साल बाद सामने आया पोलियो का मामला

कुआलालंपुर : मलेशिया में तीन माह के बच्चे को पोलियो से संक्रमित पाया गया है। मलेशिया में पोलियो का अंतिम मामला 1992 में सामने आया था। इसके बाद चले सघन टीकाकरण अभियान की बदौलत मलेशिया को वर्ष 2000 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नए मामले की जांच में पाया गया कि संक्रमण वाले इलाके में 23 बच्चों को पोलियो टीका नहीं दिया गया था। (रायटर)

श्रीलंका में बाढ़ से दस हजार से अधिक लोग विस्थापित

कोलंबो : श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के तमिल बहुल इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 10 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। कोलंबो पेज की खबर के मुताबिक श्रीलंका में कुछ हफ्तों से मूसलाधार बारिश हो रही है, स्थिति उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में गंभीर है। आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूर्वी प्रांत में 79,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 798 परिवारों के 2,507 लोग विस्थापित हुए हैं। (प्रेट्र)

चार करोड़ यूजर करते हैं लीक पासवर्ड का प्रयोग : माइक्रोसाफ्ट

सैन फ्रांसिस्को : माइक्रोसाफ्ट के मुताबिक उसके एज्योर और माइक्रोसाफ्ट सर्विस अकाउंट (एमएसए) के 4.4 करोड़ से अधिक यूजर अपने खातों में लॉग इन करने के लिए लीक पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसाफ्ट की रिसर्च टीम ने 2019 में तीन अरब डॉलर से अधिक पासवर्ड की जांच की और इनमें से 4.4 करोड़ से अधिक एज्योर और एमएसए यूजर लीक पासवर्ड का प्रयोग करते मिले। (आइएएनएस)

पाकिस्तान में अपहृत छात्रा लौटी घर, चल रही है जांच

कराची : कराची के रक्षा क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले सप्ताह एक छात्रा का अज्ञात आरोपितों ने अपहरण कर लिया गया था। वह छात्रा शनिवार को घर लौट आई है। दक्षिण क्षेत्र के डीआइजी शारजील खरल के कार्यालय ने छात्रा के वापस लौटने की पुष्टि की है। छात्रा का अपहरण किसने और क्यों किया था, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 30 नवंबर को 20 वर्षीय छात्रा को हथियारबंद लोगों ने रक्षा आवास प्राधिकरण (डीएचए) के एक रेस्तरां के पास से अगवा कर लिया था। डॉन अखबार के मुताबिक, अपहरणकर्ताओं ने उसके दोस्त हारिस फतह को भी गोली मारकर घायल कर दिया था। उसकी गर्दन के पास गोली लगी थी। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले बीते गुरुवार को डीआइजी खरल ने कहा था कि यह फिरौती के लिए अपहरण का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि, परिजनों ने फिरौती की खबरों का खंडन किया था। (एएनआइ)

चीन ने बताया आतंकी वारदातों से लिप्त रहे हैं उइगर मुसलमान

डॉक्यूमेंट्री दिखाकर कहा, वह दूर कर रहा है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने पहली बार शिनजियांग में आतंकी वारदातों के कई वीडियो फुटेज शामिल कर तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री (वृत्तचित्र) सार्वजनिक की है। इस डॉक्यूमेंट्री में अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक (ईटीआइएम) मूवमेंट के सदस्यों के जानलेवा हमलों को दिखाया गया है। चीन ने ऐसा कर लाखों उइगर मुसलमानों की सामूहिक नजरबंदी को सही ठहराने की कोशिश की है। इस नजरबंदी के लिए चीन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा झेलनी पड़ रही है।

उइगर मुसलमानों को नजरबंदी के सवाल पर चीन को हाल के महीनों में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की आलोचना झेलनी पड़ी है। चीन ने सफाई दी है कि वह शिविरों में उइगर मुसलमानों को किसी तरह प्रताड़ित नहीं कर रहा बल्कि उन्हें धार्मिक उन्माद से बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। चीन के सीमावर्ती शिनजियांग प्रांत में एक करोड़ से ज्यादा तुर्क मूल के उइगर मुसलमान रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय निंदा से बचाव के लिए चीन ने जुलाई में श्वेत पत्र जारी कर बताया था कि उइगर मुस्लिमों को शिविर में अतिवाद से दूर करने वाली शिक्षा दी जाती है और उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है।

द ब्लैक हैंड-ईटीआइएम एंड टेरेरिज्म इन शिनजियांग डॉक्यूमेंट्री सरकार द्वारा संचालित सीजीटीएन चैनल पर प्रसारित की गई। इसमें शिनजियांग प्रांत में हुए आतंकी हमलों को दिखाया गया। बताया गया कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का संबंध अल कायदा और इस्लामिक स्टेट (आइएस) जैसे आतंकी संगठनों से है।

डॉक्यूमेंट्री में बीजिंग के थ्यानमेन चौक पर 2013 में हुए कार बम विस्फोट जैसे हमलों को दिखाया गया है जिनमें कई लोग मारे गए थे। बीजिंग की घटना में आतंकियों ने पर्यटकों के समूह के नजदीक जाकर अपनी एसयूवी कार को उड़ा दिया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी प्रकार का एक हमला 2014 में युन्नान प्रांत में हुआ, जहां कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर हमला कर कई निर्दोष लोगों को मार डाला गया था।

उत्तर कोरिया ने किया अहम परीक्षण का दावा अमेरिका जुटा रहा सूचना

सियोल, एएफपी : उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि शनिवार को उसने अपने प्रक्षेपण केंद्र से एक बहुत महत्वपूर्ण लांचिंग को अंजाम दिया है। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी लेकिन इसे देश की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया। यह परीक्षण ऐसे वक्त पर किया गया जब शनिवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों को मधुर बताया।

उत्तर कोरिया के इस दावे को लेकर अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जानकारी जुटा रहा है। जानकारों के मुताबिक, यह परीक्षण उत्तर कोरिया ने अपने सोहे प्रक्षेपण केंद्र से किया। इसे आर्थिक पाबंदियों से परेशान उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका के साथ रुकी वार्ता को फिर बहाल करने के लिए दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। इस लांच को भी उत्तर कोरिया द्वारा चोरी-छिपे किया जाने वाला मिसाइल परीक्षण कहा जा रहा है। अमेरिका ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ में बिडेन सबसे आगे

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

वाशिंगटन, एएफपी : ज्यादा उम्र और अति उदारवादी होने की आलोचनाओं के बीच जो बिडेन अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे मजबूत प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। पिछले एक सप्ताह के चुनाव अभियान के दौरान 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति ने आक्रामक तेवर भी दिखाए हैं। अमेरिका में अगले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए प्राइमरी चुनाव के तहत सबसे पहले आयोवा और न्यूहैंपशायर में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही जगहों पर हालांकि बिडेन चौथे स्थान पर चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में उन्हें 28 फीसद लोगों का समर्थन हासिल है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स (16 फीसद) और एलिजाबेथ वारेन (14 फीसद) से आगे चल रहे हैं। बिडेन को इस सप्ताह राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके जॉन केरी का भी समर्थन मिल गया है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स के निदेशक लैरी सबाटो का कहना है कि डेमोक्रेट किसी भी कीमत पर ट्रंप को हराना चाहते हैं और बिडेन के पास ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका है।

चुनाव अभियान के दौरा पिज्जा के बॉक्स लेकर जाते विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रबल दावेदार जो बिडेन(दाएं)। साथ में हैं जॉन कैरी। रायटर

ट्रंप ने खुद को इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया

हॉलीवुड, एएफपी : बतौर राष्ट्रपति अपनी दूसरी पारी के लिए चुनाव मैदान में उतरे ट्रंप इजरायली मूल के मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इजरायली मूल के अमेरिकियों के गढ़ फ्लोरिडा में ट्रंप ने खुद को इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया। हॉलीवुड में शनिवार को इजरायली-अमेरिकी काउंसिल द्वारा आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने कहा, पूर्व में आप में से ज्यादातर का समर्थन दूसरे दल (डेमोक्रेट) को मिला, लेकिन आप खुद देखिए कि इजरायल को मुझसे बेहतर दोस्त नहीं मिला है। ट्रंप ने अपने भा षण में यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले का भी जिक्र किया।

हांगकांग आंदोलन ▶ लोकतंत्र और आजादी मांग रहे आठ लाख लोग सड़कों पर आए

लाल चीन के खिलाफ बिछी काली चादर

बैंक ऑफ चाइना की इमारत को नुकसान पहुंचाया

हांगकांग, एजेंसियां : हांगकांग के मध्य मुख्य कारोबारी इलाके की धरती पर रविवार को काले रंग की चादर बिछ गई। जिस सड़क पर देखो-उसी से काले कपड़ों में लोकतंत्र समर्थकों का रेला वहां पहुंच रहा था। बच्चे-बूढ़े और जवान, सभी के मुख से- आजादी के लिए हांगकांग के साथ खड़े हों, का नारा निकल रहा था। आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर आयोजित जनसभा में आठ लाख लोगों ने हिस्सा लिया। यह हाल के महीनों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। जनसभा में शामिल लोगों के एक समूह ने बैंक ऑफ चाइना की इमारत को नुकसान पहुंचाया। पथराव से इमारत के शीशे तोड़ने के साथ ही स्प्रे पेंट से उस पर चीन विरोधी नारे लिख दिए। पुलिस भी वक्त की नजाकत को समझ रही थी। संयम बरतने का एलान उसने पहले ही कर रखा था। इस दौरान हथियार लेकर आ रहे 11 लोग गिरफ्तार हुए।

हाल के निकाय चुनाव में लोकतंत्र समर्थकों को मिली बड़ी सफलता ने जाहिर कर दिया है कि हांगकांग क्या चाहता है। इसी के कारण पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में अड्डा जमाए हजारों आंदोलनकारियों को खदेड़ने के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने अपना रुख बदल लिया है। आंदोलन को मिल रहे अंतरराष्ट्रीय समर्थन को देखते हुए स्थानीय सरकार पर दबाव बन गया है कि वह आंदोलन से शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। जनसभा के दौरान हांगकांग की चीन समर्थित सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। जुलूस में शामिल होकर सभास्थल पहुंचे 50 वर्षीय वांग का कहना था कि हम अलग-अलग तरीके से अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ विदेशों में हमारी आवाज उठा रहे हैं और कुछ चुनाव के जरिये लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही। वह सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का आदेश मान रही है। हम अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ना जारी रखेंगे। विक्टोरिया पार्क से जुलूस में अपने बच्चे के साथ काले कपड़ों में आई 40 वर्षीय महिला ने कहा जब तक उसमें जान है-तब तक वह हांगकांग की आजादी की लड़ाई लड़ेगी। आज हांगकांग के साथ हर कोई खड़ा है- अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी।

छह महीने पुराना यह आंदोलन आज भी नेतृत्व विहीन है। आंदोलन के लिए लोग ऑनलाइन अपील पर संगठित होते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। इसके चलते सरकार के लिए मुश्किल है कि वह आंदोलन से निपटने के लिए किसे घेरे और किसे पकड़े। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई इस आंदोलन से जुड़ा है। हिंसा के चलते हजारों लोग मुश्किलें झेलते हैं लेकिन आंदोलन का आधार घटने की जगह बढ़ रहा है। यही हांगकांग को अपना हिस्सा मानने वाले चीन की मुश्किल है।

हांगकांग में रविवार को पांच सूत्री मांगों को लेकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। एपी

अमेरिकी सांसद ने कश्मीर पर संसद में प्रस्ताव पेश किया

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी संसद में जम्मू-कश्मीर पर एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें भारत से वहां लगाए गए संचार माध्यमों पर लगाए प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने और सभी निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षित रखे जाने की अपील की गई है। जयपाल के इस कदम का अमेरिकी में रहने वाले भारतीय समुदाय ने कड़ा विरोध किया है। जबकि, भारत भी बार-बार यह स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर मसला उसका आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप वह बर्दाश्त नहीं करेगा। चेन्नई में पैदा हुई प्रमिला जयपाल पिछले कई सप्ताह से संसद में यह प्रस्ताव पेश करने के प्रयास में थीं, लेकिन उन्हें कोई सहयोगी प्रस्तावक नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से वह रिपब्लिकन पार्टी के स्टीव वाटकिंस का समर्थन पाने में सफल रहीं। यह एक सामान्य प्रस्ताव है, जिस पर संसद के उच्च सदन सीनेट में वोट नहीं किया जा सकता है और यह कानून नहीं बनेगा।

प्रस्ताव में भारत से पूरे जम्मू-कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की गई है। भारत सरकार के पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही वहां कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पूर्व अमेरिका भर से भारतीय मूल के लोगों ने विभिन्न मंचों से इसका विरोध किया था। समझा जाता है कि जयपाल के कार्यालय को इस प्रस्ताव को पेश नहीं करने के लिए भारतीय अमेरिकियों के 25 हजार से अधिक ईमेल प्राप्त हुए। भारतीय अमेरिकियों ने कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने के उनके कदम के खिलाफ उनके कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया। जयपाल ने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि उनके पास फोटोग्राफ के रूप में इसके सुबूत हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों से बांड भरवाया जा रहा है कि रिहा होने के बाद वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम या प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्ष वर्धन शृंगला और अन्य अधिकारियों ने भी जयपाल से मिलकर कश्मीर के हालात और भारत के पक्ष को समझाया था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा।

> **'राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया मुद्दा'**
>
> भारतीय मूल के अमेरिकी अटॉर्नी रवि बत्रा ने जयपाल पर पक्षपाती, सिद्धांतहीन, हिंदू विरोधी, आतंक समर्थक और निर्लज तरीके से निजी राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके इस कदम को राजनीतिक हथकंडा बताया है। जयपाल सिएटल से सांसद चुनी गई हैं और बताया जाता है कि उनके संसदीय क्षेत्र में पाकिस्तानी मूल और वामपंथी विचारधारा वाले मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और उन्हें खुश करने के लिए ही उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है।

अमेरिका में सऊदी के सेकेंड लेफ्टिनेंट ने की थी गोलीबारी

21 साल के मुहम्मद अल शमरानी के रूप में हुई हमलावर की पहचान

फ्लोरिडा के नौसेना अड्डे पर गोलीबारी में गई थी तीन की जान

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआइ) ने बीते शुक्रवार को फ्लोरिडा के पेंसाकोला स्थित नौसेना अड्डे पर गोलीबारी कर तीन लोगों की जान लेने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। इस वारदात को अंजाम देने वाला 21 वर्षीय मुहम्मद अल शमरानी सऊदी अरब की वायुसेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट था।

एफबीआइ के अनुसार, 'घटनास्थल पर ही मार गिराया गया शमरानी पेंसाकोला स्थित नौसेना की एविएशन स्कूल कमान में प्रशिक्षण ले रहा था।' सऊदी अरब के सैनिक 1970 से ही पेंसाकोला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस गार्वर ने बताया कि पेंटागन द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत फिलहाल 852 सऊदी सैनिक अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह 153 देशों के प्रशिक्षणरत 5181 सैनिकों का 16 फीसद है।

विदेशी सैनिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की होगी समीक्षा : ट्रंप : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा, अमेरिका कई दशकों से दूसरे देशों के सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। हम इसे तुरंत शुरू करेंगे।

> **घटना की वजह का जल्द पता लगाएंगे**
>
> ट्रंप ने कहा, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना के पीछे एक व्यक्ति है या और भी लोग शामिल हैं। यह बहुत चौंकाने वाली घटना है और बहुत जल्द हम इस घटना की वजह का पता लगाएंगे। ट्रंप ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस से बात की। दोनों ही नेता इससे बहुत दुखी हैं और प्रभावित परिवारों की मदद करना चाहते हैं।

सीधे पीएम पद के लिए हो चुनाव : नेतन्याहू

यरुशलम, आइएएनएस : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे पीएम पद के लिए चुनाव कराने की मांग की है। नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बेनी गेंट्ज की मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी गठबंधन बनाने में अब तक असमर्थ रही हैं। बुधवार रात तक अगर कोई गवर्निंग काउंसिल नहीं बनी तो संसद को भंग करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा।

नेतन्याहू ने रविवार को यहां कहा कि इजरायल को उनके और गेंट्ज के बीच प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने के बारे में सोचना चाहिए। इससे संसद के लिए जहां नए चुनाव कराने की परेशानी से बचा जा सकेगा वहीं इस पर खर्च होने वाली बड़ी रकम की बचत होगी। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल के लोगों को तय करने दें कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। असाधारण परिस्थितियों के लिए असाधारण समाधान की आवश्यकता होती है। इजरायल में इस साल अप्रैल और सितंबर में हुए चुनावों में कोई भी पार्टी सरकार बनाने लायक वोट नहीं जुटा सकी। अगर बुधवार आधी रात तक गतिरोध खत्म नहीं होता है तो एक साल से कम समय में इजरायल में तीसरी बार चुनाव होंगे।

गुलाम कश्मीर में दफनाया गया ब्रिटेन में मारा गया आतंकी

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के महाप्रबंधक ने की शव लाए जाने की पुष्टि

इस्लामाबाद, प्रेट्र : ब्रिटेन में मारे गए आतंकी उस्मान खान को गुलाम कश्मीर स्थित उसके पैतृक गांव में दफनाया गया है। हालांकि, पाकिस्तान ने इसकी जानकारी से इन्कार किया है।

लंदन ब्रिज पर हमला करने वाला उस्मान (28) ब्रिटिश नागरिक था। उसके शव को विमान से लंदन से इस्लामाबाद लाया गया और शुक्रवार को उसके परिजन को सौंप दिया गया। उस्मान के एक रिश्तेदार ने कहा, 'परिवार उसे ब्रिटेन में दफनाना नहीं चाहता था।' डॉन अखबार के मुताबिक, उस्मान का परिवार उसके शव को इस्लामाबाद हवाईअड्डे से गुलाम कश्मीर के कोटली जिले स्थित किजलानी गांव ले गया। शुक्रवार दोपहर स्थानीय कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) के महाप्रबंधक (जनसंपर्क) अब्दुल हफीज ने बताया कि उस्मान का शव पीआइए की उड़ान संख्या पीके-792 के जरिये लाया गया था। इस बीच, पाकिस्तान विदेश विभाग ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि खान का शव यहां लाया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी उस्मान खान के पैतृक निवास को लेकर बीते दिनों लोग आक्रोशित हो गए थे।

> **गुलाम कश्मीर में आतंकी शिविर चलाता था उस्मान**
>
> 29 नवंबर को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने से पहले उस्मान ने लंदन ब्रिज पर आतंकी हमला किया था। उसने दो लोगों की चाकू से गोदकर हत्या और अन्य तीन को घायल कर दिया था। बाद में उसकी पहचान लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके की साजिश रचने और गुलाम कश्मीर स्थित अपनी जमीन पर आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने के मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति के रूप में हुई। उसे सात साल पहले कैद की सजा हुई थी। वह पैरोल पर बाहर आया था।

सिख दंपती को श्वेत बच्चे का संरक्षण देने का आदेश

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन में जिस सिख दंपती को श्वेत बच्चा गोद लेने से रोका गया था, कोर्ट ने उसका साथ देते हुए बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नस्ली भेदभाव के खिलाफ आदेश देते हुए पति-पत्नी को 27-27 लाख रुपये नुकसान की भरपाई के रूप में देने के लिए भी कहा है।

मिली जानकारी के अनुसार बर्कशायर के मैडेनहेड में रहने वाले संदीप और रीना मांडर ने एक श्वेत बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन किया। लेकिन रॉयल बोरो ऑफ विंडसर एंड मैडेनहेड काउंसिल ने उनके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे भारतीय मूल के हैं। दंपती को बताया गया कि प्री स्कूल में पढ़ने वाला मात्र एक श्वेत बच्चा ही गोद के लिए उपलब्ध है। चूंकि वे भारतीय मूल के हैं, इसलिए उन्हें उस बच्चे के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। दंपती ने 2016 के काउंसिल के इस आदेश को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दंपती को इस प्रयास में अपने इलाके के सांसद और तत्कालीन गृह मंत्री टेरीजा मे का भी समर्थन मिला था।

चुनावी अभियान

मंदिर में बोले जॉनसन, मोदी के साथ बनाएंगे नया भारत

कहा, ब्रिटेन में भारत विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं, महिला मित्र के साथ लंदन के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के आम चुनाव में प्रवासी भारतीय कितना अहम हो गए हैं, इसका उदाहरण शनिवार को देखने को मिला। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी महिला मित्र कैरी सायमंड्स के साथ यहां एक प्रमुख हिंदू मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और नया भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन में उनके साथ मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। खास बात यह रही कि 55 वर्षीय जॉनसन की 31 वर्षीय महिला मित्र चटक गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में थीं।

जॉनसन और सायमंड्स ने लंदन के उत्तर पश्चिम इलाके नेसडेन में प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर जाकर अपना पहला आधिकारिक अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा, ' मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार में हम इस प्रयास में उनका समर्थन करेंगे।'

गुरुवार को होने वाले आम चुनाव में जॉनसन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ओपिनियन पोल में विपक्षी लेबर पार्टी से आगे चल रही है। कश्मीर के मुद्दे पर लेबर पार्टी के कथित भारत विरोधी रूख की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए जॉनसन ने कहा, 'इस देश में किसी भी प्रकार के नस्लवाल या भारत विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है।'

तिलक लगाए और गले में माला पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, 'ब्रिटिश भारतीयों ने पहले भी कंजरवेटिव को जीतने में मदद करने में भूमिका निभाई है। जब मैंने नरेंद्र (मोदी) भाई से यह कहा तो वह हंसने लगे और बोले कि भारतीय सदैव जीतने वाले के साथ रहते हैं।' मंदिर में जॉनसन के साथ गृह मंत्री प्रीति पटेल भी थीं। आमतौर पर पश्चिमी लिबास में रहने वाली पटेल ने भी साड़ी पहन रखी थी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की गर्लफ्रेंड कैरी साइमंडस (लाल साड़ी में) हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए लंदन स्थित एक मंदिर में भारतीय साड़ी पहनकर पहुंची। मंदिर में उनका पारंपरिक तरीके से आदर-सत्कार किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री जॉनसन(दाएं) भी साथ में थे। साभार : ई-इमेज

> **'कंजरवेटिव पार्टी को मिल सकता है बहुमत'**
>
> डेली मेल के मुताबिक इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी महिला मित्र कैरी सायमंड्स गत छह नवंबर को कंजरवेटिव पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के दौरान साथ दिखे थे। बीते शुक्रवार को हुई बहस के बाद कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण में कंजरवेटिव पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की आशा जताई गई है। बीबीसी पर प्रसारित इस बहस का मुख्य मुद्दा ब्रेक्जिट और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश था।

ब्रिटिश संसद में बढ़ सकती है भारतवंशियों की संख्या

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के चुनाव में इस बार भारतीय मूल के प्रत्याशियों का प्रदर्शन जबरदस्त रहने की उम्मीद है। 2017 के चुनाव में 12 भारतवंशी संसद पहुंचे थे। इनमें पहली सिख महिला प्रीत कौर गिल और पहले पगड़ीधारी तनमनजीत सिंह विपक्षी लेबर पार्टी से सांसद चुने गए थे।

इस चुनाव में लेबर पार्टी के नवेंदु मिश्रा, कंजरवेटिव पार्टी के गगन महिंद्रा और गोवा मूल के क्लेयर कूटिन्हो अपनी-अपनी पार्टी के गढ़ों को बचाने के लिए मैदान में हैं। ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के एक विश्लेषण के अनुसार, अगली संसद के लिए विभिन्न देशों के जातीय अल्पसंख्यकों के चुने जाने की उम्मीद है। कंजरवेटिव पार्टी की प्रीति पटेल, आलोक शर्मा, ऋषि सुनक, शैलेश वारा और सुएला ब्रेवरमैन के फिर से चुनकर आने की उम्मीद है। लेबर पार्टी की तरफ से गिल और तनमनजीत को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशी सुरक्षित सीटों से लड़ रहे हैं। इसमें सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद इस्तीफा देने वाले कीथ वाज की बहन वैलेरी वाज, लीजा नैंडी, सीमा मल्होत्रा और वीरेंद्र शर्मा शामिल हैं। ब्रिटिश फ्यूचर के निदेशक सुंदर कटवाला ने कहा, यह भी संभव है कि प्रत्येक 10 में से एक सांसद जातीय अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से हो। एक दशक पहले यह आंकड़ा 40 में एक था। चुनाव लड़ रहे अन्य भारतीय प्रत्याशी कठिन लड़ाई में फंसे हैं। इनमें सारा कुमार शामिल हैं जो लेबर पार्टी के प्रभुत्व वाले लंदन के वेस्ट हैम से किस्मत आजमा रही हैं। यही हाल कंजरवेटिव पार्टी के संजय सेन का है जो लेबर पार्टी के प्रभुत्व वाले वेल्स से किस्मत आजमा रहे हैं। अकाल सिद्धू, नरिंदर सिंह सेंखो, अंजना पटेल, सीमा शाह, पाम गोशाल बैंस, भूपेन दवे, जीत बैंस, कंवल तूर गिल, गुरजीत कौर बैंस और पवित्र कुमार मान भी कड़ी लड़ाई में फंसे हैं।

ये भी जानिए
रिषभ पंत ने नाबाद 33 रन बनाए। यह पिछली 12 पारियों में उनका 30 से ऊपर का सिर्फ दूसरा स्कोर है। इस दौरान उन्होंने अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 65 रन बनाए थे।

विंडीज ने किया हिसाब बराबर

सिमंस का पचासा, विंडीज आठ विकेट से जीता भारत के काम नहीं आया शिवम का पहला अर्धशतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम के लिए रविवार का दिन बेहद खराब रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो तिरुअनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 में भारतीय टीम की सिर्फ एक ही चाल कामयाब रह सकी। टॉस के बाद शीर्ष बल्लेबाजों की विफलता, गेंदबाजी में बेदम, दोयम दर्जे का क्षेत्ररक्षण। यह कुछ ऐसे पहलू थे जिसके बिना टीम इंडिया का मैच जीतना नामुमकिन था। इसी वजह से वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को नौ गेंद शेष रहते आठ विकेट से करारी हार दी। इस जीत के साथ विंडीज ने पिछले मैच में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया। भारतीय टीम ने शिवम दुबे के टी-20 करियर के पहले अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में सात विकेट पर 170 रन का स्कोर बनाया। जवाब में विंडीज ने 18.3 ओवर में दो विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी रही बेदम: वेस्टइंडीज की टीम ने जहां पावरपले में भारतीय टीम का एक विकेट निकाला, सात से 15 ओवर के बीच तीन विकेट निकाले और आखिरी चार ओवरों में तीन विकेट निकाले, लेकिन भारतीय गेंदबाज ऐसा करने में नाकाम रहे। पावरप्ले में एक भी विकेट नहीं, सात से 15 ओवर तक दो और आखिरी ओवर में एक भी विकेट नहीं लेना भारतीय टीम की हार की कहानी बयां कर देती है। यही वजह रही कि पिछले मैच में विफल रहने वाले लेंडल सिमंस (नाबाद 67) और इविन लुइस (40) पहले विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी कर गए।

नहीं मिल सकी अच्छी शुरुआत: इससे पहले, सही मायनों में भारतीय टीम के लिए पिछले मैच की तुलना में इस बार एक चाल को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पहले भारतीय कप्तान कोहली टॉस नहीं जीत पाए और लक्ष्य पाने के मशहूर ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी के लिए विवश हो गए। इसके बावजूद भारतीय टीम को अपने उप कप्तान रोहित शर्मा से इस बार बड़ी पारी की उम्मीद थी, तो दूसरी ओर केएल राहुल पर पूरा भरोसा था। रोहित के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, वह शॉट खेलने के लिए जूझ रहे थे और लग रहा था कि वह कभी भी अपना विकेट गंवा देंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे टीम मुश्किल में आ गई। पिछले मैच में 62 रन की पारी खेलने वाले राहुल, खारे पियरे की गेंद पर हेटमायर को कैच थमाकर चले गए।

विराट की कुर्बानी: पिछले मैच में अकेले दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले विराट ने अपने पसंदीदा स्थान को इस बार अपने युवा खिलाड़ी शिवम के लिए कुर्बान कर दिया। युवा बल्लेबाज शिवम शुरुआत में जूझते नजर आए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रोहित, शिवम को क्या आत्मविश्वास देते, वह खुद ही अपनी लय के लिए तरस रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने किसी तरह से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। रन बनाने के दबाव में रोहित एक गलत शॉट का चयन कर बैठे और जेसन होल्डर ने उन्हें बोल्ड कर दिया।

एक चाल ने पलट दिया पासा: शुरुआत में जूझ रहे शिवम का खेलने का अंदाज विराट के आते ही बदल गया। विराट ने उन्हें खुलकर खेलने की छूट दी। होल्डर पर पहला छक्का लगाने के बाद विराट ने शिवम को ऐसा ही खेलते रहने की अनुमति दी। इसके बाद तो जैसे एक नया शिवम क्रीज पर था। उन्होंने कीरोन पोलार्ड के एक ही ओवर में तीन छक्के जड़ दिए। इस बीच शिवम ने मात्र 27 गेंद में करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। शिवम की फॉर्म को देखते हुए विराट ने कमान पूरी तरह से उनके हाथों में दे दी। शिवम हेडन वाल्श जूनियर की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में मिस टाइम कर कैच थमा गए। शिवम ने 30 गेंद में तीन चौके व चार छक्कों के साथ 54 रन बनाए और पूरी तरह से भारतीय पारी का पासा पलट कर रख दिया।

विराट चूके, अय्यर फेल: शिवम जब पवेलियन लौटे तो विराट से एक बार फिर पिछले मैच की तरह पारी खेलने की उम्मीद थी। किसी तरह से विराट ने जितनी गेंद खेली उतने ही रन बनाए, लेकिन जब अपना गियर बदलने का मौका था, तो वह तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्स की गेंद पर मिस टाइम कर शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े लेंडल सिमंस को कैच थमा गए। विराट ने 17 गेंद में 19 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेश सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर इस बार भी खास नहीं कर सके और मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

स्कोर बोर्ड

टॉस : वेस्टइंडीज (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : लेंडल सिमंस

भारत 170/7 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा बो. होल्डर	15	18	02	00
लोकेश राहुल का. हेटमायर बो. पियरे	11	11	01	00
शिवम दुबे का. हेटमायर बो. वाल्श	54	30	03	04
कोहली का. लेंडल बो. विलियम्स	19	17	02	00
रिषभ पंत नाबाद	33	22	03	01
श्रेयस अय्यर का. किंग बो. वाल्श	10	11	01	00
रवींद्र जडेजा बो. विलियम्स	09	11	00	00
वाशिंगटन सुंदर का. एवं बो. कॉटरेल	00	01	00	00
दीपक चाहर नाबाद	01	01	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-3, नोबॉ-2, वा-13) 18
कुल : 20 ओवर में सात विकेट पर 170 रन

विकेट पतन : 1-24 (राहुल, 3.1), 2-56 (रोहित, 7.4), 3-97 (दुबे, 10.3), 4-120 (कोहली, 13.2), 5-144 (अय्यर, 16.2), 6-164 (जडेजा, 18.6), 7-167 (सुंदर, 19.4)

गेंदबाजी : कॉटरेल 4-0-27-1, खारे पियरे 2-0-11-1, जेसन होल्डर 4-0-42-1, केसरिक 4-0-30-2, कीरोन पोलार्ड 2-0-29-0, हेडन वाल्श जू. 4-0-28-2

वेस्टइंडीज 173/2 (18.3 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लेंडल सिमंस नाबाद	67	45	04	04
इविन लुइस स्टं. पंत बो. सुंदर	40	35	03	03
हेटमायर का. कोहली बो. जडेजा	23	14	00	03
निकोलस पूरन नाबाद	38	18	04	02

अतिरिक्त : (नोबॉ-1, वा-4) 5
कुल : 18.3 ओवर में दो विकेट पर 173 रन, विकेट पतन : 1-73 (लुइस, 9.5), 2-112 (हेटमायर, 13.4)

गेंदबाजी : दीपक 3.3-0-35-0, भुवनेश्वर 4-0-36-0, वाशिंगटन 4-0-26-1, चहल 3-0-36-0, दुबे 2-0-18-0 रवींद्र जडेजा 2-0-22-1

जीत के बाद जश्न मनाते निकोलस पूरन (बायें) और लेंडल सिमंस (दायें) • प्रेट्र

पंत ने दिखाया जुझारूपन

उम्मीद थी कि भारतीय टीम प्रबंधन घरेलू खिलाड़ी संजू सैमसन को मौका देगा। संजू मैदान पर अभ्यास कर रहे थे तो दर्शकों ने संजू-संजू चिल्लाना शुरू किया। खुद कोच रवि शास्त्री ने संजू का हौसला बढ़ाया तो लगा कि संजू मैदान पर उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार रिषभ पंत ने भी जुझारूपन दिखाया। पंत ने फिनिशर की अच्छी भूमिका निभाई और 22 गेंद में तीन चौके और एक छक्के के साथ नाबाद 33 रन बनाए।

कोहली का बिग बॉस रिचर्ड्स को धन्यवाद

क्रिकेट डायरी

तिरुअनंतपुरम, आइएएनएस: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी मैच जिताने वाली 94 रनों की नाबाद पारी के लिए अपनी तारीफ करने वाले वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को धन्यवाद कहा है। कोहली ने तूफानी पारी खेलकर भारत को पहले टी-20 जीत दिलाई थी।

उस पारी के बाद रिचर्ड्स ने कोहली की तारीफ करते हुए उनकी पारी को नायाब करार दिया था। रिचर्ड्स ने ट्विटर पर लिखा था कि शानदार, बेहद शानदार पारी, विराट कोहली। कोहली ने रिचर्ड्स की इस तारीफ का तुरंत जवाब दिया और लिखा कि धन्यवाद बिग बॉस। आपकी तरफ से आई तारीफ मेरे लिए काफी मायने रखती है।

स्मिथ का सीएसए का क्रिकेट निदेशक बनना तय: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ का क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) का क्रिकेट निदेशक बनना तय हो गया है। सीएसए अध्यक्ष क्रिस नेंजानी ने इसकी घोषणा की। नेंजानी ने कहा कि उन्होंने शनिवार को स्मिथ से इस पद पर नियुक्ति के संबंध में बात की है। नेंजानी ने बोर्ड की खास बैठक के बाद कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ग्रीम स्मिथ को अपने साथ जोड़ लिया है और मैं अगले सप्ताह बुधवार तक इस बात की घोषणा करूंगा। स्मिथ ने अगर यह काम संभाल लिया तो फिर उनके पास चयन समिति और कोचिंग स्टाफ के नियुक्ति के लिए सिर्फ दो सप्ताह का समय होगा, क्योंकि इंग्लैंड के साथ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से खेला जाना है। इस बीच, सीएसए का संकट अभी भी जारी है, क्योंकि नेंजानी ने बोर्ड के अपने साथियों के साथ इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया है।

राशिद लतीफ बोले, पीसीबी खुद ही अपना मजाक ना उड़ाए: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने उम्र में फर्जीवाड़े को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की आलोचना की है। लतीफ ने अपने एक ट्वीट में पीसीबी को सलाह दी कि वह खुद ही का अपना मजाक ना उड़ाए। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में शामिल कर लिया गया। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज लतीफ ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अंडर-19 खेलने जा रहे हैं। अंडर-19 खिलाड़ी अंडर-16 खेलने जा रहे है। अंडर-16 के खिलाड़ी अंडर-13 खेल रहे हैं और अंडर-13 खेलने वाले वापस अपने मां की गोद में। 51 वर्षीय लतीफ ने आगे कहा कि खुदा के लिए पीसीबी उनकी सही उम्र बताए। फर्जी डिप्लोमा वाले डॉक्टर से काम करा के अपनी प्रतिष्ठा पर दाग ना लगाएं और ना ही खुद का मजाक उड़ाएं।

इससे पहले पूर्व प्रमुख चयनकर्ता मोहसिन खान ने भी अंडर-19 टीम में नसीम के खेलने के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि नसीम शाह का अंडर-19 टीम में खेलना यह दिखाता है कि हम जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि टूर्नामेंट जीतने पर ध्यान दे रहे हैं। सोचिए जब एक टेस्ट खिलाड़ी जूनियर विश्व कप में खेलेगा तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की क्या छवि बनेगी। पाकिस्तान को हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी-20 और टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था।

राजस्थान रॉयल्स में मामूली हिस्सेदारी पर मुनाफा होगा : वॉर्न

शेन वॉर्न • फाइल फोटो, ट्विटर

मेलबर्न, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न को 2008 में आइपीएल के शुरुआती चरण में इसकी फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में मामूली सी हिस्सेदारी दी गई थी जो आगामी दिनों में उन्हें अच्छा मुनाफा करा सकती है। 'हेराल्ड सन' की रिपोर्ट के अनुसार वॉर्न को 6,67,000 डॉलर (करीब चार करोड़ 75 लाख रुपये) भुगतान के अलावा 2008 में संन्यास से वापसी करने के बाद हर साल के लिए 0.75 प्रतिशत की हिस्सेदारी दी गई। लेकिन अब यह हिस्सेदारी उनके 'बैंक बैलेंस' में इजाफा कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई वॉर्न ने कहा कि यह मेरे करार का हिस्सा था क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका था और मैंने संन्यास से वापसी की थी, उन्होंने मुझे कप्तान और कोच बनने के लिए कहा। साथ ही मुझे कहा कि क्रिकेट टीम को वैसे चलाओ जैसे तुम चलाना चाहते हो। मैं सर्वेसर्वा था। वॉर्न टीम के कोच कम मेंटर और ब्रांड दूत रहे हैं। उन्होंने शानदार तरीके से टीम की अगुआई की और 2008 के शुरुआती आइपीएल चरण में राजस्थान रॉयल्स को खिताब दिलाया। मौजूदा भारतीय स्टार रवींद्र जडेजा उस समय प्रतिभाशाली 'अनकैप' खिलाड़ी थे जिन्हें वॉर्न ने पूरा समर्थन किया और उन्हें 'रॉकस्टार' करार किया था। उन्होंने कहा कि हमें कोई भी खिताबी दौड़ में नहीं मान रहा था, हम सबसे कम दावेदार में शामिल थे, किसी ने भी हमें खिताब जीतने वाली टीम नहीं बताया था। यह आइपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट का पहला साल था जिसमें मालिकों ने खिलाड़ियों को खरीदा और खिलाड़ियों की नीलामी लगी थी। वॉर्न मानते हैं कि अगले दो वर्षों मे इसका मूल्य दोगुना हो जाएगा।

एक नजर में

मानव ने खिताब जीता

नई दिल्ली: भारत के युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने रविवार को कनाडा के मारखम में आइटीटीएफ चैलेंज प्लस बेनेक्स विर्गो नॉर्थ अमेरिकन ओपन का खिताब जीता। दूसरी वरीयता प्राप्त मानव ने पुरुषों के अंडर-21 वर्ग के फाइनल में अर्जेंटीना के मार्टिन बेंटानकोर को 11-3, 11-5, 11-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मानव 2017 के बाद से इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 19 वर्षीय मानव इस खिताबी जीत के साथ ही आइटीटीएफ विश्व टूर अंडर-21 वर्ग में पुरुष सिंगल्स में खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले हरमीत, साथियान और सौम्यजीत घोष यह खिताब जीत चुके हैं। हरमीत और साथियान ने 2012 में क्रमश: ब्राजील और मिस्र में यह खिताब जीता था, जबकि सौम्यजीत ने 2011 में चिली में इस खिताब को अपने नाम किया था। (प्रेट्र)

एआइसीएफ में सब ठीक नहीं

चेन्नई: अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआइसीएफ) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अध्यक्ष पीआर वेंकेटरमन राजा और सचिव भरत सिंह चौहान ने अलग-अलग तारीखों को आम सभा की बैठक बुलाई है। राजा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 14 दिसंबर को चेन्नई में बैठक बुलाई है जबकि चौहान ने इससे पहले 22 दिसंबर को महासंघ के चुनाव को जल्दी कराने के साथ कुछ और मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुग्राम में आम सभा बुलाई है। चौहान ने उम्मीद जताई कि 22 दिसंबर को उनकी बैठक तय समय से होगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह तय तिथि पर होगा। अगर आप मुझे से पूछेंगे तो मैं चाहूंगा का शतरंज का संचालन ठीक से हो। चौहान और राजा के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। (प्रेट्र)

मोहित जीती विरार मैराथन

विरार: मोहित राठौर ने दो घंटे 24 मिनट और 22 सेकेंड के समय के साथ रविवार को यहां आयोजित वसई-विरार मेयर्स मैराथन 2019 को अपने नाम किया, जबकि सेना के अनीश थापा कोर्स रिकॉर्ड के साथ हाफ मैराथन के विजेता बने। राठौर एक घंटे छह मिनट में मैराथन की आधी दौड़ को पूरा कर लिया और वह कोर्स रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 2017 में उप विजेता रहे इस एथलीट को किस्मत का साथ नहीं मिला। तापमान बढ़ने के कारण वह अपनी गति को बरकरार नहीं रख सके, फिर भी सात मिनट के बड़े अंतर से विजेता बने। सुखदेव सिंह (दो घंटे 31 मिनट और 42 सेकेंड) और धर्मेंद्र (दो घंटे 32 मिनट और 39 सेकेंड) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। राठौर ने कहा कि मुझे किसी से चुनौती नहीं मिल रही थी, शायद इसलिए मैं अकेले दौड़ते हुए अपनी गति को बरकरार नहीं रख पाया। (प्रेट्र)

भारत की तेज गेंदबाजी सबसे बेहतरीन : पठान

जागरण संवाददाता, देहरादून: अपनी स्विंग के लिए मशहूर रहे भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने कहा कि वर्तमान में भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, इशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी ऐसे गेंदबाज हैं, जो किसी भी परिस्थिति और पिच पर अपना कमाल दिखा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी मैच खेलने देहरादून आई है। पठान टीम के साथ कोच एवं मेंटर के रूप में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में भी खिलाड़ियों के लिए कांट्रेक्ट सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट संघ के कांट्रेक्ट सिस्टम लागू करने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट बोर्ड राज्य में खिलाड़ियों की ऐसी पौध तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय फलक पर भारत का नाम रोशन करेगी। इरफान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रदेश की टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी। बावजूद इसके काफी कम समय में सीनियर टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी व मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया।

जाफर के लिए यादगार होगा नया सत्र

आज से शुरू होंगे रणजी ट्रॉफी के मैच, 150वां मैच खेलेंगे वसीम व 20 हजार रन के भी करीब

नई दिल्ली, आइएएनएस: भारत के लिए 31 टेस्ट और दो वनडे मैच खेल चुके घरेलू क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर के लिए सोमवार से शुरू हो रहा रणजी ट्रॉफी का 2019-20 सत्र कई मायनों में खास होगा। अगले साल 16 फरवरी को 42 साल के होने जा रहे जाफर ने बीते सत्र में विदर्भ के लिए खेलते हुए 1037 रन बनाए थे। जाफर के शानदार खेल की बदौलत विदर्भ ने लगातार दूसरी बार रणजी खिताब जीता था। अब जाफर फिर से देश के इस सबसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट में अपने बल्ले का जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। जाफर इस नए सत्र को अपने लिए यादगार बनाना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

इस सत्र का पहला मैच जाफर के करियर का 150वां रणजी मैच होगा। वह इसके साथ इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। यही नहीं, जाफर को प्रथम श्रेणी करियर में 20 हजार रनों का आंकड़ा पार करने के लिए 854 रनों की जरूरत है। अभी उनके नाम 19147 रन हैं। यही नहीं, तीन कैच लपकने के साथ ही जाफर इस टूर्नामेंट के इतिहास में 200 कैच लपकने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैचों की 58 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए पांच शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1944 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 212 रहा है। टेस्ट मैचों में जाफर ने 27 कैच भी लपके थे। यही नहीं, टेस्ट में जाफर के नाम दो विकेट भी दर्ज हैं। जहां तक वनडे मैचों की बात है तो जाफर ने दो मैचों में 10 रन बनाए।

वसीम जाफर • फाइल फोटो, इंस्टाग्राम

आज से शुरू होने वाले मुकाबले

मैच	स्थान
एलीट ग्रुप-ए	
आंध्र प्रदेश vs विदर्भ	विजयवाड़ा
हैदराबाद vs गुजरात	हैदराबाद
केरल vs दिल्ली	थुंबा
राजस्थान vs पंजाब	जयपुर
एलीट ग्रुप-बी	
बड़ौदा vs मुंबई	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश vs सौराष्ट्र	धर्मशाला
तमिलनाडु vs कर्नाटक	डिंडिगुल
उत्तर प्रदेश vs रेलवे	मेरठ
एलीट ग्रुप-सी	
असम vs सर्विसेज	गुवाहाटी
छत्तीसगढ़ vs ओडिशा	रायपुर
हरियाणा vs महाराष्ट्र	रोहतक
त्रिपुरा vs झारखंड	अगरतला
उत्तराखंड vs जम्मू-कश्मीर	देहरादून
प्लेट ग्रुप	
बिहार vs पुडुचेरी	पटना
चंडीगढ़ vs अरुणाचल प्रदेश	चंडीगढ़
गोवा vs सिक्किम	पोरवोरिम
मणिपुर vs मिजोरम	कोलकाता
नगालैंड vs मेघालय	सोविमा

मुश्किल परिस्थिति का हिस्सा बनना चाहता हूं : कार्तिक

चेन्नई, प्रेट्र : अनुभवी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हिस्सा बनना चाहेंगे जिससे युवाओं का काम आसान हो और टीम जीत दर्ज कर सके। कार्तिक ने यहां एक कार्यक्रम के इतर कहा कि मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है। मैं खुद से कहता हूं कि खुद ही मैच जीताऊं। मैं उस स्थिति का हिस्सा बनना चाहता हूं ताकि युवाओं को आसानी हो। कार्तिक और उनकी पत्नी स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्तिक ने कहा कि मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि मैं अपने अनुभव और ताकत का इस्तेमाल कर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल कर जीत तक ले जाऊं। आने वाले मैचों में मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करुंगा। कुल मिलाकर मैं अपने बचे क्रिकेट करियर का पूरी तरह से लुत्फ लेना चाहता हूं। आगे रणजी ट्रॉफी सत्र आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करुंगा कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकूं और टीम को जीत दिला सकूं।

साक्षी ने जीता स्वर्ण पदक

दक्षिण एशियाई खेल

साक्षी मलिक • फाइल फोटो, ट्विटर

काठमांडू, प्रेट्र: ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक की अगुआई में भारतीय पहलवानों ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में रविवार को यहां कुश्ती में चार स्वर्ण पदक जीते। भारत ने इस तरह से कुश्ती में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अब तक सभी 12 वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं।

साक्षी ने महिलाओं के 62 किग्रा में आसानी से पहला स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रविंदर ने पुरुष फ्री स्टाइल के 61 किग्रा में सोने का तमगा हासिल किया। साक्षी के चारों मुकाबले एकतरफा रहे, लेकिन रविंदर को पाकिस्तान के एम बिलाल को हराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पवन कुमार (पुरुष फ्री स्टाइल 86 किग्रा) और अंशु (महिला 59 किग्रा) ने भी अपने-अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। सोमवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन गौरव बालियानन (74 किग्रा) और अनिता शेरोन (68 किग्रा) क्रमश: पुरुष और महिला फ्री स्टाइल में अपने मुकाबले खेलेंगे।

15 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में: कॉमनवेल्थ गेम्स के मौजूदा चैंपियन विकास कृष्णन (69 किग्रा) और कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता पिंकी रानी सहित भारत के सात मुक्केबाजों ने रविवार को फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में विकास के अलावा स्पर्श (52 किग्रा), वरिंदर (60 किग्रा) ओर नरेंदर (91 किग्रा से अधिक) ने जबकि महिला वर्ग में पिंकी रानी (51 किग्रा), सोनिया लाठेर (57 किग्रा) और मंजू बोंबोरिया (64 किग्रा) ने फाइनल में प्रवेश किया। भारत के केवल एक मुक्केबाज सचिन (81 किग्रा) को हार का सामना करना पड़ा।

मेसी ने रोनाल्डो को पछाड़ा

- लियोन ने ला लीगा में सर्वाधिक हैट्रिक के मामले में तोड़ा रोनाल्डो का रिकॉर्ड
- मेसी की हैट्रिक की मदद से बार्सिलोना ने मालोर्का को 5-2 से दी शिकस्त

फुटबॉल डायरी

कैंप नाउ, एएफपी: दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में 35वीं हैट्रिक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे बार्सिलोना की टीम रीयल मालोर्का को 5-2 से हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई। मेसी के तीन गोल के अलावा एंटोनी ग्रीजमैन और लुइस सुआरेज ने भी बार्सिलोना की ओर से एक-एक गोल किया।

हालांकि मेसी ने इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ला लीगा में सर्वाधिक हैट्रिक करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ दिया। मेसी ने 35वीं हैट्रिक लगाई, जबकि रोनाल्डो इस लीग में 34 हैट्रिक लगा चुके हैं। मौजूदा सत्र में मेसी अब सर्वाधिक 12 गोल दागे चुके हैं। मालोर्का की ओर से दोनों गोल एंटे बुडमिर ने किए। इस जीत से बार्सिलोना की टीम 15 मैचों में 34 अंक के साथ शीर्ष पर आ गई है। उसने रीयल मैड्रिड को शीर्ष स्थान से हटाया। मैड्रिड के भी 15 मैचों में इतने ही अंक हैं लेकिन खराब गोल अंतर के कारण टीम दूसरे स्थान पर है। मेसी ने इस गोल के साथ ही स्पेनिश लीग में सर्वाधिक गोल करने के रीयल मैड्रिड के खिलाड़ी करीम बेंजमा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में रिकॉर्ड छठी बार बैलन डि ओर पुरस्कार जीतने वाले मेसी इस सत्र में स्पेनिश लीग में अब तक 12 गोल कर चुके हैं। स्पेनिश लीग में मेसी ने 35वीं बार हैट्रिक लगाई है। वहीं, इस सत्र में लीग में उनकी यह चौथी हैट्रिक है। मेजबान बार्सिलोना ने मैच के छठे मिनट में ग्रीजमैन की गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद मेसी ने 17वें मिनट गोल करके स्कोर को 2-0 तक पहुंचा दिया। इस बीच एंटे बुडमिर ने 35वें मिनट में गोल करके मालोर्का के लिए खाता खोल दिया। लेकिन, इसके कुछ मिनट बाद ही मेसी ने एक और गोल दागकर बार्सिलोना को मुकाबले में 3-1 से आगे कर दिया। बार्सिलोना का चौथा गोल 43वें मिनट में जाकर आया। मेजबान टीम के लिए यह गोल सुआरेज ने किया। बार्सिलोना ने इस गोल की मदद से हाफ टाइम तक 4-1 की मजबूत बढ़त बना ली। हाफ टाइम के बाद भी मालोर्का की टीम ने वापसी की और 65वें मिनट में एंटे बुडमिर के एक और गोल की मदद से स्कोर 2-4 कर दिया। मेसी ने आखिरी मिनटों में एक और गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की और बार्सिलोना को 5-2 की शानदार जीत दिला दी। मेसी ने इस गोल के साथ ही इस सत्र में स्पेनिश लीग में सर्वाधिक गोल करने के रीयल मैड्रिड के खिलाड़ी करीम बेंजमा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

मेसी	ला लीगा	रोनाल्डो
462	मैच	292
431	गोल	311
35	हैट्रिक	34

मालोर्का के खिलाफ कैंप नाउ में मैच शुरू होने से पहले प्रशंसकों के सामने अपने बच्चों के साथ बैलन डि ओर की ट्रॉफी दिखाते बार्सिलोना के लियोन मेसी • एपी

लाजियो ने जुवेंटस को हराया

तुरिन (इटली), एएफपी: गत चैंपियन जुवेंटस को लाजियो के खिलाफ रोम में 1-3 से सत्र की पहली हार का सामना करना पड़ा, जिससे सिरी ए फुटबॉल लीग में खिताब की दौड़ रोमांचक हो गई है। आठ बार की जुवेंटस की टीम इस हार से दूसरे स्थान है। इंटर मिलान की टीम 15 मैचों में 38 अंक के साथ शीर्ष पर चल रही है, जबकि जुवेंटस के इतने ही मैचों में उससे दो अंक कम हैं। तीसरे स्थान पर चल रहे लाजियो के भी 15 मैचों में 33 अंक हैं। जुवेंटस के खिलाफ 2003 के बाद घरेलू सरजमीं पर यह लाजियो की पहली जीत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 25वें मिनट में जुवेंटस को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के इंजुरी टाइम में लुइस फेलिप रामोस मार्ची ने लाजियो को बराबरी दिला दी। सर्गेज मिलिनकोविच साविक ने 74वें मिनट में लाजियो को बढ़त दिलाई, जबकि फेलिप काइसेडो ने दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम में एक और गोल दागकर टीम की 3-1 से जीत सुनिश्चित की।

14 लगातार ला लीगा सत्रों में मेसी के 10 से ज्यादा गोल

सत्र	गोल
2006-07	14
2007-08	10
2008-09	23
2009-10	34
2010-11	31
2011-12	50
2012-13	46
2013-14	28
2014-15	43
2015-16	26
2016-17	37
2017-18	34
2018-19	36
2019-20	10*

मेसी की टूर्नामेंटों में हैट्रिक

हैट्रिक	टूर्नामेंट	टीम
35	ला लीगा	बार्सिलोना
03	कोपा डेल रे	बार्सिलोना
08	यूएफा चैंपियंस लीग	बार्सिलोना
01	सुपर कोपा	बार्सिलोना
01	कोपा अमेरिका	अर्जेंटीना
01	फीफा विश्व कप क्वालीफिकेशन	अर्जेंटीना
04	दोस्ताना मैच	अर्जेंटीना

ला लीगा में सर्वाधिक हैट्रिक

खिलाड़ी	कुल हैट्रिक	अंतिम हैट्रिक
लियोन मेसी	35	7 दिसंबर, 2019
रोनाल्डो	34	18 मार्च, 2018
टेलमो जारा	23	15 मार्च, 1953
अल्फ्रेडो डि स्टेफानो	22	15 मार्च, 1964
मुंडो	19	4 मार्च, 1951

53 मै हैट्रिक मेसी ने अपने करियर में लगाई हैं जिसमें 47 बार्सिलोना क्लब के लिए, जबकि छह राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना के लिए हैं

2010 के बाद से बार्सिलोना के मेसी ने ला लीगा में हर साल कम से कम दो हैट्रिक लगाई हैं

2019 में मेसी चार हैट्रिक लगा चुके हैं। उन्होंने सेविया, रीयल बेटिस, सेल्टा विगो और अब मैलोरका के खिलाफ हैट्रिक लगाई

पिता बोले, शिवम जल्द पूरा करेंगे अधूरा काम

उमेश राजपूत, नई दिल्ली : भारत और वेस्टइंडीज के बीच तिरुअनंतपुरम में रविवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में जैसे ही मुंबई के युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे ने करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया तो उनके घर में जश्न मनाया जाने लगा। हालांकि, शिवम के पिता राजेश दुबे भारत की हार के साथ-साथ इस बात से भी थोड़े निराश थे कि उन्होंने शतक का मौका गंवा दिया, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद है कि शिवम जल्द ही इस अधूरे काम को भी पूरा कर लेंगे।

अपना सिर्फ पांचवां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे शिवम जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनकी मां माधुरी, पिता राजेश और दो बड़ी बहनें पूजा और प्रियंका मुंबई स्थित अपने घर पर ही टीवी पर मैच देख रहे थे। उनके साथ शिवम के कुछ दोस्त भी थे। शिवम का अर्धशतक पूरा होते ही सोसायटी के भी कुछ लोग आ गए और बधाई देने लगे। फोन पर भी बधाइयां मिलने लगीं। ऐसे में शिवम की बहनों ने तुरंत मिठाई मंगाकर सभी का मुंह मीठा कराया। राजेश के बड़े भाई रमेश दुबे मिर्जापुर से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल उनकी उम्र 80 साल के करीब है। राजेश ने बताया कि जैसे ही शिवम का अर्धशतक पूरा हुआ तो तुरंत उनके बड़े भाई ने फोन कर बधाई दी। वह शिवम के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। शिवम को क्रिकेटर बनाने में उनके बड़े भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।

हार के बावजूद भारतीय महिला जूनियर टीम बनीं चैंपियन

कैनबरा, प्रेट्र : भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को तीन देशों के हॉकी टूर्नामेंट के अपने चौथे और अंतिम मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों के 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भारतीय टीम ने शीर्ष स्थान के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एबिगेल विलसन ने 15वें और 56वें मिनट में गोल किए जबकि भारत की ओर से एकमात्र गोल गगनदीप कौर ने 53वें मिनट में किया।

लेडिज यूरोपियन टूर में लगातार दूसरी बार रनर अप रहकर मुझे बेहद खुशी है।
– अदिति अशोक, भारतीय महिला गोल्फर

पाकिस्तान का बांग्लादेश को डे-नाइट टेस्ट खेलने का न्यौता

निमंत्रण ▶ अगले महीने दो टेस्ट व तीन टी-20 मैच खेलेगी बांग्लादेश

हाल ही में भारतीय टीम के साथ बांग्लादेश ने कोलकाता में खेला था डे-नाइट टेस्ट

डे-नाइट टेस्ट का एक दृश्य। फाइल फोटो, एपी

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से अगले महीने पाकिस्तान दौरे पर कम से कम एक डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान ने इस डे-नाइट टेस्ट के लिए कराची को चुना है। बांग्लादेश का अगले महीने पाकिस्तान दौरे पर दो टेस्ट और तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलने का कार्यक्रम है। लेकिन बीसीबी अभी भी पाकिस्तान दौरे के लिए सुरक्षा रिपोर्ट और सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है।

बांग्लादेश ने पिछले महीने ही नवंबर में भारत दौरे पर अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच खेला था। एशिया में यह पहला दिन-रात टेस्ट मैच था। वहीं, पाकिस्तान की टीम अब तक चार डे-नाइट टेस्ट मैच खेल चुकी है। टीम ने ये चारों मैच घर से बाहर खेले हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश केवल टी-20 सीरीज ही पाकिस्तान में खेलना चाहता है जबकि टेस्ट सीरीज वह किसी तटस्थ स्थान पर खेलने के इच्छुक है।

बीसीबी के चेयरमैन (क्रिकेट संचालन) अकरम खान ने कहा कि हम पाकिस्तान को टेस्ट और टी-20 सीरीज अलग-अलग स्थान पर खेलने के लिए कह सकते हैं। कौन सी सीरीज पहले खेली जाएगी, यह सुरक्षा रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। कुछ कारणों से अगर हमें इसके (टेस्ट सीरीज) लिए हरी झंडी नहीं मिलती है तो फिर हमें किसी तटस्थ स्थान पर खेलने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। बांग्लादेश ने इस साल अपनी अंडर-16 टीम को पाकिस्तान भेजा था। बीसीबी अब अपने सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल से पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और फिर वह इसे रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

पाकिस्तान की टीम 11 दिसंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी कर रही है। अकरम ने कहा कि श्रीलंका से ज्यादा हमें सरकार की ओर से जारी होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) महत्वपूर्ण है क्योंकि एनओसी मिलने के बाद ही हम इस दौरे के बारे में सोच सकते हैं। हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

ब्रिसबेन हीट ने जीता महिला बिग बैश लीग का खिताब

ब्रिसबेन, एएफपी : ब्रिसबेन हीट ने रविवार को यहां के एलन बॉर्डर क्रिकेट मैदान पर खेले गए महिला बिग बैश लीग (बीबीएल) के फाइनल मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स को छह विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया। ब्रिसबेन हीट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स को निर्धारित 20 ओवरों मे सात विकेट पर 161 रनों पर सीमित किया और फिर विकेटकीपर बेथ मूनी के शानदार नाबाद 56 रनों की बदौलत 18.1 ओवरों में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। बेथ ने 45 गेंदों पर पांच चौके लगाए। बेथ के अलावा सैमी जॉनसन ने 27 और जेस जॉनसन ने 33 रन बनाए। लौरा हैरिस 19 रनों पर नाबाद रहीं। स्ट्राइकर्स की ओर से ताहिला मैक्ग्रा ने दो विकेट लिए।

इससे पहले, स्ट्राइकर्स ने एमांडा वेलिंगटन के 55 रनों की बदौलत 161 रनों का स्कोर खड़ा किया। वेलिंगटन ने 33 गेंदों पर 10 चौके लगाए। उनके अलावा कप्तान सूजी बेट्स ने 27, ताहिला ने 33 और तेगान मैकफेर्लिन ने 18 रन बनाए। हीट की ओर से जॉर्जिया प्रेस्टविज और जेस जॉनसन ने दो-दो विकेट लिए। बेथ को प्लेअर ऑफ द मैच चुना गया। वह फाइनल में लगातार दूसरे साल प्लेअर ऑफ द मैच बनीं। बेथ महिला क्रिकेट में शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं और वह अब से पहले भी कई बेहतरीन पारियों से अपनी टीम को जीत दिलाती आ रही हैं।

राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में छह स्वर्ण जीत रेलवे का शानदार सफर जारी

▶ महिला मुक्केबाजी में सोनिया और भाग्यवती ने कायम रखा अपना वर्चस्व

▶ असम की प्विलाओ बासुमात्री ने भी कड़े मुकाबले में यूथ वर्ल्ड चैंपियन को हराया

कुन्नूर, आइएएनएस : विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली सोनिया चहल (57 किलोग्राम भार वर्ग) और इंडिया ओपन की चैंपियन भाग्यवती काचारी (75 किलोग्राम भार वर्ग) ने रविवार को मुंडायाड इंडोर स्टेडियम में चौथी इलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना वर्चस्व कायम करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के दम पर रेलवे ने इस चैंपियनशिप में छह स्वर्ण पदक जीते। साल 2016 की राष्ट्रीय चैंपियन सोनिया ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए यूथ वर्ल्ड चैंपियन हरियाणा की साक्षी को एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर अपना दूसरा राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया।

एक साल पहले रजत पदक जीतने वाली भाग्यवती ने 81 किग्रा में शैली सिंह को एकतरफा अंदाज में 5-0 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। युवा वर्ल्ड चैंपियन ज्योति ने रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणा की रितु ग्रेवाल को आसानी से 5-0 से हराकर 51 किग्रा वर्ग में स्वर्ण बटोरा। 48 किग्रा में मोनिका ने ऑल इंडिया पुलिस की के बिना देवी को 5-0 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रही असम की प्विलाओ बासुमात्री और उनकी ही राज्य की अंकुशिता बोरो के बीच 64 किग्रा वर्ग में देखने को मिला। कोलोगने विश्व कप रजत पदक विजेता बासुमात्री ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियन बोरो को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित करके स्वर्ण जीता।

रेलवे के लिए छठा स्वर्ण पूर्व एशियाई चैंपियनशिप रजत पदक विजेता पवित्रा ने 60 किग्रा में जीता। पवित्रा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 2017 की विश्व युवा चैंपियन हरियाणा की साक्षी चोपड़ा को 3-2 से हराया। ऑल इंडिया पुलिस को भी कविता चहल (81 प्लस किग्रा) और मीना कुमारी देवी (54 किग्रा) ने दो स्वर्ण दिलाए। अर्जुन पुरस्कार विजेता और दो बार की विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता कविता ने हरियाणा की अनुपमा को 5-0 से हराया।

मीना कुमार देवी ने भी अपने स्वर्ण पदक की रक्षा की। हालांकि उनका सफर आसान नहीं रहा। रेलवे की मीनाक्षी ने मीना को कड़ी टक्कर दी लेकिन मीना ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 4-1 से जीत हासिल की। हरियाणा को एकमात्र स्वर्ण 75 किग्रा वर्ग में नुपुर ने दिलाया। नुपुर ने बीते साल रजत पदक जीता था लेकिन इस साल वह अपने पदक का रंग बदलने में सफल रहीं।

नुपुर ने फाइनल में केरल की इंद्राजा को 4-1 से हराया। राजस्थान ने भी स्वर्ण जीतने वाली टीमों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। उसके लिए ललिता ने 69 किग्रा वर्ग में स्वर्ण जीता। ललिता ने रेलवे की मीना रानी को 5-0 से हराया।

असम की प्विलाओ बासुमात्री। आइएएनएस

स्वीडन, थाईलैंड के साथ मैच खेलेगी महिला यू-17 टीम

मुंबई : भारतीय महिला अंडर-17 फुटबॉल टीम अगले सप्ताह से यहां मुंबई फुटबॉल एरेना में एक टूर्नामेंट में स्वीडन और थाईलैंड की मेजबानी करेगी। भारत को अगले साल अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करनी है और ऐसे में तीन देशों के बीच होने वाला यह टूर्नामेंट विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

स्वीडन की टीम महिला फुटबॉल में विश्व रैंकिंग में टॉप टीम मानी जाती है। स्वीडन की सीनियर टीम ने फ्रांस में इस साल हुए विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया था। दूसरी तरफ थाईलैंड की टीम भी एशिया में काफी मजबूत टीम मानी जाती है। टीम ने लगातार दो बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है। तीन देशों के बीच होने वाले टूर्नामेंट का पहला मैच में 13 दिसंबर को भारत और स्वीडन के बीच खेला जाएगा। 15 दिसंबर को थाईलैंड का सामना स्वीडन से, 17 दिसंबर को भारत का सामना थाईलैंड से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 19 दिसंबर को खेला जाएगा।

भारतीय टीम : गोलकीपर : मंजू गांझू, अंशिका, तनु।

डिफेंडर्स : पूर्णिमा कुमारी, ज्योति कुमारी, निर्मला देवी फनजौबम, शिल्की देवी हेमाम, कृतिना देवी थौनाओजम, निशा, अस्तम ओराओम।

मिडफील्डर्स : मार्टिना थोकोकम, प्रियंगका देवी नोरेम, बबीना देवी लिशम , अमीषा बक्सला, अवेका सिंह, किरण, डेजी क्रैस्टो, सुनीता मुंडा, मरियम्मल बालमुरुगन।

फॉरवडर्स : सुमति कुमारी, लिंडा कोम सेटरे, साईं सांखे।

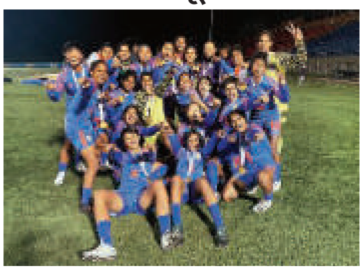

भारतीय महिला यूथ-17 फुटबॉल टीम। फाइल फोटो, आइएएनएस

लिवरपूल ने बोर्नमाउथ को 3-0 से हराया

लंदन, रायटर : अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही मैनेजर जुर्जेन क्लोप की टीम लिवरपूल ने शनिवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मुकाबले में 15वें नंबर की टीम बोर्नमाउथ को आसानी से 3-0 से हरा दिया। लिवरपूल के लिए तीन गोल अलेक्स ओक्सलैंड-चेंबरलिन, नबी केइटा और मुहम्मद सलाह ने दागे। लिवरपूल के 16 मैचों में 46 अंक हैं जबकि बोर्नमाउथ के इतने ही मैचों में 16 अंक है।

लिवरपूल के खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से बोर्नमाउथ की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसका फायदा अलेक्स ओक्सलैंड-चेंबरलिन को मिला जिन्होंने 35वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। हेंडरसन ने बॉक्स के बाहर अलेक्स को गेंद पास की जिन्होंने गेंद को उसकी सही जगह पर भेज दिया। हालांकि पहला हाफ खत्म होने में सिर्फ एक मिनट बचा था और इस दौरान केइट और सलाह की जोड़ी ने मैच में अपनी टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। इस बार सलाह ने केइट की मदद से गोल दागा। पहले हाफ में लिवरपूल 2-0 से आगे रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में इस जोड़ी ने मिलकर एक और गोल कर दिया। केइटा ने गेंद को सलाह के पास भेजी और फिर सलाह ने चतुराई से बायें पैर से गेंद को गोल पोस्ट में भेजकर टीम को 3-0 की मजबूत बढ़त दिलाई। अंतिम समय तक यही स्कोर रहा और लिवरपूल ने जीत हासिल की।

केन, सोन ह्यूंग-मीन और अली की जुगलबंदी : टॉटनहम की बर्नले पर 5-0 की जीत में हैरी केन, सोन ह्यूंग-मीन और डेले अली की जुगलबंदी ने शानदार काम किया। केन ने मैच में दो गोल दागे जबकि एक गोल करने में मदद की।

बार्सिलोना को हटाकर शीर्ष पर पहुंचा रीयल मैड्रिड

मैड्रिड, रायटर : रीयल मैड्रिड की टीम शनिवार को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मैच में एस्पेनयॉल को 2-0 से मात देकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। मैड्रिड ने बार्सिलोना को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। मैड्रिड के लिए दो गोल राफेल वरने 37वें मिनट और करीम बेंजेमा ने 79वें मिनट में किए। हालांकि फेरलैंड मेंडी को 83वें मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया जिसके कारण मैड्रिड को यहां से मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच अंकों का अंतर तीन का है।

विविध

फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बने फार्मासिस्टों पर गिरेगी गाज

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

▶ 70 पंजीकरण रद करने व एफआइआर कराने की तैयारी में स्टेट फार्मेसी काउंसिल

हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल दूसरे राज्यों से बारहवीं के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे बने फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में काउंसिल ने सबसे पहले सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड, मध्य भारत ग्वालियर से बारहवीं करने के बाद फार्मासिस्ट बने 70 लोगों का पंजीकरण रद कर दिया है। इसके अलावा काउंसिल ने बारहवीं करके फार्मेसी डिप्लोमा या डिग्री लेने वालों के बारहवीं कक्षा के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने का काम शुरू कर दिया है।

सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड, मध्य भारत ग्वालियर को सीबीआइ ने अपनी जांच में फर्जी पाया था इसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से पिछले माह एक प्रपत्र जारी हुआ था। इसमें सभी विभागों को आदेश दिए गए थे कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मियों की पदोन्नति से लेकर नियुक्ति तक में यह जांच लें कि कोई सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड, मध्य भारत ग्वालियर से उत्तीर्ण तो नहीं है। मुख्य सचिव के इस आदेश के बाद हरियाणा के सभी विभागों में हड़कंप मचा है। कर्मचारियों को डर सता रहा है कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जांच की आंच उन तक न पहुंच जाए।

काउंसिल अन्य राज्यों से बारहवीं करके फार्मासिस्ट बने सभी के प्रमाण पत्र जांचने की प्रक्रिया में जुटी है मगर इसके पूरा होने में समय लगेगा। 2015 में काउंसिल ने ऐसे 44 लोगों के खिलाफ पंचकूला थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी जिन्होंने बारहवीं के फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर फार्मेसी डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है।
– धनेश अदलखा, चेयरमैन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हरियाणा

पंजाब में चल रहा है गैरहाजिर रहने पर भी फार्मेसी कराने का व्यापार

स्टेट फार्मेसी काउंसिल बारहवीं के फर्जी प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद अगली कार्रवाई उन फार्मासिस्ट के खिलाफ भी करने जा रही है जिन्होंने अपने शिक्षण संस्थानों में गैर हाजिर रहते हुए भी फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री पा ली है। ऐसे फार्मासिस्टों को फार्मेसी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और काउंसिल पंजाब सहित अन्य राज्यों के ऐसे संस्थानों की विजिलेंस जांच की मांग कर रही है जो गैर हाजिर रहे बच्चों को बिना पढ़ाई के डिप्लोमा या डिग्री दे रहे हैं।

मप्र में इंजीनियर ने उठाई बंदूक, धमकी देने वालों को तीन घंटे तक दी चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह

▶ स्थानीय तहसील ग्राउंड में रविवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बंदूक लेकर करते रहे इंतजार

मध्य प्रदेश के दमोह में सीएमएचओ कार्यालय के निर्माण शाखा में पदस्थ सब इंजीनियर अभिषेक चक्रवर्ती ने अपने विरोधियों की धमकी का जवाब देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। वह रविवार सुबह नौ बजे अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर स्थानीय तहसील ग्राउंड पहुंचे और दोपहर करीब 12 बजे तक मैदान के मंच पर घूमते रहे।

अभिषेक चक्रवर्ती ने बताया कि उनके विभाग के निर्माण कार्य करने वाले कुछ लोग अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, लेकिन वह शासन के नियमों का पालन कराने के लिए कहते हैं। ये तरीका ठेकेदार व उनके साथियों को पसंद नहीं और इसलिए वे उन्हें बार-बार धमकी देते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी इसलिए उन्होंने तय किया कि विरोधियों को वह एक मौका देंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही सूचना जारी की थी कि जो भी उनसे बैर रखता है और जो कुछ करना चाहता है, वह मैदान में आकर अपनी क्षमता का परिचय दे सकता है।

दमोह में स्थानीय तहसील ग्राउंड में बंदूक लेकर खड़े सब इंजीनियर अभिषेक चक्रवर्ती। नईदुनिया

यदि कोई हमला करेगा तो चला देंगे गोली : अभिषेक चक्रवर्ती से जब पूछा गया कि वह बंदूक लेकर क्यों आए हैं तो उनका कहना था कि वह उनके धर्म की विद्या है। भगवान राम ने भी धर्म युद्ध के लिए हथियार उठाए थे और यह भी धर्म युद्ध ही है। उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बंदूक नहीं उठाई है। लेकिन जो लोग उन्हें धमका रहे हैं, यदि वे यहां आते हैं और उन पर हमला करते हैं तो वह परिस्थिति के हिसाब से गोली चलाने से नहीं चूकेंगे।

जब उनसे पूछा कि यहां पर बंदूक लेकर घूमने के लिए क्या उन्होंने पुलिस से अनुमति ली या पुलिस में शिकायत की तो उनका कहना था कि कथित लोगों ने उनका अपमान किया है इसलिए उन्हें यही ठीक लगा कि वह सीधे तौर पर मामले का निपटारा कर लें। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले विज्ञप्ति जारी करते हुए साफ किया था कि वह तीन घंटे रविवार को तहसील मैदान में रहेंगे। इन दिनों में किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें पुलिस की अनुमति है। उधर, एसपी विवेक सिंह ने कहा कि ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्हें कोई शिकायत थी तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहते या पुलिस में शिकायत करते। बंदूक लेकर घूमना गलत है। मामले में कार्रवाई करेंगे।

30 साल बाद छत्तीसगढ़ में खुजली बनी महामारी

नईदुनिया, रायपुर

▶ एम्स, आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्रों में पहुंच रहे रोज 50 मरीज

बच्चों की गर्दन के नीचे के अंगों में अगर छोटे-छोटे दाने दिखें और तेज खुजली हो रही हो तो नजरअंदाज न करें। यह अति संक्रामक खुजली रोग है, जिसे मेडिकल की भाषा में स्केबीज कहते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के त्वचा विज्ञान विभाग की ओपीडी में रोज 200 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 20 मरीज स्केबीज से पीड़ित होते हैं। आंबेडकर अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक केंद्र को मिलाकर रोज 50 मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, पहली बार इतने अधिक स्केबीज पीड़ित आ रहे हैं।

बच्चे अधिक होते हैं प्रभावित : स्केबीज बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। स्कूल, हॉस्टल, बोर्डिंग में रहने के दौरान पीड़ित बच्चों से यह फैलती है। समय पर उपचार नहीं करने से पीड़ित मरीज के साथ पूरे परिवार को लंबे समय तक प्रभावित कर देती है। इसके लक्षण है त्वचा पर लाल चकत्ते, दाने और तेज खुजली होना।

अलग से की जा रही मॉनिटरिंग : स्केबीज पीड़ित लोगों की एम्स में मॉनिटरिंग की जा रही है। एम्स रायपुर के डर्मेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. सत्यकी गांगुली ने बताया कि ओपीडी में दो वॉलिंटियर की अलग से ड्यूटी तक लगा दी है, जो स्केबीज के मरीजों को बताते हैं कि उन्हें क्या-क्या सावधानी बरतनी है। सारकॉप्टीज स्केबियाई नामक माइट (परजीवी) से स्केबीज फैलती है। इस परजीवी का आकार घुन से भी छोटा होता है।

डॉक्टरों के अनुसार इस तरह का संक्रामक रोग पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के समय जवानों में देखा गया था। यह संक्रामक के रूप में 1960 में फैला था। उसके बाद 1990 में स्केबीज का अटैक हुआ था।

ऐसे रखें ध्यान

- स्केबीज में पूरे परिवार का इलाज किया जाता है।
- घर की सभी चादर और कपड़ों को गरम पानी में धोने से यह इंफेक्शन खत्म होता है।
- माइट सामान्य तौर पर कुत्ते और बिल्लियों के शरीर में पाए जाते हैं।
- क्रीम हफ्ते में सिर्फ एक बार रात को सोते समय पूरा परिवार लगाएं।
- कई मरीज सिर्फ इंफेक्टेड हिस्से पर क्रीम लगाते हैं, जिससे रोग खत्म नहीं होता

स्केबीज संक्रामक रोग जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जरा भी लक्षण दिखें तो एम्स के डर्मेटोलॉजी ओपीडी में दिखाएं। यह 15 दिन में ठीक हो जाएगा।
– डॉ. सत्यकी गांगुली, विभागाध्यक्ष, डर्मेटोलॉजी, एम्स रायपुर

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले भाई दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने द्वारका से गिरफ्तार किया। मौके से तीन कंप्यूटर व पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपित नौकरी डॉट कॉम व इसके जैसी अन्य साइट्स से बेरोजगारों को डाटा जुटाकर नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करते थे।

डीसीपी दक्षिणी-पूर्वी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि शिकंजे में आए जालसाज भाई सत्यम कुमार व कुमार शिवम निवासी सीतामढ़ी, बिहार हैं। सत्यम ने बीसीए और शिवम ने एमबीए किया हुआ है। इस समय दोनों द्वारका स्थित फ्लैट में रहते थे। आरोपितों ने गत जुलाई में भारतीय वायु सेना से रिटायर जूनियर वारंट अफसर के साथ 1.42 लाख की ठगी की थी। आरोपितों ने नौकरी डॉट कॉम की तरह नौकरी-गो-डॉट-कॉम, नौकरी-प्लस-डॉट-कॉम और नौकरी-बिल्डर-डॉट-कॉम नाम से फेक जॉब पोर्टल बना रखे थे। जॉब मुहैया कराने वाली साइट से बेरोजगारों का डाटा उठाकर वे उन्हें इन तीनों फेक जॉब पोर्टल के नाम पर मेल भेजते थे। इसके बाद कॉल कर नामी कंपनियों में जॉब लगवाने की बात कहते थे।

झांसे में आए बेरोजगार युवकों से बॉयोडाटा बनाने, इंटरव्यू फिक्स कराने, इंटरव्यू जल्दी कराने, रेफरेंस देने व ऑफर लेट दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। आरोपित पीड़ितों से कभी मिलते नहीं थे। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या पेमेंट एप से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कराते थे। ठगी के लिए कॉल कराने के लिए आरोपितों ने द्वारका में किराये का फ्लैट लेकर कॉल सेंटर बना रखा था।

रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर वकील अहमद से 13 जुलाई को नौकरी डॉट कॉम पर जॉब के लिए प्रोफाइल डाला। 15 जुलाई को आरोपितों ने उन्हें कॉल किया और जॉब लगवाने के नाम पर ठगी की। काफी समय बाद भी नौकरी न मिलने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रिकार्ड खंगालने पर पता चला है कि आरोपित प्रति माह करीब 12 लाख रुपये बेरोजगारों से ठगते थे।

वर्ष 2016 में सत्यम दिल्ली के एक कॉल सेंटर में टेलीकॉलर का काम करता था। वहां उसकी मुलाकात सहकर्मी अविनाश से हुई। अविनाश ने उससे जल्द पैसा कमाने के लिए फर्जी जॉब पोर्टल बनाकर बेरोजगारों को ठगने की बात कही। दोनों ने फेक जॉब पोर्टल बनाकर ठगी का धंधा शुरू किया।

सहकारी बैंक नाभा के परिसर में मैनेजर ने उगाए पोस्त के पौधे, केस

जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)

नाभा के सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में मैनेजर ने अपने कर्मचारियों के साथ पोस्त के पौधे लगा दिए। तीन क्यारियों में उगाए इन पौधों की लंबाई करीब आठ इंच है। गांव मैहस के जमींदार बलवीर सिंह ने जब इन पौधों को देखा तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत दी। कोतवाली नाभा पुलिस ने पौधों को कटवाकर कब्जे ले लिया है।

बैंक मैनेजर सतनाम सिंह और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपित फरार हैं। आरोपित बैंक मैनेजर की सेवानिवृत्ति में कुछ समय ही शेष बचे हैं। जमींदार बलवीर सिंह ने बताया कि उनका सहकारी बैंक से करीब दो लाख का रुपये का लोन पास हुआ था। रकम लेने के लिए वह शुक्रवार को बैंक पहुंचे तो शनिवार के लिए बुलाया गया। शनिवार को बैंक गए तो देखा कि बैंक परिसर में चारपाई के आकार की तीन क्यारियां थीं। इनमें पोस्त के पौधे लगे थे। जब उन्होंने इस पोस्त की खेती की वीडियो बनानी शुरू की तो बैंक मैनेजर व कुछ अन्य कर्मचारियों ने धक्का-मुक्की कर दी। इसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत कर दी। बैंक प्रबंधक मान गए कि यह पोस्त के ही पौधे हैं। पुलिस ने पौधे कटवा जांच के लिए लैब में भेज दिए। सहकारी बैंक के अंदर पोस्त की खेती के बारे में बहुत से लोगों को पता था, लेकिन किसी ने पुलिस व प्रशासन को शिकायत नहीं की। इसकी वजह बैंक मैनेजर का दबदबा था।

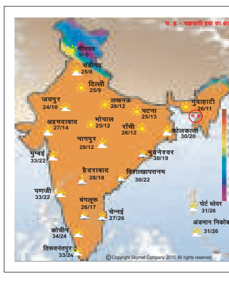

मौसम विशेष

कश्मीर की घाटी में कंपकपाती सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। दिन ठंडा रहेगा। जम्मू क्षेत्र, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के साथ ठंडी सुबह में हल्का कोहरा व कुहासा रहेगा। बादलों में वृद्धि होगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में तापमान में हल्की वृद्धि होगी। मौसम शुष्क बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/आंबा	अहमदाबाद	30/17/व
कोलकाता	31/21/सा	बड़ौदा	31/19/सा
चेन्नई	30/23/व	नागपुर	30/13/आंबा
हैदराबाद	30/19/सा	इन्दौर	30/18/आंबा
बंगलूरू	28/17/सा	राँची	28/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/25/सा	पटना	27/13/आंबा
गुवाहाटी	24/16/आंबा	जमशेदपुर	29/18/सा
गंगटोक	05/-1/आंबा	पुणे	31/19/व

संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की हुई पहली बैठक

1946 में आज ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉ सच्चिदानंद को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि दो दिन बाद डॉ राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में आठ समितियों का गठन किया गया जिन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

सबसे लंबा टीवी धारावाहिक कोरोनेशन स्ट्रीट शुरू हुआ

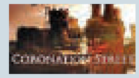

आज ही के दिन 1960 में दुनिया का सबसे लंबे समय तक हर रोज चलने वाला धारावाहिक 'कोरोनेशन स्ट्रीट' का प्रसारण शुरू हुआ था। इसके अब तक 9 हजार 945 एपिसोड और 51 सीजन आ चुके हैं। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है।

बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को जन्मदिन मुबारक

अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1945 में पटना में हुआ था। अपनी बुलंद आवाज से हर किसी को 'खामोश' करने वाले सिन्हा ने कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। पहली फिल्म 1969 में आई 'साजन' थी। पिछले साल उनकी जीवनी 'एनिथिंग बट खामोश' रिलीज हुई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे। सिन्हा ने इसी साल भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा।

ज्वालामुखी की चट्टानें भी बढ़ाती हैं ग्लोबल वार्मिंग

चिंताजनक ▶ ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन में सामने आई बात

कहा– वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाने के तरीकों में करना होगा बदलाव

लंदन, प्रेट्र : ज्वालामुखी की चट्टानों के सक्रिय होने के बाद इनसे उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि हमारे वायुमंडल पर इसका प्रभाव पुराने अनुमानों से कहीं ज्यादा पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष सामने आने के बाद वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाने के अपने पुराने तरीकों में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।

नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी के भूगर्भ में बदलावों के कारण पिछले 6.5 करोड़ साल में सबसे ज्यादा अस्थायी ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि मैग्मा के पृथ्वी की सतह पर आने और ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के बीच क्या संबंध हैं।

ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका लार्ज इगनिस प्रोविंसेज

प्रतीकात्मक

(एलआइपी) भी निभाते हैं। एलआइपी उन क्षेत्रों को कहते हैं, जहां आग्नेय चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती हैं। भूगर्भिक बदलावों के चलते समय-समय पर इसके क्रस्ट से मैग्मा सतह की ओर निकलते रहता है। जागृत ज्वालामुखी को एलआइपी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

ऐसे किया अध्ययन: इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एक मॉडल बनाकर लगभग 5.5 करोड़ साल के अंतराल में कार्बन उत्सर्जन के कारण तापमान में आए बदलावों का आंकलन किया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने उत्तरी अटलांटिक के आग्नेय चट्टानों वाले हिस्सों में ग्रीनहाउस गैसों के प्रवाह की भी गणना की। पृथ्वी पर ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे और ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं।

आग्नेय चट्टानें भी करती हैं कार्बन उत्सर्जन: यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के लेक्चरर और इस अध्ययन के सह-लेखक स्टीफन जोन्स ने कहा, 'हमने आग्नेय चट्टानों से प्रवाहित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों का पता लगाने के साथ मैग्मा बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर यह पता लगाया कि कार्बन उत्सर्जन के लिए ये चट्टानें कितनी जिम्मेदार होती हैं।' जोन्स ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमाने पाया कि पिछले 6.5 करोड़ साल में इन चट्टानों में ज्वालामुखी सक्रिय होने से ग्रीनहाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सजर्न हुआ है।'

जलवायु परितर्वन के लिए हैं जिम्मेदार : उन्होंने कहा, 'इसलिए कहा जाता सकता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जितने अन्य कारक जिम्मेदार हैं, उतनी ही ये आग्नेय चट्टानें भी जिम्मेदार हैं। इन चट्टानों से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है।

दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी

ज्वालामुखी किसी दानव से कम नहीं है। जब तक ये सुप्तावस्था में पड़े हैं तब तक सब ठीक है लेकिन जैसे ही ये जागृत होते हैं तो एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेते हैं। दुनियाभर में ऐसे कई ज्वालामुखी हैं। अकेले लैटिन अमरीका में दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से कई बेहद खतरनाक भी हैं। आइए एक नजर डालते हैं विनाशकारी ज्वालामुखियों पर....

प्रतीकात्मक

कोलिमा, मैक्सिको

यह सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। यह समय-समय पर राख और धुआं छोड़ता रहता है। इसकी ऊंचाई 3280 मीटर है। वर्ष 2015 और 2016 में इसके राख उगलने के कारण आसपास के इलाके खाली करा दिए गए थे।

पोपोकटेपेटल, मैक्सिको

यह ज्वालामुखी 5,452 मीटर ऊंचा है और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह मैक्सिको सिटी से दक्षिण-पूर्व में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 1994 के बाद यह ज्वालामुखी सक्रिय है। इससे राख और लावा निकलता रहता है।

ग्लैरस, कोलंबिया

कोलंबिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 1993 में हुए एक विस्फोट में वैज्ञानिकों के एक समूह और पर्यटकों की यहां मौत हो गई थी, क्योंकि वे सभी लोग ज्वावालामुखी के क्रेटर के भीतर गए थे।

तुरीआलबा, कोस्टा रिका

यह कैलिफोर्निया के सैन जोंस शहर के करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। 2016 में इसमें विस्फोट हुआ था।

वाट्सएप अब कॉल वेटिंग की भी देगा जानकारी

प्रतीकात्मक

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक के स्वामित्व वाला वाट्सएप अब कॉल वेटिंग फीचर के साथ एक नए वॉइसओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइडर भी बन गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमें कॉल करने का प्रयास करता है तो अधिकतर फोन और ऑपरेटर बता देते हैं कि कोई हमें कॉल कर रहा है और उसकी कॉल वेटिंग में है। कुछ ही वीओआइपी सर्विस इसका समर्थन भी कर रही हैं, पर अभी तक वाट्सएप इसमें नहीं था। यह सेवा वाट्सएप पर भी मिलेगी। अभी तक, जब आप फोन पर व्यस्त होते थे और कोई आपको वाट्सएप पर कॉल करने का प्रयास करता था तो उन्हें घंटी सुनाई देती थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता था। अंत में कॉल अपने आप कट जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, वाट्सएप पर कॉल वेटिंग वी 2.19.352 स्टेबल (एपीके मिरर) और इससे ऊपर के वाट्सएप वर्जन लिए उपलब्ध रहेगी। वहीं, वाट्सएप बिजनेस पर वी 2.19.128 (एपीके मिरर) के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इधर-उधर की

स्वाद के चक्कर में दांत निगल गई महिला

लंदन, एजेंसी: पेस्ट्री खाने से पहले आप कितना सोचते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन 52 वर्षीय एंजिला मैकगिल जीवन में कभी भी पेस्ट्री का स्वाद नहीं चखना चाहेंगी। दरअसल वह क्रिसमस के लिए मिठाई बना रही थीं। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि थोड़ा स्वाद चख लिया जाए। जब वे पेस्ट्री खा रही थीं, उसी दौरान उनके दो नकली दांत निकलकर अंदर चले गए। शुरू में तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन दर्द बढ़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि दोनों नकली दांत उनके पेट के अंदर चले गए हैं, तो वे परेशान हो उठीं। एक्सरे के दौरान पता चला कि उनके गले के आधे हिस्से में जाकर यह दोनों दांत अटक गए हैं। उन्हें पिछले महीने ही नकली दांत लगाए गए थे। दांत निकालने के बाद उन्हें अब आराम है, लेकिन पेस्ट्री खाने से तो उन्होंने तौबा कर ली।

शोध अनुसंधान

ब्लड टेस्ट से चलेगा रात में हाई बीपी के खतरे का पता

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (ओएसए) के मरीजों में कई बार रिवर्स डिपिंग की समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या में रात में सोते समय ब्लड प्रेशर कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। अब वैज्ञानिकों ने इस खतरे का पता लगाने के लिए एक सामान्य जांच की प्रक्रिया ईजाद की है। इसमें खून की जांच से यह पता लगाना संभव हो सकता है कि ओएसए से पीड़ित किस व्यक्ति में रिवर्स डिपिंग का खतरा है। रिवर्स डिपिंग के कारण व्यक्ति में दिल की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ओएसए की स्थिति में सोते-सोते अचानक सांस अटक जाती है। खर्राटे आना इसके लक्षणों में शुमार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओएसए से पीड़ित लोगों में अगर समय रहते रिवर्स डिपिंग के लक्षणों का पता चल जाए, तो उन्हें दिल की बीमारियों व अन्य खतरों से बचाना संभव हो सकता है। - आइएएनएस

व्यायाम से कम होता है असमय मौत का खतरा

कठिन व्यायाम करने वाली महिलाओं में दिल की बीमारियों, कैंसर और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण असमय मौत का खतरा कम रहता है। हालिया अध्ययन के दौरान महिलाओं की व्यायाम करने की क्षमता और इस दौरान उनके दिल की गतिविधियों को परखा गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया था। इन सभी को ट्रेडमिल पर व्यायाम करने को कहा गया। महिलाओं को धीरे-धीरे गति बढ़ाने और तब तक व्यायाम करने को कहा गया जब तक कि थकान का अनुभव न हो। 4.6 साल तक चले अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष दिया कि जिन महिलाओं ने तेज व्यायाम किया उनमें विभिन्न बीमारियों के कारण असमय मौत का खतरा कम पाया गया। उन्होंने कहा कि व्यायाम के दौरान दिल का सही से काम करना सेहत के लिए सबसे अच्छा संकेत है। - आइएएनएस

अलग होती है अवसादग्रस्त रोगियों के मस्तिष्क की संरचना

▶ **अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लगाया पता**

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : शोधकर्ताओं ने उन बच्चों के मस्तिष्क की संरचनात्मक बनावट में अंतर पाया है जिन्हें अवसादग्रस्त माता-पिता के कारण यह बीमारी आनुवंशिक रूप से मिलने का खतरा ज्यादा रहता है। अवसाद यानी डिप्रेशन एक सामान्य और दुर्बल मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न होती है लेकिन अवसाद के कारण बहुत पेचीदे होते हैं। आनुवंशिक रूप में यह बीमारी माता-पिता से मिलने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अवसादग्रस्त माता-पिता के बच्चों को अब यह बीमारी होने की आशंका अन्य के मुकाबले दो से तीन गुना अधिक होती है।

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और इस अध्ययन के लेखक रैंडी पी. ने कहा, ' इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि जिन्हें यह बीमारी आनुवंशिक रूप से मिलने का जोखिम ज्यादा होता है, उनके मस्तिष्क की संरचनात्मक बनावट में भिन्नता यह बताती है कि उन बच्चों में शुरुआती वर्षों में ही डिप्रेशन पनपने का खतरा अधिक रहता है।' उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम समय रहते ही एमआरआइ के जिरये मस्तिष्क में आए बदलावों का पता लगाएं और डॉक्टर की सलाह लेकर उसका उपचार कराएं।

जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ रहा है पक्षियों का आकार

▶ **मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा**

▶ **1978 से 2016 के बीच पक्षियों की 52 प्रजातियों पर किया शोध**

▶ **यह अध्ययन ईकोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है**

वाशिंगटन, प्रेट्र : लगातार गर्म होती जलवायु के कारण कई पक्षियों को आकार तो सिकुड़ रहा है, लेकिन इनके पंखों का फैलाव ज्यादा होने लगा है। जलवायु परिवर्तन के खतरों का आकलन करने वाले एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है।

अमेरिका की मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शिकागो में इमारतों से टकराने के कारण नीचे गिरने वाले प्रवासी पक्षियों की 52 प्रजातियों के एक डाटा सेट का विश्लेषण कर यह दावा किया है।

अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि 1978 से 2016 तक 52 प्रजातियों के पक्षियों के शरीर का आकार घट गया है और 49 प्रजातियों में सांख्यिकीय रूप से भारी कमी आई है। इस अध्ययन के परिणाम ईकोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इसमें बताया गया है कि इस अवधि में 40 पक्षियों की प्रजातियां ऐसी हैं, जिनके पंखों का आकार बढ़ गया है। इसमें अब फैलाव अपेक्षाकृत ज्यादा हो गया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक ब्रायन वीक्स ने कहा, 'बढ़ते तापमान के कारण इन पक्षियों के शरीर का आकार घट रहा है। लेकिन यह बात जरूर चौंकाने वाली है कि इससे केवल एक ही प्रजाति के पक्षी प्रभावित नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर पक्षियों में तापमान बढ़ने के कारण हुए बदलावों को देखा गया। शोधकर्ताओं ने कहा, 'पुराने अध्ययन में ऐसी कई संभावनाएं जताई जा रही थी कि जलवायु परिवर्तन का पक्षियों भी सर्वाधिक असर पड़ रहा है, जो सच साबित होता दिख रहा है।' उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर गर्मी बढ़ने से पक्षियों की मौत तो आम बात है, पर आकार सिकुड़ने का मतलब है कि एक लंबी अवधि से पक्षी भी ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा कि जिस दर से आज पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है यदि इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हो सकता है कि भविष्य में कई पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

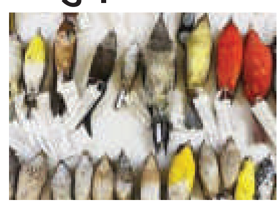

शिकागों में इमारतों के टकराकर नीचे गिरे मृत पक्षी। फाइल

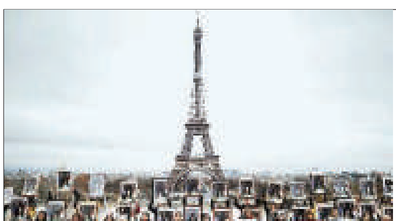

फ्रांस के राष्ट्रपति का उलटा पोर्ट्रेट लेकर प्रदर्शन

पेरिस में विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के सामने हजारों की संख्या में जलवायु कार्यकर्ताओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का पोर्ट्रेट उलटा करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीओपी25 के नेताओं से जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस समय दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन की वजह से वातावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर गहरी चिंता है। एएफपी

शांति की कामना

उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती पाजू में स्थित असैन्य जोन (डीएमजेड) में बने पार्क में शांति की कामना के लिए शांति रिबन बांधती महिला। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण की धमकी देने और मिसाइल टेस्ट की वजह से क्षेत्रीय शांति को खतरा बना रहता है। लोग अक्सर यहां आकर शांति की कामना करते हैं। एएफपी

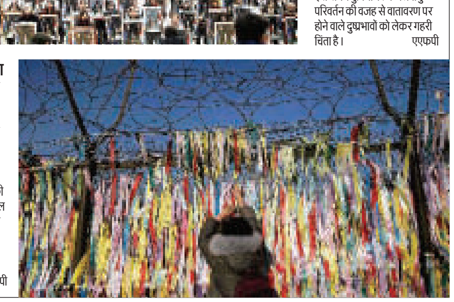

स्क्रीन शॉट

टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूं : विनीत कुमार सिंह

सात सवाल

फिल्म 'मुक्काबाज' के बाद से विनीत कुमार सिंह खासे व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म 'सांड की आंख' तथा वेब शो 'बार्ड ऑफ ब्लड' के बाद उनकी 'आधार' समेत कई फिल्में आएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वह सक्रिय हैं। उनसे बातचीत :

'मुक्काबाज' के बाद जिंदगी कितनी बदली?

-बहुत ज्यादा। मुझे वैरायटी किरदार ऑफर हो रहे हैं। लगातार शूट कर रहा हूं। इसके बाद मैंने 'सांड की आंख', 'बार्ड ऑफ ब्लड,' 'आधार', 'गुंजन सक्सेना', नेटफिलक्स के लिए वेब शो 'बेताल' शूट किया। फिलहाल साउथ की रीमेक फिल्म शूट कर रहा हूं। यह मेरी जिंदगी का बेहतरीन दौर चल रहा है।

'सांड की आंख' सच्ची घटना से प्रेरित थी। फिल्में सिखाने में कितनी मददगार होती हैं?

- मेरा मानना है कि सिनेमा का प्रभाव समाज पर काफी होता है। आपको सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 'सांड की आंख' भी सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।

फिल्मों में आप एक तरफ केंद्रीय भूमिका वाले किरदार निभा रहे हैं तो दूसरी तरफ पैरेलल रोल...

- पैरेलल किरदार की वजह से मुख्य किरदार आसानी से मिल जाते हैं। लोगों को रेफरेंस मिल जाता है कि मैंने वैसा काम किया है। 'मुक्काबाज' के लिए लोग मेरे बारे में बतौर बॉक्सर नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नहीं था। तब समझ में आया कि रेफरेंस बेहतर रोल दिलाने में मदद करेगा। लिहाजा अगर कोई किरदार मैंने नहीं किया है तो उसे निभाता हूं। मेरी कोशिश केंद्रीय और पैरेलल किरदारों में संतुलन साधकर चलने की है।

टीवी से दूर हैं पर वेब शो कर रहे हैं... ?

- 'बार्ड ऑफ ब्लड' करने की वजह किरदार उम्दा होने के साथ यह भी थी मेरा काम 190 देशों में पहुंच रहा है। उसके अलावा शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस तले बने जॉम्बी हॉरर शो 'बेताल' की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

साउथ की सुपरहिट फिल्म 'थिरुट्टू पयाले 2' की रीमेक से कैसे जुड़ना हुआ?

- 'थिरुट्टू पयाले 2' का निर्देशन सूसी गणेशन ने किया था। वही रीमेक का भी निर्देशन कर रहे हैं। गणेशन को 'मुक्काबाज' में मेरा काम पसंद आया था। इस फिल्म में मेरे किरदार में काफी लेयर हैं।

लखनऊ में आपने उसकी शूटिंग की थी। वहां से कैसा कनेक्शन रहा है?

- लखनऊ से मेरा खास नाता है। वहां पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल खेलने गया था। उसी से मेरा राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले चार हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप लखनऊ में लगा था। कोच हमें सप्ताहांत में खाना खिलाने बाहर ले जाते थे।

इस साल क्या सीखने की कोशिश की?

- इस साल टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूं। पहले मेरे पास इतना काम नहीं था। अब बैक टू बैक काम कर रहा हूं, , लिहाजा टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा हूं।

स्मिता श्रीवास्तव

धौनी लाएंगे परमवीर चक्र विजेताओं की कहानी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धौनी की जिंदगी पर फिल्म 'धौनी : द अनटोल्ड स्टोरी' बन चुकी है। उसमें उनकी क्रिकेटर बनने से लेकर वर्ल्ड कप जीतने के सफर को दर्शाया गया था। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया, जब उन्हें करियर में सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा। यह दौर था, जब आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई सुपरकिंग्स पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया था। तब धौनी और बाकी खिलाड़ियों को किस प्रकार की मुश्किलों से गुजरना पड़ा? उनकी मनःस्थिति क्या थी? इन्हीं पहलुओं को इस साल

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हॉट स्टार स्पेशल पर रिलीज डॉक्यूड्रामा शो 'रोर ऑफ द लॉयन' में दिखाया गया था। उसमें धौनी और बाकी खिलाड़ियों ने अपनी आपबीती साझा की थी। अब महेंद्र सिंह धौनी बतौर प्रोड्यूसर काम करने की तैयारी में हैं। खबरों के मुताबिक, वह अपनी कंपनी धौनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तले एक फाइनाइट शो लाने की तैयारी में हैं। इस शो को वह सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो नेक्स्ट के साथ मिलकर बनाएंगे। स्टूडियो नेक्स्ट ही इस बार 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 11 का सहनिर्माता था। बताया जाता है कि धौनी का शो परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की कहानी से प्रेरित होगा। शो का प्रसारण अगले साल किया जाएगा।

डिजिटल में सेंसरशिप को ठीक नहीं मानते विवेक

अभिनेता विवेक ओबेरॉय वेब सीरीज 'इनसाइड एज' के दूसरे सीजन में नजर आएंगे। उनका कहना है कि सेंसरशिप अब पुराने जमाने की बात हो गई है। दर्शकों को उनकी पसंद की फिल्में ओर शो देखने की आजादी मिलनी चाहिए। विवेक कहते हैं, 'मेरा मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह रेटिंग का नया सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कुछ आपत्तिजनक शो को लोग रेटिंग दे सकें। अगर आप 18 साल के हैं और सरकार चुनते हैं, तो अपनी पसंद के शो भी देख सकते हैं।' 'इनसाइड एज' के दूसरे सीजन में विवेक के अलावा अंगद बेदी, सिद्धांत चतुर्वेदी, शायोनी गुप्ता व सपना पब्बी जैसे कलाकार नजर आएंगे। विवेक कहते हैं कि शो को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है, जिसका श्रेय लेखक, निर्देशक व निर्माताओं को जाना चाहिए।

अध्ययन

जले हुए जंगलों को अपना ठिकाना बनाते हैं चमगादड़

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा– खुले स्थानों पर इन्हें पराध्वनिक तरंगों के जरिये स्थिति निर्धारण करने में होती है आसानी

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : घने जंगलों की अपेक्षा चमगादड़ खुले और आग से जले हुए जंगलों को अपना ठिकाना बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। 17 स्तनपायी पक्षियों पर किए गए एक सर्वेक्षण में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चमगादड़ खुद को आसानी से जंगलों में लगी आग के अनुकूल बना लेते हैं।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (यूसी) डेविस के शोधकर्ताओं ने कहा, 'जंगलों में रहने वाले कई चमगादड़ हालांकि घने क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और इनकी कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो खुले क्षेत्रों को अपना आवास बनाती हैं। सर्वे के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि दोनों की प्रजातियों के चमगादड़ घने जंगलों की अपेक्षा आग से जल चुके जंगलों को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इन स्थानों पर उन्हें पराध्वनिक तरंगों के जरिये स्थिति निर्धारण करने में आसानी होती है और अपना भोजन भी वह बिना किसी समस्या के खोज लेते हैं, जबकि घने जंगलों में चमगादड़ों को अपनी राह में आने वाली कई चुनौतियों को पार करना होता है।

जंगलों में लगी आग चमगादड़ों के आवासों को कैसे प्रभावित कर रही है। यह पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने माइक्रोफोन के साथ एक ध्वनिक सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया, जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालने

प्रतीकात्मक

के साथ-साथ चमगादड़ों के संचार के तरीकों पर नजर रखती थी। इसके बाद शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर के जरिये रिकॉर्डिंग का विजुअलाइजेशन किया और चमगादड़ों की प्रजातियों की पहचान कर उनके रहन-सहन की विशेषताओं का पता लगाया। साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि हर प्रजाति के चमगादड़ के रहन-सहन का तरीका एक-दूसरे के काफी भिन्न था। 11 में से आठ प्रजातियां ऐसी थीं, जिन्होंने आग से जले हुए जगलों को अपना ठिकाना बनाया था। यूसी डेविस के पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता और इस अध्ययन के मुख्य लेखक जैक स्टील ने कहा, 'यह बात चौंकाने वाली है कि है चमगादड़ आग से जल चुके जंगलों में अपना आवास बनाना अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं।'

रडार प्रणाली के जरिये खोजते हैं भोजन

चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम 'टैरोपस मीडिएस' है। स्तनधारी होते हुए भी यह अन्य पक्षियों से तेज उड़ सकता है। ये फलाहारी और कीटभक्षी दोनों तरह के होते हैं। चमगादड़ के शरीर की त्वचा पैराशूट जैसी होती, जिसकी मदद से ये लंबी उड़ान आसानी से भर लेते हैं। चमगादड़ों की अपनी एक रडार प्रणाली होती है जिसकी मदद से ये अंधेरे में अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। रात में उड़ते समय चमगादड़ अपने मुंह से उच्च आवृत्ति की पराध्वनिक तरंगें पैदा करता है, जो सामने किसी ठोस वस्तु से परावर्तित होकर तत्काल चमगादड़ के मस्तिष्क को संदेश प्रेषित करती हैं, फलस्वरूप चमगादड़ अपनी दिशा बदल देता है। इसी वजह से रात के अंधेरे में चमगादड़ किसी पेड़, पहाड़ या मकान से टकराए बगैर अपने शिकार की तलाश कर लेता है।